

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च 2008

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूचि

बुधवार, 12 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
हिन्दू गर्ल्ज कालेज, जगाधरी के विद्यार्थियों का स्वागत	(4)3
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4)3
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(4)20
तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्र न एव उत्तर	(4)20
अनुपस्थिति की अनुमति	(4)27
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(4)28
सदन के निर्णय को रद्द करना	(4)28
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)32
वाक आउट	(4)64
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)66

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 12 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बरज, अब सवाल होंगे।

Steps taken to supply Canal Water upto Tail-end

***816. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Irrigation Minister be pleased to state the steps taken by the Government to supply water upto tail-end of the villagers of Rai Malikpur, Banyal and Daukhera of Narnaul constituency?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Village Rai Malikpur of Narnaul constituency falls at the tail-end of Budhwal Sub Minor which off-takes from Dhantal Minor of Nolpur Diktributary System. The work of internal clearance of Nolpur Distributory, Dhantal Minor and Budhwal Sub Minor is in progress and is likely to be completed by 31-05-2008. Availability of water in the J.L.N. system has been increased and pumps on this system are also being rehabilitated to increase pumping capacity. With these steps, the canal water supply position upto the tail, end of village Rai Malikpur will improve.

The area of villagers Daukhera and Banyal of Narnaul Constituency is hilly and has not been covered under the command of Mahendergarh Canal System of J.L.N. Lift Irrigation Project.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नौलपुर डिस्ट्रीब्यूट्री अटेली डिस्ट्रीब्यूट्री के 4७694 किलोमीटर से निकलती है यह तकरीबन 41 किलोमीटर लम्बी है। हमारे पास पानी की कमी है और यह कमी इसलिए है क्योंकि बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक कैनाल अभी तक नहीं बन पाई है। इसके बनने पर ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। पानी नौलपुर डिस्ट्रीब्यूट्री में 28 किलोमीटर तक चल रहा है। पहले मात्र मंगोल तक पानी जाया करता था लेकिन अब हमने चक मलिकपुर तक पानी पहुंचवाया है। रैस्टोरे इन और रिहेबीलिते इन के काम भी चले रहे हैं। 21 पम्पस इनके हल्के के हमने ठीक करवाए हैं और 23 पम्पस ऐसे हैं जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। 25.250 किलोमीटर पर जो एम०एल०डी० 8 है वहां पर बामड़वास गांव है वह गांव आखिर में पड़ता है लेकिन है आसपास, वहां का पम्प हाउस भी काम नहीं कर रहा है। आगे जाकर जैन माइनर जहां से निकलती है वहां पर भी पम्प हाउस काम नहीं कर रहा है। जितनी डिस्ट्रीब्यूट्रीज आगे बनाई हैं खासतौर से धनताल माइनर वगैरह, इनमें प्रोब्लम यह आ रही है कि ये हिली एरिया हैं इसलिए इतना कुछ करने के बाद भी मुझे बहुत कम उम्मीद है कि पानी की जितनी एवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक पानी वहां तक पहुंच पाएगा। पम्प हाउसिज की सफाई भी

हम करवा रहे हैं और पम्प हाउसिज को हम ओपरेट भी कर देंगे। लेकिन जब तक बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक नहर नहीं बनती है और जब तक पानी की एवलेबिलिटी ज्यादा नहीं बन पाती तब तक वहां तक पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी हमारे विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि वहां पर पानी पहुंचे। टेल पर पानी न पहुंचने का दूसरा कारण यह भी है कि हैड्रेज पर पानी की काफी चोरियां होती हैं। उन चोरियों को रोकने के लिए हमारी तरफ से पेट्रोलिंग भी की जाती है। मैं विशेष तौर पर पूरे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बगैर आउटलैट के लोग पम्पस लगाकर जहां पर भी पानी की चोरियां करते हैं उनको वे ऐन्क्रेज न करें क्योंकि पानी की चोरी होने के कारण ही टेल पर पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं मेरे माननीय साथी भार्मा जी को बताना चाहूंगा कि जिन गांवों का वे जिक्र कर रहे हैं वहां तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री राधे याम भार्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन्होंने नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, धनताल मार्डनर और बुधवाल सब-मार्डनर की आन्तरिक सफाई की बात की है। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मैंने दौखेड़ा और बनयाल गांवों के बारे में प्रश्न किया है ये गांव सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से कवर हो सकते हैं, नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से कवर नहीं हो सकते क्योंकि नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और उन गांवों के

बीच में कृष्णावती नदी पड़ती है इसलिए नदी के बीच में ये कैसे नहर बनायेंगे? इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन चार गांवों और उनके आस-पास 10-11 ढाणियों में नहरी पानी कैसे पहुंचाया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने अपने प्र न में सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का कोई जिक्र नहीं किया जबकि अब ये कह रहे हैं कि उन गांवों को सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ा जा सकता है।

श्री राधे याम भार्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दौखेड़ा और बनयाल आदि गांवों में नहरी पानी की व्यवस्था करने के बारे में प्र न पूछ रहा हूं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरी से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मंत्री जी केवल यह बता दें कि दौखेड़ा और बनयाल आदि गांवों में पीने के लिए ये नहरी पानी किस तरह से पहुंचायेगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने राय मिलकपुर, दौखेड़ा और बनयाल गांवों के बारे में प्र न पूछा है। ये गांव सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से काफी दूरी पर हैं। ये गांव नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर पड़ते हैं।

श्री राधे याम भार्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और इन गांवों के

बीच में कृष्णावती नदी पड़ती है। वहां से ये किस तरह से पानी इन गांवों में पहुंचायेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसको हम इग्जामिन करवा लेते हैं। यदि नदी हो पार करके पानी पहुंच सकता है तो नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी पहुंचाया जायेगा और यदि कोई दूसरा हल निकलेगा तो वह निकालेंगे। अगर इसमें कोई फिजीबिलटी होगी तो हम जरूर पानी पहुंचायेंगे। वैसे ही बेकार में हम रजबाहे बनाते रहें और सरकार का पैसा वेस्ट करते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है।

हिंदू गर्ल्स कालेज, जगाधरी के छात्र-छात्राओं का स्वागत

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अगला प्र न पूछा जाये उससे पहले मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिंदू गर्ल्स कालेज, जगाधरी के बी०ए०-III क्लासिज के 52 छात्र-छात्राएं और उनके चार अध्यापक इस समय द कि दीर्घा में मौजूद हैं। मैं इन सबका पूरे सदन की तरफ से स्वागत करता हूं। ये छात्र-छात्राएं हमारी अगली पीढ़ी हैं। मुझे आ ता है कि वे आज इस सदन की कार्यवाही से एक नई प्रेरणा लेकर जायेंगे।

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To reclaim the Water Logging Land in the villages of District Bhiwani

***827, Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Irrigation Minister be pleased to state –

(a) whether any scheme has been formulated by the State Government to reclaim the water logging land of Chang, Mitathal, Gujrani, Sai, Kaluwas, Nathuwas, Ghuskani, Tigrana, Badesara, Jatai, Dhanana and Madhana villages of District Bhiwani ;

(b). If so, the status of the said scheme togetherwith the steps taken in this regard alongwith the time by which the farmers will get relief therefrom; and

(c). whether the State Government has discussed with the Central Ground Water Board in this regard?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a). Yes, Sir. A scheme namely constructing Mithathal – Ghuskani Link drain to reclaim water logging land in Distt. Bhiwani has been formulated.

(b). The scheme has been approved and is likely to be completed by 30.06.2009.

(c). This scheme does not require approval of Central Ground Water Board.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि क्या जिला भिवानी के चांग, मिताथल, गुजरानी, साई, कालुवास, नाथुवास, घुकानी, तिगड़ाना, बढेसरा, जताई, धनाना तथा मधाना गांवों की सेमग्रस्त भूमि का सुधार करने के

लिए सरकार कोई योजना बना रही है या नहीं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जिस स्कीम का जिक्र किया है उस स्कीम में ये गांव नहीं आते। इन गांवों के लिए क्या कोई दूसरी स्कीम सरकार बना रही है ताकि वहां के गांवों की सेम की समस्या दूर हो सके?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी चांग गांव की बात कर रहे हैं it is served by Chang Drain No. 2 और वहां के पानी को लिफ्ट करके भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में आर०डी. 155000 में डाला जाएगा, जिसका काम पूरा हो चुका है। दूसरा साईं गांव है, जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर ड्रेनेज की कोई प्रोब्लम नहीं है। कभी-कभी बरसात के दिनों में थोड़ा पानी जुड़ जाता है। उस पानी को पम्पस से लिफ्ट करके आर०डी० 132 से 138 में डाल दिया जाता है। जो सुई है वह भिवानी-घग्गर ड्रेन सर्व करती है और उस पर काम चल रहा है। रेवाड़ी खेड़ा के बारे में उन्होंने कल भी जिक्र किया था इसके बारे में मुझे बताया गया है कि वहां पर ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कालूवास में मिथाथल ड्रेन नम्बर 3 से पानी ड्रेन आऊट होगा जिसका काम कम्प्लीट हो गया है। गुजरानी ड्रेन का काम भी कम्प्लीट हो गया है। मिथाथल ड्रेन नम्बर 2 का काम भी कम्प्लीट हो गया है। मिथाथल-घुसकानी ड्रेन से पानी ड्रेन होने का काम अण्डर प्रोग्रैस है। तिगड़ाना से मिथाथल घुसकानी ड्रेन से पानी निकाला जायेगा यह काम भी कम्प्लीट हो गया है। प्रेम नगर ड्रेन से पानी निकालने का काम अण्डर प्रोग्रैस है। मुंढाल-तालु लिंक

ड्रेन का काम भी कम्पलीट हो गया है। लोहारू-जाटू जो कि मुंडाल तालू लिंक ड्रेन द्वारा निकाला जायेगा वह काम भी कम्पलीट हो गया है। मुंडाल कलां ड्रेन से उसका पानी निकाला जायेगा वह काम भी कम्पलीट हो गया है। इसी प्रकार से मुंडाल खुर्द का काम भी कम्पलीट हो गया है इसे बास ड्रेन से और बौहनी थाका ड्रेन से हम ड्रेन करेंगे। एक गांव है सुखपुरा जो कि मुंडाल सुखपुरा लिंक ड्रेन से निकाला जाएगा जिसका काम अण्डर प्रोग्रेस है और जतोई ड्रेन का काम भी कम्पलीट हो गया है। बड़ेसरा ड्रेन नम्बर 1 और 2 से निकाला जाएगा और इसका काम भी कम्पलीट हो गया है। मिरान ड्रेन का काम अण्डर प्रोग्रेस है और सगनाम जो भिवानी-घग्गर ड्रेन से निकाला जाएगा यह काम भी कम्पलीट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम है यह इसी सरकार के दौरान हमने भुरू की थी और इसमें जहां तक मैं समझता हूं यह काम 30 जून, 2008 तक पूरा कर दिया जाएगा। पहले यह हमने केवल आर०डी० 0 से 50100 तक पर ही कार्य किया था और अब इसको हम आर०डी० 50100 से लेकर 70630 तक पूरा करेंगे। यह स्कीम 29 जनवरी, 2008 को अप्रूव हुई है और 30 जून, 2008 तक हम इसको पूरा कर देंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा जो सदन के सामने इन्होंने मुंडाल की ड्रेन के बारे बताया है इसके बारे में जो-जो इनफॉर्मेशन इनको दी गई है उसकी ये दोबारा फिर से

जांच करवा लें क्योंकि जो मुंडाल-सुखपुरा ड्रेन है उसका तो सैव 1 न नम्बर 4 का नोटिस भी नहीं हुआ है और उसके बारे में पेपर में भी कुछ नहीं आया है इसलिए उसके कम्पलीट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता; अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मधाना और धनाना गांवों के लिए कोई स्कीम नहीं है और न ही अब तक कोई स्कीम तैयार की गई है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसको भी दोबारा एग्जामिन करवा लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुंडाल ड्रेन का सम्बन्ध है तो उसका काम कम्पलीट हो गया है और सुखपुरा ड्रेन का काम अण्डर प्रोग्रैस है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें कई जगह अवार्ड होना बाकी है जिसके लिए हमने पैसा जमा करवा दिया है। सैव 1-9 भी हो गया है और यह काम अण्डर प्रोग्रैस है और जैसे ही अवार्ड होगा हम इसका काम भुरु कर देंगे। लेकिन जब तक अवार्ड नहीं होगा तब तक काम भुरु नहीं हो सकता। अवार्ड करने का काम डा०आर०ओ० का है और डी०आर०ओ० लगाने के लिए मैंने कल भी रेवेन्यू मिनिस्टर से रिकवैस्ट की थीं इसके अतिरिक्त आपने दो और गांवों के बारे में जिक्र किया है यह काम अभी तक नहीं हुआ और मुंडाल लिंक ड्रेन से उसका वर्क कम्पलीट हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई सं 1य हैं तो इस बारे में मैं अपने अधिकारियों से बात कर लूंगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई

सुझाव भी देना चाहते हैं तो उन्हें हमारे पास भिजवा दें, हमारे अधिकारी उन पर भी आवश्यक कार्यवाही कर लेंगे।

श्री रामकिान फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये जो ड्रेन निकाली जा रही है मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे भिवानी में गंदे पानी का नाला जो हमारे तो गाम, बवानी खेड़ा, आलमपुरा, बालावास, कंवारी, धमाना, धमाकुंजा और कुंगड़ के पास से निकलता है उसके पास किसानों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। सरकार जो जमीन ड्रेन के लिए एक्वायर करती है वह कम करती है जिसके कारण किसानों को रास्ते कम मिलते हैं। जो पुल बनाए जाते हैं बरसात के दिनों में उनकी मिट्टी कट कर वह रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है जिसके कारण किसानों को रास्ता नहीं मिलता। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इन पुलों और दूसरे रास्तों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्रेन के ऊपर रास्ते की बात है तो हमारे नार्मस के मुताबिक जो रास्ते हैं जो गांवों से गांवों को जो जोड़ते हैं उनके ऊपर तो हम पुल बनवाते हैं। जहां रास्ते हमारे नार्मस में कवर नहीं होते और कोई जरूरी रास्ता है तो वह केस माननीय मुख्य मंत्री जी तक जाता है अगर मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल मिल जाती है तो हम उसको बना देते हैं। माननीय सदस्य के इलाके में ऐसे कई एरिया हैं, जहां पर

वास्तव में पुलों की जरूरत है। ऐसे पुलों को हम अव य बनायेंगे।

Vigilance Enquiry

@832. Shri Shamsheer Singh Surjewala : Will the Chief Minister be pleased to state whether any criminal case/enquiry is pending against Shri Om Parkash Chautala and his associates before the Haryana Vigilance Bureau; if so, the details thereof?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

One criminal case FIR No. 20 dated 18.10.2005 under Sections 420/467/468/471/120B IPC & 13 of P.C. Act has been registered at Police Station State Vigilance Bureau, Hisar against Sh. Om Parkash Chautala, ex-Chief Minister, Shri K.C. Bangar and others arising from Enquiry No. 3/2005 Chandigarh regarding alleged irregularities in the selection of H.C.S. and Allied Services and other posts. Haryana Public Service Commission has refused to handover most of the relevant record to the State Vigilance Bureau. In order to obtain record, State Vigilance Bureau filed an application in the Court of Chief Judicial Magistrate, Hisar for obtaining search warrants but the request was rejected. Thereafter, State Vigilance Bureau went in revision before the Sessions Judge, Hisar which was also dismissed. Thereafter, the State

Vigilance Bureau filed a Criminal Misc. Petition under Section 482 Cr.P.C. in the Hon'ble Punjab & Haryana High Court challenging the orders of the Chief Judicial Magistrate, Hisar and Sessions Judge, Hisar. The petition is being heard by Hon'ble Punjab & Haryana High Court. In view of the non-supply of the relevant records by the Haryana Public Service Commission, further investigation by State Vigilance Bureau is held up.

In addition, Enquiry No. 10/2005-Chandigarh against Sh. Om Parkash Chautala ex-Chief Minister and the then Director, Animal Husbandary, Haryana regarding alleged misappropriation of grants under various centrally sponsored programmes in the Animal Husbandary Department and purchases made thereunder, is also pending.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने श्री भाम ार सिंह सुरजेवाला जी के प्र न के जवाब में जो वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है उससे यह प्रमाणित होता है कि श्री ओमप्रका ा और उनके साथियों के विरुद्ध जो मुकद्दमें दर्ज किए हैं वह इसलिए किए गए क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान में बंगलिंग उन दिनों की गई। जो नियुक्तियां की गई उनके बारे में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में जिक्र किया है कि “alleged irregularities in the selection of HCS and Allied Services.” सर, इनके भासन के दौरान 3 बार एच०सी०एस० और एलाइड सर्विसिज में सलैव ान हुआ है। यह कौन से साल का

एडवरटाईजमेंट था और ये जो वैकेन्सीज हैं ये कौन से साल की थी जिनके अंग्रेस्ट या जिस रिक्कायत पर इन्होंने मुकद्दमा दर्ज किया है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने वक्तव्य में जो यह कहा है कि निदेशक, पं. उपालन हरियाणा और श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ पं. उपालन विभाग में की गई अनियमितताओं व गबन के बारे में भी इन्क्वायरी है तो यह इन्क्वायरी क्या है और क्या इसकी तफती पूरी हो चुकी है और अगर इसकी तफती पूरी हो चुकी है तो इसमें भी क्या विजिलेंस विभाग या पुलिस विभाग मुकद्दमा दर्ज करेगा? जो इसमें गबन किया गया है उसकी मात्रा क्या है वह गबन कितने रुपये का है या उस गबन की संख्या क्या है? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे।

डॉ० सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो श्री भामदेव सिंह सुरजेवाला जी के नाम था तो फिर श्री कर्ण सिंह दलाल कैसे पुट अप कर रहे हैं?

Mr. Speaker : Hon'ble members, Shri Shamsher Singh Surjewala has authorized Shri Karan Singh Dalal to ask the question, under Rule 52(3) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly. Under Rule 52(3), any member can authorize any other member of the House to go put the question on his behalf, if the Speaker allows. The written request of Shri Shamsher Singh Surjewala is here and I have allowed Shri Karan Singh Dalal to ask the question.

डॉ० सु गील इन्दौरा : ठीक है सर, मैं यही जानना चाहता था। अगर रिटन में परमिशन है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से हमने स्टेटमेंट हाउस के पटल पर रखी है। माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा इसमें हमने इन्क्वायरी नं० 3 ऑफ 2005 की चर्चा की है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि ये कौन-कौन से वर्ग की सिलैबन थी। अध्यक्ष महोदय, इस केस के बारे में हमें कुल 37 रिक्वायर्मेंटें मिली हैं जो कि हरियाणा के भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हुई हैं। ये रिक्वायर्मेंटें उन लोगों ने भी की हैं जो खुद इस पद के सिलैबन के लिए उम्मीदवार थे। इन रिक्वायर्मेंटों में आरोप लगाया गया है कि इन सिलैबन के लिए उस समय के आयोग के सदस्यों द्वारा अथवा उस वक्त की सरकार के मुखिया द्वारा पैसा लिया गया है। भिन्न-भिन्न रिक्वायर्मेंटें हमारे पास लम्बित हैं जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी लिस्ट बड़ी लम्बी है इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी को इसकी कॉपी भिजवा दूंगा। इन रिक्वायर्मेंटों पर जांच चल रही है। यह अकेली एच०सी०एस० की सिलैबन की रिक्वायर्मेंट नहीं है इसके साथ ही बहुत सारी एलॉयड सर्विसिज के साथ रिलेटिड रिक्वायर्मेंटें भी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि फोरैस्ट सर्विसिज ग्रुप "बी" कैटेगरी के अन्दर भारीरिक परीक्षा में भारी

हेरा-फेरी हुई है इसकी जांच विजिलेंस के पास है। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार, एच०सी०एस०, नॉमिनेटिड कैटेगरी में लगाए हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एस०डी०ओ०, इलेक्ट्रिक के पद के लिए गोल्ड मैडलिस्ट कुमारी बिन्दले 1 daughter of श्री बिन्दले 1 को गोल्ड मैडलिस्ट हारने के बावजूद सिलैक्टान से छोड़ दिया गया जबकि सैकण्ड और थर्ड डिवीजन वाले कैंडीडेट्स को सिलैक्ट कर लिया गया। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। इसी तरह से सीनियर ऐनालिस्ट के पदों की भर्तियां जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की गई उसमें ऐसे कैंडीडेट की सिलैक्टान हो गई जो मिनिमम योग्यता भरी पूरी नहीं करता था, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आई है। डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर के बारे में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने बताया था कि सरकार कार्यवाही कर रही है। एक ऐसे व्यक्ति का सिलैक्टान कर लिया गया है जो अपनी आयु सीमा पार कर चुका है। इसी प्रकार की गई और खामियां उसके अन्दर पाई गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर सिलैक्टान में अनियमितताओं के बारे में एफ०आई०आर० दर्ज करवाने के बारे में आदेश माननीय कृषि मंत्री जी ने दे दिये हैं। वे तीनों अधिकारी जो नाजायज तरीके से सिलैक्ट हुए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर की नियुक्ति में भारी अनियमितताएं हुई हैं। इसी प्रकार से एच०सी०एस० और एलॉयड सर्विसिज की सिलैक्टान में भारी अनियमितताएं की गई। कायदे कानून को ताक पर रख कर सिलैक्टान में कानून की धज्जिया उड़ाई गई। जो रिपोर्टें

प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ केसिस हाई कोर्ट में चले हुए हैं। स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑफिसर की जो 17 लोगों की सिलैकान की गई है उसमें भी रिक्वायत प्राप्त हुई है। जो हमारे दलित भाई हैं उनमें से कइयों के साथ ज्यादाती की गई है। उनकी रिक्वायत भी हमारे पास आई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। कोई भी ऐसी सिलैकान नहीं बची है जिसमें हेरा-फेरी की रिक्वायत न की गई हो। जो रिक्वायतें आई हैं वे इस समय विजिलेंस के पास हैं और अण्डर इन्वैस्टिगेशन हैं। Regarding inquiry No. 10 of 2005 जिसमें यह इल्जाम है कि ऐनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट का पैसा श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा डेवियरैक्टर ने मिल कर खुद-बुर्द कर लिया है जिससे सरकारी को हानि पहुंची है। यह मामला अभी भी अण्डर विजिलेंस इन्वैस्टिगेशन है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि जून, 2008 तक इस इन्क्वायरी को पूरा करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि जो इल्जाम लगाया गया है कि इसमें कितने पैसे का गबन हुआ है। इस बारे में इस वक्त मेरे पास पूरे तथ्य उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो रिकॉर्ड मैंने देखा है उसके मुताबिक उसमें तकरीबन 130 लाख रुपये की राशि इन्वाल्ड है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में सदन को बताया है कि जो नियुक्तियां की गई हैं

उसमें किस प्रकार से अनियमितताएं की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब ये जान चुके हैं कि आयोन ने लोगों की भर्ती रिक्त, सिफारिश, जाति और धर्म के नाम पर की है और वे लोग विभिन्न विभिन्न महकमों में बैठकर प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके अन्दर यह काबलियत नहीं है कि वे उन महकमों के साथ इन्साफ कर सकें। क्या माननीय मंत्री सदन में आवासन देंगे कि जिन नियुक्तियों के बारे में ये मानते हैं कि ये नियुक्तियां अयोग्य होते हुए भी की गई हैं। इसके मायने उनको ये नौकरियां नहीं दी जानी थी लेकिन उनको यह नौकरियां दी गई थीं। उनको बजाए अन्दर रूल सात चार्ज फिट करने के क्या भागे-काज नोटिस देकर फौरन बर्खास्त करने के बारे में ये विचार करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसे कि मैंने बताया है कि डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर की इन्क्वायरी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। इस बारे में कल माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में बताया था कि हमने यह निर्णय लिया है कि इण्डियन पिनल कोड की धारा 420, 467 और 471 जिनमें फौजरी डाकूमेंट वगैरह के मामले आते हैं उनके तहत हमने मुकद्दमा दर्ज करवाने का निर्णय ले लिया है। जहां तक उनको नौकरी में लगाने और न रखने का सवाल है तो इस बारे में इनका जो सुझाव है कि ऐसे व्यक्तियों को भागे-काज नोटिस देना चाहिए, सरकार इस बारे में

एडवोकेट जनरल से ओपिनियन ले लेगी। उनकी ओपिनियन के मुताबिक ही हम कार्यवाही करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत अच्छी बात कही है। यह जो एम०पी०एस०सी० ने नियुक्तियों की सिफारिश की है इसमें साफ तौर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इसमें बहुत बड़ा धोखा प्रदेश की जनता के साथ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अयोग्य व्यक्ति अपने सरकार कामकाज का निपटारा अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। वह आदमी सारा दिन दफ्तरों में न बैठकर के जैसी उनकी फितरत है, जैसे उनके आचार-विचार हैं, वे लोगों के साथ धोखा-धड़ी करते रहे हैं वही काम करते रहते हैं जिन अधिकारियों ने एच०पी०एस०सी० में ये गलतियां की हैं उनके खिलाफ सरकार ने मुकद्दमें दर्ज किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं। आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को विभागों में नौकरियां दी हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि यह सिलैब इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की गई है और इस प्रकार की खामियां उस वक्त का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था जो आज भी है, हमने और

आरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह पाया कि इसमें भारी अनियमितताएं पूरी सिलैक इन के वक्त में की गई हैं। जो मैरिटोरियस कैंडिडेटस थे, जो काबिल उम्मीदवार थे उनको छोड़ दिया जाता था और नियुक्ति किसी अन्य आधार पर की जाती थी। ये सब बातें सोच कर राष्ट्रपति जी को हरियाणा सरकार ने एच०पी०एस०सी० की इम्पीचमेंट का रैफरेंस दिया है, जो कि विचाराधीन है। आज पब्लिक सर्विस कमी इन कोई सिलैक इन करके भेजेगा तो हम उस सिलैक इन को करने के लिए बाध्य हैं। परन्तु फिर भी अगर माननीय सदस्य को लगे कि इसके अन्दर किसी अधिकारी की अनियमितता में भागीदारी है तो ये उस स्पैसिफिक इन्सटांस के बारे में हमें लिखकर भेजें। मैं इनसे सरकार की तरफ से वायदा करता हूँ कि हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री तजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि भिन्न-भिन्न अनियमितताओं की बहुत सी कम्प्लेंट्स हैं। जब सरकार को इतना पता लग गया है कि सर्विस कमी इन ने बेहता ा धांधली की है तो ये सारी अनियमितताओं के बारे में एक ही इन्क्वायरी करें और इन्क्वायरी ऐसी न करें जैसे कि एक केस में 3 साल इन्क्वायरी करते हुए हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि ये इन्क्वायरी को टाईम बाऊंड करें।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, जिस पोस्ट के लिए गलत सिलैक इन हुई है जैसे कि 10 पोस्ट्स हैं और उनमें से 2 की

गलत सिलैव इन है। क्या आप उन दो पर इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं या 10 के खिलाफ ही इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं?

10.00 बजे

श्री तजेन्द्र पाल सिंह मान : नहीं सर, मैं तो कहता हूँ कि जोभी कारगुजारी उस वक्त के पब्लिक सर्विस कमी इन ने पांच-छः साल के समय में की, उसकी जांच करवानी चाहिए। उस वक्त इस कमी इन को भंग करके सभी सदस्यों के इस्तीफे दिलवाकर रिप्लेस करके दोबारा से मैम्बर बना दिया गया था लेकिन इसके बाद उनका चरित्र हाई कोर्ट में और विभिन्न नियुक्तियों में सामने आ गया था लेकिन इसके बाद उनका चरित्र हाई कोर्ट में ओर विभिन्न नियुक्तियों में सामने आ गया था। क्या सरकार ऐसा सोच रही है कि उस समय टोटल जितनी भी नियुक्तियां की गयी हैं चाहे वह पोल्यू इन बोर्ड में नियुक्ति की गयी हों जिसमें जे०ईज० से सीधे ही ऐक्सियन बना दिया गया, उनकी इन्क्वायरी का कोई समय निर्धारित है? स्पीकर सर, अब तक तीन साल हो गये हैं इसलिए उनका समय निर्धारित किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, मेरा दूसरा सवाल हालांकि इस प्र न से रैलेवैन्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हलके के उस वक्त के विधायक के गांव में जो नम्बर ऑफ मर्डर्ज हुए थे उनके करने वाले आज तक अनट्रेस हैं। उन लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी भी पूरी नहीं हुई है इससे ऐसा

लगता है कि इस मामले में कहीं न कहीं मिलीभगत तो जरूर है। क्या मंत्री जी इस मामले की भी इन्क्वायरी करवाएंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है उससे मैं भी अपने आपको जोड़ता हूँ। मैं। इनसे केवल यह कहना चाहूंगा कि हमने जो एक स्टेटमेंट टेबल ऑफ दी हाउस में रखी है उसको ये पढ़ें क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो इन्क्वायरी नम्बर 382005 है वह regarding alleged irregularities in the selection of H.C.S. and allied services and other posts के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकार्ड मांगा था ताकि जो बात सच है वह सामने आ जाए और अगर कमेंट झूठी है तो वह भी सामने आ जाए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह रिकार्ड देने से इंकार कर दिया, वह रिकार्ड दिखाने से इसलिए इंकार कर दिया ताकि तफ्तीशी अफसर इन्क्वायरी करके सच का सच और झूठ का झूठ सामने न ला सके। स्पीकर सर, अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर विजिलेंस ब्यूरो गया है और वहां पर इस समय यह प्रक्रिया प्रोग्रेस में है। इस मामले में माननीय हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक हम फर्दर कार्यवाही करेंगे। इनकी यह बात सही है कि इस मामले में तीन साल का समय बीत गया है। अध्यक्ष महोदय, हम यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस इन्क्वायरी का निपटारा कर सकें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हालांकि इनका वह प्र न मेन सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु इस मामले में जो रिक्वायत पार्टी है यदि उनकी तरफ से लिखवाकर भिजवा दें तो मैं मान साहब को ऐ योरेंस देता हूं कि इस मामले में भी कार्यवाही की जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक दरखास्त ये रिक्वायत पार्टी से लिखवाकर मुझे दिलवा दें, हम 6 महीने के अंदर इन्क्वायरी पूरी करके क्रिमिनल इन्वैस्टीगेशन डिपार्टमेंट कर देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, श्री भामदेव सिंह सुरजेवाला जी ने अपने सवाल में श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके एसोसिएट्स के राजकाज में हरियाणा के अंदर जो खुली लूट और खसौट के काम हुए हैं, उनके बारे में पूछा है। उस समय कईसे वाकये हुए थे जिनकी अब पुलिस, विजिलेंस और सी०बी०आई० जैसी संस्थाएं जांच कर रही हैं और मुकद्दमें दर्ज हो रहे हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी फैसले आए हैं। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सिरसा में बिजली विभाग की जमीन पर कब्जा हुआ है।

Mr. Speaker : Dalal Sahib, please ask your supplementary only pertaining to this question. In this regard, you can ask separate question.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, चूंकि यह भी ओम प्रका 1 चौटाला एंड एसोसिएटस का मामला है इसलिए मैं पूछना चाहता था लेकिन अगर आप मुझे इस बारे में पूछने के लिए एलाऊ नहीं करते हैं तो मैं अपना दूसरा प्र न पूछ लेता हूँ। इनके समय में जो एच०सी०एस० गलत तरीके से नोमीनेट हुए हैं उनमें एक प्रताप सिंह का एच०सी०एस० भी है। पहले यह हुडा विभाग में कार्यरत था लेकिन इसको स्टैनो होते हुए भी सीधे ही एच०सी०एस० बनाया गया। इनके खिलाफ रिट कायते पिछले और अब के भासन के सामने आयी है तो क्या मंत्री जी इस बात का वि वास दिलाएंगे कि जो एच सी एस पिछली सरकार ने नोमीनेट किए और बोर्ड एवं कारपोरे िंज के नियामो को बदलकर या न बदलाव भी नोमीनेट किया, क्या मंत्री जी उन अन्य एच सी एस को जिनको हटाने का सरकार ने नोटिस दिया है, उनके साथ उस प्रताप सिंह को जिनको स्टैनो से एच सी एस बनाया था, उसका भी चयन उसी लिस्ट मे हुआ था, क्या इसको हटाने के बारे मे माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जिस व्यक्ति वि ेश को लेकर प्र न पूछा है तो इस बारे मे पूरे तथ्य इस समय मेरे पास हैंड इन नहीं है लेकिन जो भी उचित कार्यवाही होगी वह हम अव य करेंगे ऐसा मै माननीय

सदस्य को आवास देना चाहता हूँ। अगर किसी की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है तो ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार उस पर नियमों के मुताबिक उचित कार्यवाई अवश्य करेगी।

श्री फूल चंद मुलाना: स्पीकर सर, क्या मंत्री महोदय यह विचार भी कर रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन कीमिनल की हैल्प कर रहा है उसके मायने ये हुए कि वह भी उसमें इन्वोल्व है, उसकी मंशा क्या है? They are concealing the record in order to help the criminals. क्या ऐसे कमीशन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या किमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने का सरकार विचार रखती है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक मुलाना जी हैं। उनकी चिंता वाजिब है कि जब हाईएस्ट सलैक इन बाडी इस प्रकार के नैपुटिज्म और इररैगुलैरिटीज में इन्वोल्व हो जाए तो फिर प्रांत की 2 करोड़ 30 लाख जनता का विवास अपने आप सलैक इन प्रोसेस के बारे में संदेह के घेरे में आ जाता है।

Mr Speaker: No running comments. ओढ़ साहब, आपको बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मौजूदा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन और उसकी

प्रक्रिया दोनो भारी संदेह के घेरे में है। उनकी निष्पक्षता, उनकी काबिलियत and their capacity to make fair and independent selection is in serious doubts. इसके लिए संविधान के अंदर जो प्रक्रिया है उसमे इम्पीचमेंट का प्रावधान है, मुख्यमंत्री जी ने सारी बात को देखकर इसका बडा कडा नोटिस लिया और हमने पब्लिक सर्विस कमी न को हटाने के लिए एक रिफरेंस राष्ट्रपति जी को दे दिया है। दूसरा प्र न माननीय मुलाना साहब ने किया है कि क्या इंडिपेंडेंट आफ इम्पीचमेंट और नो कांफीडेंस मो न के अलावा आपराधिक मुकद्दमा ऐसे पब्लिक सर्विस कमी न के सदस्यो और उनको मुखिया के खिलाफ दर्ज करेंगे। मै उनका आ वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले में इंकवायरी जारी है। माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल ने जो पब्लिक इंट्रैस्ट लिटिगे न इस मामले मे डाली थी, वह मामला भी उच्च न्यायालय मे अंदर विचाराधीन है। दोनो की फाइंडिंग्स आते ही जो भी दोशी पाया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ आपराधिक मुकद्दमा अव य दर्ज किया जाएगा।

Promoting the Livestock

***852. Sh. Randhir Singh:** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state the steps taken by the Government for promoting the livestock in the state and whether the farmers are being encouraged for promoting livestock; if so, the details thereof?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha): Sir, the Government is undertaking various programmes in the State to promote the livestock and encourage the farmers. In brief the details are placed on the Table of the House.

Annexure-I

The Department is taking up following activities to improve the livestock and encourage the farmers in the State:-

1. The State of Haryana is credited with having the best infrastructure in the country. A total of 2605 Veterinary Institutions catering to the needs of livestock owners. On an average one Veterinary Institution per less than three villages.

2. The Haryana Livestock Development Board has been constituted with a view to boost up the genetic improvement of livestock in the State. It is the State implementing Agency of National Project for Cattle and Buffalo Breeding (100% Centrally Sponsored Scheme). The different breeding activities, starting from quality frozen semen production to doorstep A.I. services are carried out under this programme.

3. To preserve, improve and fast multiply quality Murrah germplasm, a noble programme of identifying top yielding Murrah buffaloes and giving incentive to the owners of such recorded animals has already started showing encouraging results. Under this programme, cash incentive to the owners of buffaloes yielding 11&15 Kg. of milk per day are given Rs. 3000/- whereas the owners of the buffaloes yielding above 15 to 20 Kg. are given Rs. 6000 and 10000, respectively. All the identified buffaloes are insured and 100% insurance

premium in the case of Scheduled Castes and 75% in the case of general farmers is borne by the Government. Male calves born to these high yielding buffaloes are purchased by the Government and reared as future bulls for supply to the Gram Panchayat at subsidized rates. The topmost bulls categorized on the basis of dam yield are being maintained at the high-tech sperm stations (Semen banks) for production of semen.

4. There has been export of Murrah bulls and semen to institutions of national and international repute like National Dairy Development Board, Bhartiya Agro Industries Foundation in addition to several states of the country including Punjab, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Uttaranchal, Gujrat, Chhatisgarh and Delhi.

5. The State is taking all necessary steps to keep its livestock healthy. the implementation of Foot & Mouth disease control programme is a success story. Its including during the last three years has been as good as zero.

6. We are the first State to provide an insurance cover to "Haryana cows and bullocks and 50% of the insurance premium in the case of general category farmers and 100% in the case of Scheduled Castes farmers is borne by the Government in such cases.

7. To promote cattle production and conservation, registered Gaushalas numbering 157 in the State are assisted from time to time through various State & Central agencies.

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है वह बहुत सराहनीय है। मैं उनका ओर

मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले सै। न के दौरान मैंने कुछ सुझाव दिये थे उन सुझावों को सरकार ने लागू किया है और इन सुझावों पर हरियाणा प्रदेश के हजारों किसानों को फायदा भी हुआ है। इससे हरियाणा प्रदेश के किसान जो पशुपालक हैं उनका हौंसला बढ़ा है, रुची बढ़ी है इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह भी सुझाव देना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंट्र पूछिए।

श्री रणधीर सिंह: ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पशुपालकों के पशुओं के लिए जो बीमा राशि योजना रखी गई है वह भैंसों के लिए और गायों के लिए 30 हजार रुपये रखी गई है जबकि आज के दिन जो मुराह भैंस की वैल्यू है।

श्री अध्यक्ष: आप यह पूछो की इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बीमा राशि को भैंसों के लिए 50 हजार या 60 हजार तक बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और जो गायों के लिए बीमा राशि रखी गई है क्या उसको 20 हजार तक तथा जो क्रेस ब्रीड की राशि है उसको 30 से 40 हजार रुपये तक बढ़ाने का कोई

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, इसके साथ साथ जो हमारी हरियाण नस्ल की गाय की बीमा राशि 10 दस हजार रखी गई है क्या उसको भी बढ़ाने का कोई विचार है?

सरदार एच एस चटठा: अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात की है हम इस राशि 10 को जरूर बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपने दो सप्लीमेंट्री पूछ ली है अब आप केवल एक और पूछ सकते हैं, I will allow only one more supplementary.

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर सर, मुर्गा नस्ल की भैंस जो 18 किलो दूध देती है उसके कटडे की कीमत हरियाणा सरकार के हिसाब से दस हजार रुपये है।

श्री अध्यक्ष: आपका अपना कोई डेयरी फार्म है क्या?

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर सर, गरीब आदमी और किसान इस व्यवसाय से गुजारा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार मुर्गाह नस्ल की भैंस के कटडे की कीमत दस हजार से बढ़ाकर 25-30 हजार रुपये करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि इस कटडे पर किसान का एक वर्ष का खर्चा दस हजार रुपये से ज्यादा आ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हिसार में एक पशु विज्ञान विद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ

कि जो सरकार ने और विभाग ने पंजुओ के लिए पोली क्लीनिक की योजना बनाई है जो अभी दो जिलो मे भुरु की है क्या सरकार इस योजना को सभी जिला हैडक्वार्टज पर खोलने का विचार करेगी?

सरदार एच एस चटठा: अध्यक्ष महोदय, मै चौधरी रणधीर सिंह जी को मुबारकबाद दिये बगैर नही रह सकता क्योंकि इनका जो डेयरी फार्म है वह हरियाणा प्रदेश के बैस्ट डेयरी फार्मज मे से एक है और मै यह कहूं कि सबसे बैस्ट है तो कोई गलत नही होगा। इसलिए इनको डेयरी फार्म के बारे मे ज्यादा नॉलेज है।

श्री अध्यक्ष: अब तो किसी की नजर नही पडेगी। आप इस बारे मे एग्जामिन करवा लेना।

सरदार एच एस चटठा: ठीक है सर, इसके बारे में एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री सुखबीर फरमाणा: स्पीकर सर, मेरे हल्के के गांव सुसाना मे एक किसान की भैंस जिसकी कीमत 50 हजार रुपये थी उसको किसी ने जहर दे दिया और उस भैंस की मौत हो गई क्या सरकार उस किसान की कोई मदद करेगी?

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह जी ने जो सवाल पूछा है पंजुओ की चोरी या मरने के बाद बीमा राशि देने के बारे में है।

सरदार एच एस चटठा: स्पीकर सर, हरियाणा हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसके हर तीसरे गांव में या तो पशुओं का होस्पिटल है या डिस्पेंसरी खोली गई है। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें इतने डिस्पेंसरी या हास्पिटल पशुओं के लिए खोले गए हों। सरकार को आशा है कि हर गांव में पशुपालन विभाग का एक वर्कर काम करे जो इन मुर्रा भैंसों की देखभाल करें। हरियाणा हिन्दुस्तान में नम्बर एक है जिसके सबसे ज्यादा बैस्ट एनीमलज है। मुर्रा नस्ल की भैंस हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में बैस्ट है। Murrach buffalo is number one in India.

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है इसलिए मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान में जब भी कहीं बर्ड फ्लू आता है तो उसका डर हरियाणा के पौल्ट्री फार्मस में भी आता है। इसके कारण पौल्ट्री में अंडे वगैरह जो भी चीजे होती हैं उनको कोडियो के भाव बेचनी पड़ती हैं क्या सरकार ने उन्हें मुआवजा देने के बारे में सोचा है और कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे आने वाले समय में हरियाणा में कभी बर्ड फ्लू न फैले?

सरदार एच एस चटठा: अध्यक्ष महोदय, बहन जी का सवाल इस सवाल से कनेक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में बर्ड फ्लू नहीं है, हरियाणा इस बीमारी से फ्री है। हरियाणा में सारे डाक्टर, यूनिवर्सिटीज को

हिदायत है कि कही भी एक या दो मुर्गी मर जाएं तो उनका पोस्ट मार्टम करे इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में बिमारी है ही नहीं तो फिर किस बात के लिए हम कोई कदम उठाएं?

श्री सुखबीर फरमाणा: अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के पशु मर जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं क्या उनकी मदद करने को कोई प्रस्ताव सरकार का है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी शिकायत डी सी को लिखवाकर भिजवा दें?

श्री सोमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूएंसी के कई गावों में पशु हस्पताल बने हुए थे और वहां वी एल डी ए बैठते थे लेकिन अब 3 सालों से कई अस्पतालों की बिल्डिंग खाली पड़ी है, उनमें पशु अस्पताल की तरफ कोई कर्मचारी नहीं बैठता, क्या मंत्री जी उन अस्पतालों में कोई वी एल डी ए या वैटरनरी डाक्टर अप्वायंट करने की कृपा करेंगे।

सरदार एच एस चटठा: अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात वाजिब है कि काफी अस्पतालों में वैटरनी डाक्टर नहीं है। पीछे हमने इन डाक्टरों की भर्ती की थी लेकिन वे सारे लग चुके हैं और अब हम 200 वैटरनरी डाक्टरों और वी एल डी ए जल्दी ही भर्ती करने वाले हैं। कोई भी पशु अस्पताल ऐसा नहीं होगा जहां वैटरनरी डाक्टर न हो।

श्री तेजेन्द्र पाल मान: अध्यक्ष महोदय, कैथल ब्रीडींग मे मुरा ब्रीड के लिए हरियाणा मे कई जिले सिलैक्ट हुए है, कैथल भी उन जिलो मे से एक है, उन जिलो के लिए कई प्रकार के कंसै उन भी दिए हुए है लेकिन चिकित्सा सर्विस जिसका आपने जिक्र किया कि हर गांव मे एक वर्कर रखेंगे तो अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हर गांव मे एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलने का कोई प्रावधान करने का सरकार का विचार है क्यांकि इसकी जरूरत भी है?

सरदार एच एस चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, आप इस डिपार्टमेंट के पी एच डी है। हम हरियाणा मे इनसैमीने उन डिवैल्पमेंट स्कीम लाए है, कोई ऐनीमल जो तीन साल का हो वह कंसीव नही करता अगर कंसीव करता है तो गिर जाता है उसके ईलाज करने के लिए हमने हरियाणा के सारे गावों को कवर करने का प्रोग्राम बनाया है। मुरा नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ जिले सिलैक्ट किए है यह ठीक है, इसका मतलब यह नही कि हमने दूसरे जिलो को रिजैक्ट किया है, दूसरे जिलो को भी इसी तरह इमदार मिलती रहेगी, उसी तरह अच्छी दवाईयां मिलती रहेगी। हरियाण हिन्दुस्तान मे सबसे पहली स्टेट है जहां मुंहखुर की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है।

**Class I and II Officers on deputation to Boards/
Corporations**

***880. Sh Karan Siungh Dalal:** Will the Chief Minister will be pleased to state-

(a) the number of Class I and II Haryana Government Officers presently working on deputation in various Boards and Corporations:

(b) the number of those in (a) above who have overstayed their normal deputation period of three years;

(c) the number of those in (b) above who are staying on deputation without equivalent or higher sanctioned posts; and

(d) the number of those deputations in (a) above who have gone back to the same or other board;/corporation without spending the minimum required colling period in their parent department?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

Sir, the information is as under:-

(a) Class I 49 and Class II 36'

(b) Class I 2 and Class-II 6;

(c) Class-I 2 and Class-II 2

(d) Nil

श्री कर्ण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने (a) के जवाब मे कहा है कि श्रेणी-1 के 49 ओर श्रेणी-2 के 36 अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। क्या मंत्री जी कृप्या बतायेंगे कि श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के

अधिकारी जिन बोर्ड और निगमों में तीन वर्ष की अवधि से अधिक ठहरे हुए हैं उन बोर्ड और निगमों का क्या नाम है?

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपका यह सवाल पूछने के पीछे क्या मतलब है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बहुत से बोर्ड और निगम हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में डैपुटी मैन पर गये हुए हैं वे एच एस आई आई डी सी और हुडडा जैसे महत्वपूर्ण बोर्ड और निगमों में गये हुए हैं या दूसरी जगह गये हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, बोर्ड और निगम ओटो नोमस बोर्ड बनाई गई है जिनमें सरकार का बहुत कम दखल होना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में बैठे हुए हैं, उन बोर्ड और निगमों का क्या नाम है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब के प्रश्न के हिस्से का जवाब है श्रेणी-प1 के 49 और श्रेणी-2 के 36 अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में डैपुटी मैन पर गये हुए हैं। क्योंकि इनके प्रश्न के इंटेंट से नहीं मालूम था कि ये बोर्ड और निगमों का नाम भी जानना चाहेंगे इसलिए अभी मुझे बोर्ड और निगमों का नाम मालूम नहीं है। मैं मेरे माननीय साथी को बाद में लिखकर बोर्ड और निगमों के नाम भिजवा दूंगा। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी ओवर स्टे कर गये हैं उनका जवाब

'ख' पार्ट में दिया हुआ है। उन बोर्ड कारपोरेट एंज का नाम मैं बताना चाहूंगा कि ये कर्मचारी हरियाणा पावर जनरेटिंग कारपोरेट एंज, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, कुरुक्षेत्र डिवैल्पमेंट बोर्ड, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेट एंज और हरियाणा रुरल डिवैल्पमेंट फण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के अंदर कार्यरत है।

श्री अमीर चंद मक्कड: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इनके पास लिस्ट होगी कि कौन कौन से अधिकारी कौन कौन से बोर्ड और कारपोरेट एंज में ओवर स्टैट पर रुके हुए हैं। क्या उनको वहां से बदलने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी?

Mr Speaker: Makkar Ji, it is not possible to give reply. You may ask your separate question in this regard and Hon'ble Minister will give reply.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री यह है कि आज तमाम दुनिया के सभी देश आपस में एक दूसरे के ज्ञान से नये नये अविशकारों से जुड़े हुए हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन को आश्वस्त करेंगे कि हमारे जितने भी बोर्ड और निगम हैं उनके अंदर जो स्पेसिफिक लिस्ट अधिकारी हैं, जो बोर्ड एवं निगमों को बहुत अच्छे तरीके से चला सके उनकी नियुक्ति की जाये ताकि बोर्ड और निगम तरक्की कर सकें। क्या इस बारे में मंत्री जी सदन का आश्वस्त करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्र न है परंतु यह नीति का प्र न है इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि जो अधिकारी सबसे काबिल और योग्य हैं वे अधिकारी किसी भी बोर्ड और निगम में कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों में कई दूरगामी निर्णय लिये हैं। मेरे माननीय साथी यदि किसी स्पेसिफिक केस के बारे में या स्पेसिफिक बोर्ड या निगम के बारे में जानना चाहते हैं तो उस बारे में हमें लिखकर भित्ति दें, हम उसका जवाब लिखकर देंगे।

Construction of By-Pass of Dadri City

***927. Shri Nirpender Singh Sangwan:** Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work on by-pass of Dadri City is likely to be started together with the time by which the said by-pass is likely to be completed?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Land acquisition process has been initiated for Dadri by pass. Work shall be taken up after land is acquired.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि दादरी के अंदर ढाणी मोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से दिल्ली रोड पर ट्रफिक बंद हो जाता है और

दूसरा रोड दादरी भाहर के बीच में से है। उस रोड पर हर रोज तकरीबन 1100-1200 डम्पर खेडी बुरा, अटेला और माणकावास की पहाडियो से कंकीट लेकर दिल्ली की तरफ जाते है। दादरी भाहर के अन्दर से अगर ये सारे का सारा ट्रैफिक निकालेंगे तो ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंटस और पाल्यू इन जैसी अनेक गंभीर समस्यायें पैदा हो जायेंगी। इसलिए मै मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक यह बाई पास नहीं बनता है तब तक सारे का सार ट्रैफिक दादरी भाहर के बीच में से न निकाला जाये। यह बहुत जरूरी बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, दादरी भाहर के बाई पास के बारे में मै बताना चाहूंगा कि बाई पास के बारे में जो रिपोर्ट थी वह आ चुकी है। टोटल 15.27 करोड रुपये की लागत से यह आर ओ बी बनेगा। इसका सैव इन 4 सरकार ने कर दिया है। इसमें लैंड एक्वीजी इन की कॉस्ट 6.38 करोड रुपये होगी और इसके कंस्ट्रक् इन पर तकरीबन 8.79 करोड रुपये की लागत आयेगी। एल ए डी बी 4.50 करोड हमने इसकी दे दी है और बाकी के लिए नाबार्ड को भेज रखा है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा बताई गई ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्याओं का संबंध है तो इसके लिए हम साईड में काफी स्पेस रखेंगे। कई अन्य जगहों पर भी इस तरह स्पेस हमने रखा है। अगर उससे बात नहीं बनी तो जहां जहां से ट्रैफिक निकल सकता होगा उसको

देखते हुए हम इसके लिए आलटरनेटिव रुट भी बनाकर देंगे जिससे वहां पर इस प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं होगी।

श्री बलवंत सिंह सढौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रि जी से जानना चाहूंगा कि सारे हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सारा ट्रैफिक यमुनानगर के बीच में से होकर निकलता है जिससे वहां पर हर रोज घंटों जाम लगा रहता है तो क्या यमुनानगर में उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए सरकार के पास कार्ड बाई पास बनाना विचाराधीन है?

केप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके लिए ये मुझे अलग से नोटिस दें, फिर हम इसकी फिजीबिल्टी को कम्प्लीटली एग्जामिन करवा लेंगे। मेरे विचार से यह बात इनकी सही है कि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है। इस काम के लिए हम एक कंसलटेंट भी हॉयर कर देंगे और अगर फिजीबिल्टी बनेगी तो हम वहां पर बाई पास जरूर बनायेंगे।

Opening of an I.T.I in Pataudi Constituency

***863. Shri Bhupinder Chaudhary:** Will the Industrial Training and Vocational Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute in Pataudi constituency.

Urban Development Minister (Sh A. C.

Chaudhary): Yes, Sir it is proposed to convert the Vocational Education Institute at Mojabad into an ITI with effect from the next academic session.

श्री भुपेन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जवाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि 14 मई, 2006 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हम पटौदी के अंदर आई टी आई खोल रहे हैं। यह मामला विचाराधीन है और इसके लिए जमीनो का सर्वे भी हो चुका है। मौजाबाद का तो सैपरेट इ यू है। यहां पर आई टी आई खोलने की बात मैंने पूछी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 में अनाउंसमेंट की थी जिसको 2 साल हो चुके हैं तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री ए सी चौधरी: स्पीकर सर, चूंकि सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था इसलिए मैंने जवाब भी अंग्रेजी में ही दिया है। अब मैं आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूछा है कि पटौदी में आई टी आई खोली जाएगी या नहीं तो मैंने इनको बताया है कि हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट को ही आई टी आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहां तक पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई अनाउंसमेंट का संबंध है तो इस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास उसके लिए जमीन का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसे केंसिज में हमारे द्वारा कुछ नाम्ज फिक्स किए गए हैं

और जब तक वे पूरे नहीं होते तब तक हम कोई आई टी आई खोलने का प्रस्ताव नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अनाउंसमेंट के बाद निर्धारित नाम्ज को पूरा करवाना होता है इसलिए आप निर्धारित नाम्ज को पूरा करवाइये। मंत्री जी ने आपको आ वासन दे दिया है आपकी आई टी आई बन जायेगी।

Sarva Shiksha Abhiyan

***904. Sh. Shahida Khan:** Will the Education minister be pleased to state the percentage of the amount spent under the Sarva Shiksha Abhiyan in the district Mewat out of the total amount allocated for the state?

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, in 2006-07, 5-37% and In 2007-08 upto (31.01.2008) 4-01%.

श्री भाहिदा खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें मेवात के अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ है और इस केस में कई महीने तक लोग जेल में भी रहे हैं। बाद में इस केस में हेरफेर करके इस केस को बिगाड़ दिया गया क्योंकि जब अधिकारी लोग आपराधियों से हमदर्दी रखेंगे तो केस तो बिगड़ेगा ही। इसके अलावा मेवात को जिला बने लगभग 4 साल हो गये हैं लेकिन आज तक वहां पर कोई भी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं

बनाया गया है जबकि सरकार मेवात के बाहर बड़े बड़े हॉर्डिंग्स लगा रही है कि हम शिक्षा के उपर ध्यान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है भाहिदा जी, आप इस बारे में लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें आपको जवाब दे दिया जायेगा।
Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अंशिन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित
प्रश्नों के लिखित उत्तर

Facility of Community Toilets in Bhiwani

***889. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide community toilets in following localities of Bhiwani-

1. Singi Kat Basti;
2. Bawri-Gate;
3. Hanuman-Gate'
4. Balmiki Basti;
5. Kameti Mohalla
6. Jain Chowk
7. Khadi Mohalla
8. Durga Colony and
- 9 Brijawasi Colony?

भाहरी विकास मंत्री (श्री ए सी चौधरी): नही श्रीमान् जी ।

Consolidation in Lohari Sub-Division

***920. Shri Somvir Singh:** Will the Minister of Stte for Revenue and Disaster Management and Consolidation be pleased to state-

(a) the number of such villages in Lohari Sub-Division where the consolidation has not been done so far and whether it is alos a fact that jamabandi of village Kharkhari have also not prepared; and

(b) the time by which the said work of consolidation as referred in Part(a) above will be completed?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल):

(क) श्रीमान जी, सात (7) गांव नामतः गोकलपुरा, मण्डौली कलां, खरकडी अलाउदीनपुर, पहाडी, सिंधानी व चहडकलां की चकबंदी अभी तक नहीं हुई है। यह भी ठीक है कि गांव खरकडी की जामबंदी अभी तक तैयार नहीं की गइ।

(ख) लगभग 3 वर्ष में, बार्ते इन गावों के हकदारान सहयोग दें

Female Foeticide

***894. Sh Sher Singh:** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that steps taken by the

Government to curb female foeticide have not yielded the desired results; if so, the reasons thereof?

स्वास्थ्य कंत्री (बहिन करतार देवी): नही श्रीमान् जी। लिंग अनुपात मे सुधार हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म लिंग अनुपात 819 था। इस घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके फलस्वरुप लिंग अनुपात सिविल रजिस्ट्रें इन सिस्टम अनुसार बढ़कर वर्ष 2006 मे 857 हो गया तथा सिविल रजिस्ट्रें इन सिस्टम अनुसार वर्ष 2007 के अन्त तक यह अनुपात बढ़कर 860 हो गया है।

**Contribution of Government on India under the B.P.I
Scheme**

***898 Shri Tejendr Pal Singh Mann:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the percentage wise details of amount contributed by the Government of India and Haryana Government under the BPL scheme during the period from 1.04.2006 to 31.03.2007 and 01.04.2007 to 31.12.2007 seperately?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

बी पी एल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार का अंशदान

1.4.2006 से 31.3.2007 तथा 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की पृथक पृथक अवधि के दौरान बी पी एल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा अंशदान की गई राशि का प्रति मातवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

अवधि	वस्तु	भारत सरकार का अंशदान (करोड रु) तथा प्रति मात	हरियाणा सरकार का अंशदान (करोड रु) तथा प्रति मात
1.4.2006 से 31.03.2007	गेहूं तथा चावल	263.26 (98.1 प्रति मात)	5.23 (1.9 प्रति मात)
1.4.2007 से 31.12.2007	गेहूं तथा चावल	250.00 (98.3 प्रति मात)	4.38 (1.7 प्रति मात)
1.4.2006 से 31.3.2007	मिट्टी का तेल	*374.2 (100 प्रति मात)	भून्य
1.4.2007 से 31.12.	मिट्टी का तेल	*280.6	भून्य

2007		(100 प्रति त्त)	
------	--	-----------------	--

*लगभग

Construction of Bus Stand at Village Badli

***901. Sh. Naresh Sharma:** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the Gram Panchayat of Village Badli, district Jhajjar has transferred land to the Haryana Roadways for construction of Bus Stans; if so, the details of steps taken by the Transport Department for the construction of Bus-Stand there?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): जी हां, महोदय। दिनांक 22.2.1989 को 20 कनाल 4 मरला भूमि परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित की गई थी, लेकिन अभी तक भूमि का वास्तविक मौका पर कब्जा परिवहन विभाग को नहीं सौंपा गया है। प्रस्तावित भूमि खाली नहीं है और इस पर कई पक्की दुकाने तथा मकान बने हुए हैं। परिवहन विभाग को दी गई भूमि पर से ढांचे हटाने के बारे में जिला प्रशासन के साथ मामला उठाया हुआ है। खाली भूमि का कब्जा प्राप्त होने के बाद बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा।

Construction of Bus Stand at Karnal

***909. Smt. Sumita Singh:** Will the Transport Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus stand

with all the modern facilities including market etc. at Karnal;
and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):

(क) जी हां, महोदया

(ख) प्रस्तावित करनाल बस स्टैंड का निर्माण सभी आधुनिक सुविधाएं सहित सार्वजनिक तथा निजी सहभागिता (बी ओ टी) के माध्यम से निर्माण किया जाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म को सौंप दिया है। जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा प्रस्तावित दस्तावेज तैयार हो जायेंगे तो बस स्टैंड हेतु निविदाएं मांग ली जायेंगी।

To Set-up Big Industry in Ateli Constituency

***929 Sh. Naresh Yadav:** Will the Industries Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a big industry in the industrially backward area of Ateli constituency; if so, the details of the steps being taken by the Government in this regard; and

(b) whether the status of industrial area is being given to the Kanti Kheri area adjacent to Neemarana (Rajasthan) near Ateli?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा):

(क) नहीं श्रीमान्, अटेली निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में बड़ा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

Construction of Bhakra Hansi Butana Canal

***819. Dr. Sushil Indora:** Will the Irrigation Minister be pleased to state

(a) whether the construction work of Bhakra Hansi Butana Canal has been completed;

(b) if not, the present position thereof;

(c) whether there is any inter state dispute in it; and

(d) whether the rules and regulations have been followed to link the Bhakra main canal and the permission has been obtained from the concerned Department or the Ministry?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) श्रीमान् जी, हांसी बुटाना ब्रांच बहु-उद्देशीय सम्पर्क चैनल का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) 99 प्रति ता से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ग) जी हां श्रीमान जी, पंजाब एवं राजस्थान सरकारों ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2007 की याचिका क्रमांक 1 तथा याचिका क्रमांक 3 दायर की है।

(घ) जी हां श्रीमान जी, इस परियोजना के लिए नियम तथा विनियमों को पालन किया गया है।

Power generated by Yamuna Nagar Thermal Power plant

***803. Dr Sita Ram:** Will the Power Minister be pleased to state the total quantum of power generated daily after the inauguration of Yamuna Nagar Thermal Power Plant during the period from 1st November, 2007 to December, 2007 together with the quantum of electricity demand of the State met out by the said power plant?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): श्रीमान, दीनबंधू छोटूराम ताप विद्युत परियोजना, यमुनानगर की 300 मैगावाट की पहली ईकाई ने दिनांक 13.11.2007 को समकर्मण होने के बाद, नवम्बर तथा दिसम्बर 2007 के दौरान 73092 युनिट बिजली का उत्पादन किया है। 28.02.2008 तक इस इकाई ने राज्य की मांग को पूरा करने हेतु 815.96 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है।

Construction of New Subzi Mandi of Narnaul

***815. Sh Radhey Shyam Sharma:** Will the Agriculture Minister be pleased to state the time by which the work is likely to be started on new sabzi mandi of Narnaul?

कृषि मंत्री (सरदार एच एस चटठा): हां, श्रीमान जी, निर्माण कार्य दिनांक 14.04.2008 तक भुरु किये जाने की सम्भावना है।

Water Logging Land of the State

***828. Shri Ranbir Singh Mahendra:** Will the Agriculture Minsiter be pleased to state-

(a) whether any survey has been conducted by the State Government in respect of water logging land of the State; if so, the district wise and village wise details thereof and

(b) whether any steps have been taken by the Central Ground Water Board in Haryana in this regard, if so, the initiative by the Government in this regard?

कृषि मंत्री (सरदार एच एस चटठा):

(क) हां, श्रीमान जी, इस संबंध मे विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) हां श्रीमान जी, इस संबंध मे सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(अ) हां श्रीमान जी, कृषि विभाग की भू-जल कोश भाखा द्वारा नियमित रूप से प्रति वर्ष माह जून (वर्शा ऋतु पूर्व) एवं माह अक्टूबर (वर्शा ऋतु के बाद) राज्य मे चुने हुए 2105 ग्रिड बिंदुओ (कुंए, पिज्योमैट्रिक टयूब आदि) से जलस्तर मापा जाता है। अक्टूबर 2007 मे लिये गये अंतिम आंकडो के अनुसार 0-1.5 मीटर जलस्तर के तहत 111030 हैक्टेयर जिसमे 163 गांव आते है और 1.5-3.0 मीटर जलस्तर के तहत 333144 हैक्टेयर मे 427 गांव आते है।

(ब) श्रीमान जी, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड चण्डीगढ द्वारा राज्य के जिला गुडगांव, झज्जर एवं हिसार की हांसी तहसील मे सेमग्रस्त क्षेत्रो मे अध्यक्ष महोदय,यन किया गयाहै तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट सिफारि गो के साथ जारी की गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 मे नीदरलैंड सरकार की तकनीकी व वित्तीय सहायता से लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि को सुधारने के लिए एक परियोजना लागू की गई है तथा सोनीपत एवं कैथल जिलो में 2406 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया जा चुका है। कृषि विभाग ने वर्ष 2003-04 से भारत सरकार तथा राज्य सरकार की 70:30 हिस्सपूंजी के आधार पर लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि के सुधार के लिए एक योजना कियन्वित की जा रही है तथा अभी तक इस योजना के अन्तर्गत भिवानी, झज्जर, सिरसा व सोनीपत जिलो के 1742 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है।

Allotment of Residential Plots to Scheduled Caste Families

***833 Sh. Shamsher Singh Surjewala:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether Haryana Government had announced the grant of residential plots measuring 100 yards to each of the landless S.C families residing in rural areas;

(b) if so, the time by which the beneficiaries are likely to be given the residential plots;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to arrange finance for the construction of houses on such plots; and

(d) whether the Government intends to develop the land where the plots will be given?

मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान् जी,

(क) पात्र अनुसूचित जाति के परिवारों को 100 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट नि: शुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) क्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। दिनांक 31.3.2008 तक आवेदन पत्र आमंत्रित करने तथा उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए दिनांक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्लॉट आवंटन की समय सारणी पात्र लाभार्थियों की संख्या तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) नही श्रीमान जी, हालांकि, अलाटी अधिसूतिच बैंक या राज्य सरकार की अन्य स्कीमो के अधीन पात्रता के अनुसार वित्त व्यवस्था कर सकता है।

(घ) यथासमय गलियां, पेयजल, बिजली इत्यादि की मूलभूत सूविधाएं प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Godowns Hired on Rent

110. Shri Karan Singh Dalal: Will the Deputy Chief Ministerr be pleased to state-

(a) the yearwise number of godowns hired on rent by the Food & Supplies Department in the State during the year 2000-2001 till date.

(b) whether prior permission from the competent authority was obtained for hiring the godowns as referred to in (a) above; and

(c) if so, the details of such godowan with the names of officers who hired these godowns without prior permission/approval of the competent authority alongwith the action taken against them?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन): श्रीमान् जी,

(क) खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा किराए पर लिये गये गोदामो का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	किराए पर लिये गये गोदामो की संख्या
2000-01	70
2001-02	113
2002-03	121
2003-04	114
2004-05	68
2005-06	43
2006-07	33
2007-08	28

(ख) गोदाम को किराये पर लेने व संबंधित पार्टी के साथ इकरारनामा करने के लिये जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक स्वयं सक्षम प्राधिकारी है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक पी आर मन्यूअल भाग-3 के नियम 6(ए) अनुसार गोदामो के चयन तथा उनको किराए पर लेने के लिए भी सक्षम है।

यद्यपि किराए की अदायगी निदेशक खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा के पूर्व स्वीकृति से वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत/नियत की गई दरों के आधार पर प्रदान की जाती है। पंजाब वित्ती

नियमावली वाल्यूम-1 के नियम 19.6 क्रम संख्या 8 अनुसार जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक 1000/- रुपये तक तथा निदे 1क, खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा 1000/- रुपये से अधिक के किराए की आदायगी करने के लिए सक्षम है। इसलिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा किराए पर गोदाम लेने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परंतु गोदामों की किराए की आदायगी सक्षम अधिकारी यानि निदे 1क, खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा की पूर्व अनुमति लेने के उपरांत की जाती है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि मण्डी से भारतीय खाद्य निगम को स्टॉक का सीधा प्रेशण किया जाता है, जो स्टॉक प्रेशणा के बाद भोश रह जाता है, को खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा जन संस्थाओं के साथ साथ नीजि संस्थाओं से किराए पर लिये गये गोदाम/पलिन्थो पर भण्डारण किया जाता है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अपने अपने जिले में निरीक्षक अमले के साथ तालमेल करके मण्डी के समीप स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोदाम किराए पर लेते हैं। इसके उपरांत जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक संबंधित पार्टी के साथ निर्धारित पी आर 53/96 में इकरारनामा करते हैं।

(ग) जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा गोदाम किराए पर लेने के लिए पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुपस्थिती की अनुमति

(i)

Mr Speaker: Hon'ble Member, I have received Leave of Absence dated 11th March, 2008 from Shri Birender Singh, Finance Minister which reads as under:-

Speaker Sir,

“Due to unavoidable circumstances it would not be possible for me to attend Session on 12th March, 2008. I may please be granted leave of absence from the House.”

Question is-

That permission for leave of absence to Shri Birender Singh, Finance Minister to remain absent from the sitting of the House on 12th March, 2008 be granted.

The motion was carried.

(ii)

Mr Speaker: Hon'ble Member, I have received Leave of Absence dated 11th March, 2008 from Shri Subhash Choudhary, M.l.A which reads as under:-

Respected Speaker Sir,

“ I am sorry to say that i may not attend the Haryana Vidhan Sabha Session on 12-3-2008 due to personal appearance in Civil Court, Jagadhari on 12-3-2008. Therefore, I request you to grant me leave for 12-3-2008.

Thanks.”

Question is

That permission for leave of absence to Shri Subhash Choudhary M.L.A to remain absent from the sitting of the House on 12th March, 2008 be granted.

The motion was carried.

अनुपस्थिती संबंधी सूचना

Mr Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Sh. Paramvir Singh, Parliamentary Secretary dated 11th March, 2008, vide which he has expressed his inability to attend the sittings of the House due to his ill-health. He has also stated that he will attend the Session of Haryana Vidhan Sabha as soon as he recovers from his illness.

सदन के निर्णय को रद्द करना

Dr. Sushil Indora: Mr. Speaker Sir, before starting the discussion on the Governor's Address, I want to say something. अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दिनो से हमारे जो इंडियन ने इनल लोकदल के सम्मानित सदस्यगण है उनको सदन से निकाला जाता है। हमारे एक माननीय सदस्य श्री रामफल चिडाना को सदन की बाकी अवधि के लिए निकाला गया है यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, यह बात तो श्री कर्ण सिंह दलाल जी के सुझाव पर जो मीटिंग हुई है उसमें डिस्कशन हो चुकी है।

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, एक अनावश्यक प्रस्ताव हमारे खिलाफ लाया गया है। हमारे ऊपर लांचन लगाया गया है कि हम हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब करते हैं जबकि हकीकत यह है कि सरकार की तरफ से ऐसे प्रोवोकेशन किये जाते हैं। सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा करती है कि यहां का माहौल बिगड़े और हम हरियाणा प्रदेश के लोगों की सच्ची बात को हरियाणा विधान सभा में न रख सकें। (गौर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और यह कहना कि सदन किसी विशेष दल के खिलाफ साजिश कर रहा है, यह अनुचित होगा। (गौर एवं व्यवधान)

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, यह हमारा हक है कि हम अपनी बात को सदन में कह सकें। हमारे साथी को सदन में वापिस बुलाया जाये और सरकार इस पर खेद प्रकट करें। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है आपने जो प्रस्ताव की बात की है
the resolution was adopted by the house unanimously. The

Members of different parties were sitting in the House. It was adopted unanimously, रही बात unanimously resolution को वापिस लेने की तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात आपने श्री रामफल चिडाना को पूरे हाउस के लिए निकालने की बात कही है तो उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले दस सदन के अंदर एक ऐसा वाक्या हुआ जिस पर मुझे लगता है कि हर सदस्य को, श्री औम प्रकाश चौटाला जी को भी, एन सी पी के सदस्य को भी, बी एस पी के सदस्य को भी, बी जे पी के सदस्यों को भी, कांग्रेस के सदस्यों को भी और निर्दलिय सदस्यों को भी खेद है। वह दिन इस सदन के लिए भी एक खेद का दिन था। अध्यक्ष महोदय, श्री औम प्रकाश चौटाला जी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं। हमारे वैचारिक मतभेद बी जे पी के साथियों से भी हैं, बी एस पी के साथियों से भी हैं, एन सी पी के साथियों से भी हो सकते हैं। हमारे नीतिगत मतभेद भी हो सकते हैं। स्पीकर सर, सत्ता पक्ष का विपक्ष की सारी बात से और विपक्ष का सत्ता पक्ष की सारी बात से सहमत होना जरूरी नहीं है, यही प्रजातंत्र की खुबसूरती भी है। इस खुबसूरती में sometimes we also agree and sometimes we disagree, Sir. इसलिए विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्तलिफ दलों को अपनी बात कहने का अधिकार है परंतु यह अधिकार किसी भी सदस्य को नहीं है कि वह दूसरे सदस्यों पर हाथ उठाए

या उनके साथी गाली गलौच की भाशा का इस्तेमाल करें अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर माननीय सदस्य इन्दौरा साहब ने एक बात उठाई है। वे अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर भी हैं। और अगर वे अपनी पार्टी में उनकी बात को आगे ले जाते हैं तो मैं इस सदन के सामने इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो हुआ it is highly comndemable Sir. यह बहुत ही निन्दनीय है उसको देखते हुए बगैर आरोप—प्रत्यारोप के माननीय विपक्ष के साथी खेद प्रकट करें और इस सार 'इंसिडेंट को कण्डैम करे तो मुझे लगता है कि let by gone be by gone Sir. और हम लोग एक नई प्रणाली की, एक नई मर्यादा की, एक नई परम्परा की भुरुआत करें अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वे खेद प्रकट करे तो हम एक नई भुरुआत करें अगर ये खेद प्रकट करते हैं तो हाउस की कार्यवाही में भाग लेने के लिए उनको वापिस बुला लिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात के लिए आपकी तारीफ कर रहा है। पिछले दिन जो कुछ हुआ है उन सब बातों को दरकिनार करके आपने फाखदिली दिखाई। जब सभी माननीय सदस्यों ने आपसे अनुरोध किया तो आपने आज सवेरे अपने चैम्बर में सभी दलों के माननीय विधायकों को बुलाया। माननीय मंत्री जी भी वहां पर थे। आदरणीय इंदौरा साहब की मौजूदगी में वहां पर जो बात हुई वहां पर भी आपने फाखदिली दिखाई और यहां तक भी कहा कि जैसे ये लोग चाहते हम वैसे ही सदन को चलाने को तैयार हैं। मीटिंग के अंदर

मुख्तलिफ तोर पर जो बात हुई थी इन्दौरा साहब वहां पर खुद मौजूदा थे। जो बात यहां पर आई है यह बैठक में नहीं हुई थी। इस बैठक में तीन बातें तय हुई थीं। पहली बात यह थी कि माननीय स्पीकर साहब के प्रति कोई भी सदस्य अपवाद नहीं करेगा और किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करेगा। नम्बर दो, क्वैचन आवर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिससे प्रदेश के लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। माननीय किसी विधायक को अगर किसी विभाग की कारगुजारी से कोई तकलीफ है तो वह भी प्रेनकाल के अंदर ही उस विभाग से कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही यह तय हुआ था कि प्रेनकाल के दौरान किसी भी माननीय सदस्य किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह हुई थी कि जो माननीय सदस्य हाउस से निकाल दिए गए हैं उस बारे में अब कोई भी बात दोहराई नहीं जाएगी क्योंकि अगर फिर से उस बात को दोहराते हैं तो उससे फिर से एक उत्तेजक माहौल बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य इन्दौरा साहब सुबह की बैठक में मौजूद थे इसलिए मैं आपकी मार्फत इन्दौरा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी व्यवस्था दी है वे अपनी तरफ से लागू करवाएं और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा हम इस बात को अपनी तरफ से लागू करवाएंगे तथा यह आवासन देंगे कि कोई भी सदस्य इस प्रकार की कोई बात नहीं करेगा जिससे माहौल खराब हो। इस बात का फैसला मीटिंग के अंदर ही

हो चुका है। इस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय अपना फैसला देंगे।

श्री औम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, सदन के अंदर जिस प्रकार का वातावरण हुआ उसकी तो सीमा लोग निंदा करते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि यह क्यों हुआ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात यहां पर हो रही है। हमारे सदस्य को अपमानित किया गया। बीच में जो विधायक थे, वे इस समय हाउस में मौजूद नहीं हैं, उनकी हर समय ऐसी सोच रहती है और वे गाली गलौच पर आ जाते हैं। सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्य यहां पर गालियां खाने के लिए नहीं आये हैं। जो कसूरवार है वह माफी मांगे राम गुप्ता फिर उसके बाद अगली कार्यवाही भुरु की जाए।

श्री अध्यक्ष: ऐसी बात मेरे हिसाब से नहीं हुई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी औम प्रकाश चौटाला बहुत लम्बे अर्से से इस सदन के सदस्य हैं, तजुर्बेकार हैं, मैं इनसे यह अनुरोध करूंगा कि जो मौजूदा सदन के अंदर गतिरोध पैदा हुआ है उसको छोड़कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का हम सभी निर्वहन कर पाएंगे। हम सब अपने अपने इलाकों से चुनकर आए हैं। हरियाणा के 2 करोड़ 30 लाख लोगों की जिम्मेवारी हम सब पर है इसलिए हमें कई बार छोटी छोटी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आरोप

और प्रत्यारोप हमें ला लगाए जाएंगे और हमें ला लगाए जा सकते हैं। परंतु जैसा आपने खडे होते हुए ही कहा था कि सदन में जो हुआ है उसका सबको खेद है। इसको कहकर मुझे लगता है कि हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा करके हम सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चला सकते हैं। मैं इनसे उम्र में और तजुर्बे में छोटा हूँ और मैं इनसे आदर के साथ यह अनुरोध करूंगा कि अगर आज भी आरोप—प्रत्यारोप के अंदर पडे रहेंगे तो इस सदन की सुचारु तरीके से कार्यवाही चलाने में दिक्कत आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य के साथ एक सदस्य की दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना की हम सब निंदा करते हैं और अगर आप सब सहमत हैं तो हम आपसे सादर यह अनुरोध करेंगे कि उस सदस्य को सदन में वापिस बुला लिया जाए। वे सदन में आकर अगर कहें कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी और उनको भी इस घटना पर खेद है। तक हम आगे चलेंगे। अगर हम इसी रतह से इल्जाम और काउअर इल्जाम लगाते रहेंगे तो सदन आगे नहीं चल पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से आगे चलनी चाहिए।

Mr Speaker: Is it the sense of the House that Shri Ram Phal Chirana, M.L.A may be called back in the House?

Voices: Yes.

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):
Sir, I beg to move-

That that decision of the House taken on 10th March 2008 in respect of Shri Ram Phal Chirana, M.L.A suspending him for the remainder of the present Session under Rule 104 read with Rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, be rescinded.

Mr Speaker: Motion moved-

That that decision of the House taken on 10th March 2008 in respect of Shri Ram Phal Chirana, M.L.A suspending him for the remainder of the present Session under Rule 104 read with Rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, be rescinded.

Mr Speaker: Question is-

That that decision of the House taken on 10th March 2008 in respect of Shri Ram Phal Chirana, M.L.A suspending him for the remainder of the present Session under Rule 104 read with Rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, be rescinded.

The motion was carried.

Mr Speaker: Now, I allow Mr Ram Phal Chirana, M.L.A to participate in the proceedings of the House.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपकी फिराखदिली की दाद देता हूँ और आपका अनुरोध करता हूँ। मैं सभी माननीय सदस्यों से तथा सीनियर मैम्बरों से अनुरोध करता हूँ कि हम इन बातों में न पड़कर के क्योंकि यह बजट से इन है और इस बजट से इन में विपक्ष को जो भी कहना है

वह बिना किसी टीका टिप्पणी के कहे। विपक्ष सरकार को इस बात के लिए विवर्णित कर दे कि वाकई कही पर कोई अनदेखी हुई है और गलत कार्य हो रहे हैं। ऐसी हेल्दी डिस्कशन करके सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करें

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन बीती बातें विसार दे और आगे की सुध लें। आगे सदन सुचारु रूप से चलेगा ऐसी हम कामना करते हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr Speaker: yesterday, Somvir Ji was on his legs. Please, continue your speech on Governor Address.

श्री सोमवीर सिंह (लोहारु): स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गवर्नर एड्रेस में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में दिखाया गया है। इस एड्रेस से साफ झलकता है कि यह सरकार किसानों की विशेष तौर पर मदद करने का इरादा रखती है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के बिजली के 1600 करोड़ रुपये माफ किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो जमींदारों की जमीन एक्वायर की जाती है उसका फ्लोर रेट हरियाणा में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सन् 2007 में वर्षा ज्यादा होने के कारण और ओलावृष्टी के कारण जो नुकसान हुआ था उसका 208 करोड़ रुपये का मुआवजा सरकार ने दिया

है। इसी तरह से सरसौ और चने की फसल को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत भामिल किया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसी तरह से मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा गन्नौर में 500 एकड़ जमीन पर वि. व. स्तर की टर्मिनल मार्किट बनाई जा रही है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा दिवस पर सरकार ने जमींदारों के कोओप्रटिव बैंकों के लोन का जो इन्ड्रस्ट माफ किया है इससे जमींदारों को बहुत फायदा होगा। सरकार ने 830 करोड़ रुपये के कर्जों के इन्ड्रस्ट माफ किया है, उससे आम आदमी को इन्ड्रस्ट के बोझ में दबा हुआ था, इससे उसको बहुत राहत मिली है। इसी तरह से प. उ. वि. विद्यालय की स्थापना हिसार में की जा रही है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से समान पानी के बंटवारे का एक साहसिक कदम इस हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इस हांसी बुटाना लिंक कैनल को बनाने का करीब करीब 90 फीसदी काम हो चुका है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी चेयर पर पदासीन हुए।) सभापति महोदय, इससे पहले तो कुछ जिलों को पानी का फायदा हो रहा था लेकिन आने वाले समय के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि दक्षिणी हरियाणा को इसका काफी फायदा मिलेगा। इसी तरह से यह सरकार पीने के पानी पर काफी जोर दे रही है। खासतौर पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। उनके लिए 200 लीटर की पानी की टंकी मुफ्त में देने और पानी का

कनैव उन देने का काम किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हरियाण में 'इंदिरा गांधी पेय जल स्कीम' की भुरुआत की है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर सबसे बड़ी प्रोब्लम जो है वह बिजली की है। बिजली की इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले यमुनानगर थर्मल प्लांट के अंदर 300-300 मैगावाट की दो यूनिट्स लगायी है। इसी तरह से हिसारे के खेदड गांव के अंदर थर्मल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आए थे। वहां पर 1200 मैगावाट का थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है। यह प्लांट वर्ष 2010 ते पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार झाडली गांव के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 1500 मैगावाट का थर्मल प्लांट लगाने की भुरुआत की है। यह प्लांट वर्ष 2010 में चालू किया जाना है। इसी तरह से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कई गावों में ग्रामीणी कनैक्टिविटी में सुधार की स्कीम लागू की गयी है। इस योजनामें 242 करोड रुपए की लागत आएगी। इस योजना से आम आदमी को फायदा होगा। इसी तरह से भाहरो कं अदंर नगरपालिकाओ की मदद करने के लिए उनको वित्ती सहायता दी जा रही है। गुडगावं में भी एक नये नगर निगम की स्थापना की जा रही है। इसी तरह 8 नगरपालिकाओ की भी स्थापना की जा रही है। इन 8 नगरपालिकाओ में मेरे लोहारु भाहर को भी भामिल किया गया है जिसके लिए मैं सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों की मदद करने के लिए जिन भाहरी क्षेत्रों के वार्डों में उनकी

आबादी 50 परसेंट से अधिक है वहां 144 वार्डों में सरकार आने वाले दो साल के अंदर 144 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसी तरह से भाहरो के अंदर भी हाउस टैक्स माफ किया गया है। इसी तरह से देहात के अंदर चूल्हा टैक्स भी माफ किया गया है। यह चूल्हा टैक्स अनुसूचति जाति के लोगों का तो अनाउंसमेंट के वक्त ही माफ कर दिया गया था और जो बाकी लोग है उनका भी चूल्हा टैक्स 31 मार्च तक हमें उनके लिए माफ कर दिया जाएगा यदि वे अपना टैक्स 31 मार्च से पहले पहले पे कर देंगे। इसी तरह से चेयरमैन सर, हुडडा ने भाहरो के अंदर एक 'आरि याना' नाम की योजना शुरू की है। पंचकूला में 2072 फ्लैट्स इसी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, सिरसा, अम्बाला, और गुडगांव में भी ऐसे ही बीस हजार फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड के द्वारा भी कमजोर वर्गों के लिए 50 हजार मकान बनाए जा रहे हैं इन मकानों में औरतो के 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह से गांव के अंदर हुडडा की तरह सैक्टर बनाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिससे गांव के अंदर भी अब तरक्की हो सकेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको पहले महेन्द्रगढ़ और सिरसा में शुरू किया गया था उसको अब अम्बाला और मेवात जिलों में भी लागू किया जा रहा है। आने वाले वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंदर इस योजना को बाकी जिलों के अंदर भी लागू किया जाएगा। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने गांवों के

अंदर एक और योजना लागू की है। यह मुख्यमंत्री दलित गावें उत्थान और मलिन बस्ती विकास योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की 50 प्रति 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों में 50 लाख रुपये प्रति गांव खर्च करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी। इससे इन गावों के अंदर भी तरक्की हो सकेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको पहले महेन्द्रगढ़ और सिरसा में शुरू किया गया था उसको अब अम्बाला और मेवात जिलों में भी लागू किया जा रहा है। आने वाले वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंदर इस योजना को बाकी जिलों के अंदर भी लागू किया जाएगा। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने गावों के अंदर एक और योजना लागू की है। यह मुख्यमंत्री दलित गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती विकास योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की 50 प्रति 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों में 50 लाख रुपये प्रति गांव खर्च करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी। इससे इन गावों के लोगों को फायदा होगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने करनाल के अंदर एक रैली की थी जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को काफी प्रोत्साहन देने की बात कही थी। जिन अनुसूचित जाति के लोगों के पास रिहायश के लिए एग्रीकल्चर जमीन नहीं है उनको 100-100 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। चेयरमैन सर, यह एक बहुत बड़ा काम है इसका लोगों को बहुत देर से इंतजार था क्योंकि लोगों के पास जगह की कमी थी। मैं इसके लिए सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से गावों में सफाई

कर्मचारी लगाने की बात है। इसके लिए भी एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गावों में 11000 सफाई कर्मी नियुक्त किए जा रहे हैं। इनको 3510 रुपये प्रति हैड के हिसाब से दिया जाएगा। चेयरमैन सर, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत फायदा होगा, उनको बहुत राहत मिलेगी। इतनी भारी संख्या में किसी भी स्टेट के अंदर इम्प्लायमेंट नहीं दी गयी है हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जिसने यह काम किया है। इसी तरह से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। सरकार ने वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष घोषित किया है। जिन बच्चों ने अपनी पढाई बीच में छोड़ दी थी उनके लिए आगामी सत्र से सरकार द्वारा बुक्स और एक्सरसाइज बुक्स फ्री दी जाएगी। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों की मदद के लिए एक अलग से मासिक छात्रवृत्ति की योजना बनाई गयी है। इसी तरह के टेक्नीकल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके। इसी तरह से गैस्ट टीचर्स की नियुक्ति कर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब हम किसी भी गांव में स्कूल में जाते हैं तो हमें टीचर्स की कमी महसूस नहीं होती है। कुछेक बातें ऐसी हैं जो मैं अपनी कांस्टीच्युएन्सी के बारे में कहना चाहूंगा। चेयरमैन सर, एक बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पडी है। सर्दी ने इस बार पिछले 50 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। इस सर्दी से मेरे एरिया में सरसों और जौ की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार ने बिजली के बकाया बिल माफ

किए है और 830 करोड रुपया बैंको के ब्याज छोडा है। इसके अलावा भी और बहुत सी राहते सरकार ने प्रदान की है। केन्द्र सरकार ने भी 60000 करोड रुपया जमींदरो का छोडा है। सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरसों ओर जौ व थोडे बहुत गेहूं की फसल का जो मेरे एरिया मे नुक्सान हुआ है उसकी गिरदावरी करवाकर उसका मुआवजा किसानो को दिलवाया जाए। इसी तरह से ने नल हॉर्टीकल्चर मि नल ने बहुत बडी राशि स्टेट गवर्नमेंट को जमींदारो के लिए दी है। बागवानी के उपर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पौधे तो लगवा दिये लेकिन उनके रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आप पिछले तीन साल का रिकार्ड देख सकते है। 20 परसेंट पौधे भी नहीं बचे है। पौधे लगा तो दिये जाते है लेकिन उनकी मेंटीनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से मैं सरकार के ध्यान मे एक बात भी लाना चाहता हूं कि ने नल फूड सिक्योरिटी मि नल के तहत 500 रुपये प्रति कट्टे के उपर सबसिडी दी जाती है। गेहूं के प्रति कट्टे के उपर 200 रुपये दिये जा रहे है। भिवानी सब डिवीजन के अंदर इसके तहत 4.5 करोड रुपये के बिल सबमिट हुए है ओर भिवानी के लोहारु सब डिवीजन मे अब तक मात्र 4 लाख रुपये की राशि के बिल सबमिट हुए है। भिवानी सब डिवीजन के अंदर 4.5 करोड के बिल और लोहारु के अंदर मात्र चार लाख रुपये के बिल सबमिट हुए हैं इसका क्या कारण है? जबकि लोहारु क्षेत्रफल भी बडा है। इसका कारण यह है कि

अधिकारियों की कमी है। भिवानी में 35 ए डी और लगे हुए हैं जबकि लोहारु में मात्र 3 ए डी और हैं। क्या तीन आदमी इतना काम संभाल लेंगे? इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए। मेरे एरिया के किसानों को इस बात का बहुत नुकसान हुआ है। उनको जो सबसिडी मिल सकती थी, उससे वे वंचित रह गए हैं। इसके लिए यह भी करना चाहिए जो लोग अब बिल सबमिट करना चाहते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए ताकि वे भी अपने हिस्से की सबसिडी ले सकें। ए डी और को आफिस किराए पर लेने के लिए 50 रुपये की राशि दी जाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या 50 रुपये की राशि में कोई आफिस किराए पर दे देगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि देहात के अंदर ए डी और बैठ सकें और वहां के किसान इस बात का फायदा उठा सकें। इसके अलावा एक और अहम समस्या भी आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि पेस्टीसाइड्स ओर चोती के बीच बहुत सी जगहों पर डुप्लीकेट दिये जाते हैं ओर बिल वे देते नहीं हैं। इस बारे में हर तीसरे महीने चैकिंग होनी चाहिए। चैकिंग के लिए जो किसान क्लब बना हुआ है उस किसान क्लब के मੈबर को साथ लाना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। एच एल आर डी सी और सो ल कंजरवे इन डिपार्टमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं इरीगे इन मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कुछेक उपल जो कि आउट आफ नार्म्स है बहुत सी जगहों पर कंसोलिडै इन के अंदर रास्ते कटे हुए हैं। लेकिन इरीगे इन डिपार्टमेंट के

नियम में है कि एक किलोमीटर के नजदीक एक साईड और एक किलोमीटर दूसरी साईड में दो किलोमीटर के भी हम कोई पुल नहीं बनायेंगे। अगर कन्सोलिडेशन के अंदर वह रास्ता नजदीक कर दिया गया है तो किसन का क्या कसूर है। उस पुल के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करो यह हम नहीं कहते लेकिन उस किसन का ट्रक्टर तो उसके खेत में आ जा सके, उसकी उंट गाड़ी तो आ जा सके। अगर ऐसे भी आप पुल बनाएंगे तो ऐसे पुल पर ज्यादा से ज्यादा दो लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। मेरे कान्सटीच्यूएन्सी में ऐसे तकरीबन 15 पुल बनाने की डिमाण्ड बार बार उठाई गई है तो निचले स्तर पर तो मंजूर हो जाती है लेकिन यहां पर आकर वह रिजैक्ट हो जाती है कि यह तो आउट आफ नामर्ज है। उस जमींदार का क्या कसूर है जिसके खेत के बीचों-बीच से नहर निकल जाती है और उसके खेत में जाने का रास्ता नहीं मिलता। आप कहते हैं ये नामर्स में नहीं आते।

श्री सभापति: नामर्स ये होने चाहिए कि जाह 'कन्सोलिडेशन का रास्ता छुटा है पुल उसी रास्त पर बनाया जाना चाहिए।

श्री सोमवीर सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस किसान का 20 एकड़ का खेत है और उसके खेत के बीचों-बीच से नहर निकाली गई है और वहां पर कंसोलिडेशन का पाथ नहीं है तो इसमें किसान का क्या कसूर है? नहर निकालते समय यह देखना चाहिए कि उस किसान

का खेत एक तरफ रहे ओर अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया तो उसको अपने खेत में जाने के लिए एक तरफ रास्ता तो अवय ही दिया जाना चाहिए।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल वाजिब है। जो नहरों पर पुल बनाने की डिस्टेंस है वह अब सरकार ने कम भी किया है। पहले यह डेढ़ किलोमीटर का था जिसे अब घटाकर एक किलोमीटर कर दिया है। लेकिन हमने यह भी कोशिश की है कि जहां गांव से गांव कनेक्ट करते हो तो उनको भी हमने टेकअप किया है। लेकिन जहां जहां नहरों पर पुलों को बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां पर सरकार द्वारा आउट ऑफ नार्मर्ज में भी इजाजत दे दी जाती है। अगर माननीय सदस्य के हल्के में ऐसा कोई एरिया है जहां पर नहर पर रास्ता देने की बहुत निहायत जरूरत है तो इस पर सरकार अवय विचार करेगी।

श्री सोमवीर सिंह: मेर कास्टीच्यूंएसी में ऐसे 15 केंसिज हैं जो नीचे के आफिसिज से रिक्मेंड होकर आये हुए हैं। सरकार उन पर विचार करे और कुछ तो किसानों को सुविधा दे। जिसके खेत के बीच से नहर निकाली है और जहां कोई कंसोलीडेसन का पाथ नहीं है वहां पर यह सुविधा मिलनी चाहिए। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जो लोहारू फीउर बनाया गया था यह उस समय खासतौर पर लोहारू और बाढडा कान्सटीच्यूंएसी के आखिरी टेल एण्ड तक पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया था

ओर यह बहुत समय पहले बनाया गया था। उस समय पानी की जो मात्रा दी गई थी उसके बाद उस लोहारु फीडर से कम से कम 7-8 जगह नये माईनर और नये लिंक बनाये गए है जैसे कि कमोद, बोंद, भागवी, मिसरी, समसपुर माण्डी, मानकवास आदि माईनर बनाये गये है। इस तरह से इनका नुक्सान तो आखिरी एरिया मे पडने वाले लोहारु और बाढडा एरियाज का ही होता है। जो पानी उस समय लोहारु फीडर और बाढडा एरिया के लिए मंजूर किया गया था तो इन नए माईनर्ज के निकलने से जो पानी की कमी होगी तो उन लोगों की होगी जिनका एरिया टेल एंड पर पडता है। वहां पर कर्डी लिंक माईनर निकाले गए है। मेरी मंत्री जी से इस बारे मे बात भी हुई थी उन्होने मुझे आ वासन भी दिया है कि बोंद लिंक को लोहारु फीडर के साथ न जोडा जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य की सही बात है कि जितने भी कैरियर चैनल्ज है उसमे जो भी जगह जगह मांग आती है विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जहां तक हो सके उसमे से मिनिमम कैरियर चैनलज माईनर्ज निकाले जायें। विशेष तौर पर लोहारु और बाढडा के इलाको में जहां पीने का पानी नही पहुंच पाता है और जहां पानी की चोरी भी होती है। क्योंकि लोग बीच मे सीधे पम्प लगा लेते है। माननीय सदस्य ने इस बारे मे मुझ से दूरभाश पर भी यह बात की थी। तब विभाग ने इस बारे मे मीटिंग ली थी हमने फैसला

किया है कि इस प्रकार के सब माईनर कैरियर चैनलज न निकाले जायें ।

श्री सभापति: जब हांसी बुटाना लिंक नहर बन जाएगी तो पूरा पानी आ जायेगा और यह समस्या हल हो जाएगी। पानी की अवेलेबिलिटी बढ जायेगी।

श्री सोमवीर सिंह: माननीय मंत्री जी से मैने इस बारे में टेलीफोन पर भी बात की थी कि लोहारु फीडर के उपर परमानेंट मोरियो मे से इतना पानी नही जाता जितना इंजर लगाकर पानी चोरी करके जाता है, कई जगह 8-8 इंच मोटे पाईप परमानेंट लगा रखे है और वह चलते भी है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते है कि जहां आठ इंची पाईप नाजायज लग रहे हो ओर सैंकडो इंजन नाजायज लगा रखे हो तो आगे पानी कैसे जा सकता है? मै दावे के साथ कहता हूं कि 7 और 8 तारीख को लोहरवाडा और मोरवाला गांव मे ऐसी चोरी के केस पकडे गये थे। जब उन पर विभाग ने ऐक् इन लियातो लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और उनको छोड दिया गया। मे आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रास्ता जाम करके पानी की चोरी कर सकते है क्यांकि इससे लोगों का नुक्सान हो रहा है? अगर ऐसा है तो हम भी रास्ता जाम करवाना भुरु करवा देते है। आप एडमिनिस्ट्र इन की तरफ से सख्ती बरतें। उन लोगों के उपर भी केस बनाए गए थे। इस बात का आप अपने अधिकारियो से पता करवा ले और डी सी से भी पता करवा लें। रास्ता जाम होने की

वजह से केस भी वापिस हुए थे। उन लोगों ने पानी की चोरी करने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। जिस दिन से नहर बनी है लोहारु मे टेल तक पानी नहीं पहुंचा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, इन्होने मुझे परसो सूचना दी थी तो मैने उसी समय डी सी भिवानी और डी सी झज्जर से बात की और उनसे कहा कि जहां जहां इस प्रकार बडे बडे पाईप लगा रखे है जिसकी वजह से आगे के एरियाज मे पीने का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां आप सख्ती से कार्यवाही करें मै माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के इलीगल पाईप लगाते है उनकी कतई मदद न करें। हमारी पूरी कोशिश है कि इस प्रकार की पानी की चोरियो न हो। इनके कहने पर ही मैने उसी समय डी सी भिवानी और डी सी झज्जर से बात की थी।

श्री सोमवीर सिंह: तहसील मे इस तरह की मैक्सिमम चोरियां हो रही है। वहां आपके अधिकारी जाते है और तावान लगा देते है लेकिन तावान न कोई पे करता हे और न कोई तावान से डरता है इसलिए मै कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए पुलिस की मदद लें और एकस्ट्रा कर्मचारियो की मदद लें।

श्री सभापति: सोमवीर जी, मंत्री जी ने पूरा आ वासन दे दिया है इसलिए आप अगला प्वायंट लें।

श्री सोमवीर सिंह: सभापति महोदय, पम्प हाउस नं० 1 से लेकर 8 तक के लिए महकमे ने बिजली की इंडीपेंडेंट लाईन 1970 मे ली थी। वहां पर डिपार्टमेंट ने अलग से अतिरिक्त पैसा जमा भी करवाया था। हर महीने करीब डेढ करोड रुपये का बिल इरीगे इन डिपार्टमेंट पे कर रहा है। लेकिन जो बिजली की लाईने बिछी हुई है उन लाईनो से पी डब्ल्यू डी ने, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने और आई टी आई बेरला ने भी अलग से कनैक् इन लिए हुए है। इन कनैक् इनो के वजह से पम्प हाउसिज पर पूरी वोल्टेज नही पहुंच पाती। बार बार ट्रिपिंग होती है। पीछे से कुछ पम्प चले और आगे लोड नही उठता तो उसका कोई फायदा नहीं हमने बार बार विधान सभा मे यह बात उठाई है कि बिजली नही मिल रही है हमे बिजली पूरी देने के आ वासन मिल रहे है और कहा जाता है कि ये कनैक् इन हटवा दिए जाएंगे लेकिन आज तक ये कनैक् इन नही हटे है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई टाईम निश्चित कर दें कि इतने समय के बाद ये कनैक् इन हटा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, इस इ यू के बारे मे इनका प्र न नं० 678 भी लगा है। यह बात सही है कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को पीने का पानी भी देना होता है, कुछ कनैक् इन पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने उन फीडसज्र पर ले रखे है। मैने पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से कहा था कि वे बिजलीके अधिकारिया को कहें कि या तो उनको अलग से फीडर दे और

अगर दिक्कत है तो कम से कम वहां की कैपेसिटी को बढ़ाएं। जहां तक आई टी आई बेरला के कनेक्ट इन लेने के बारे में बात है तो उसके बारे में आदेश दिए गए हैं कि उसका कनेक्ट इन डिस्कनेक्ट कर दे लेकिन जो प्राइवेट जमींदारों को कनेक्ट इन देने की बात है तो हमने कोई प्राइवेट जमींदारों को कनेक्ट इन नहीं दे रखे हैं और अगर कोई ऐसी बात आपके नोटिस में आती है तो आप बताएं उन कनेक्ट इन को हम हटवा देंगे। जहां तक पीने के पानी की समस्या है तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए हम कदम उठाएंगे।

श्री सभापति: मंत्री जी, इन्होंने प्राइवेट कनेक्ट इन की बात नहीं की बल्कि चोरी रोकने की बात कही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, इन्होंने प्राइवेट कनेक्ट इन की बात की है। जहां तक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है तो अगर वे ट्यूबवैल्व के कनेक्ट इन एकदम हटवाएंगे तो दिक्कत आएगी। हमने पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से कहा था कि इस मामले में कार्यवाही करें और अलग से इंडीपेंडेंट फीडर लगवाएं ताकि हमारे पम्प हाउसिज पर इस तरह की दिक्कत न आ सके। हम कोशिश करेंगे कि वोल्टेज को बनाएं ताकि बार बार ट्रिपिंग भी न हो।

श्री सोमवीर सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने

या पी डब्ल्यू डी ने जो कनेक्शन वहां पर ले रखे हैं उनके लिए एक टाइम निर्धारित करे कि कितने टाइम बाद ये कनेक्शन हटा लेंगे।

श्री सभापति: सोमवीर जी, यह प्रश्न काल नहीं है। आप अपनी बात रखें।

श्री सोमवीर सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप जवाब दे रहे हैं। मैं तो अपनी बात बोलूंगा ही। सभापति महोदय, बेरला में पम्प हाउस नं० 6 और 7 को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पम्प नं० 6 और 7 को अलग अलग जगह से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। एक जगह से बिजली चली जाती है तो दूसरा पम्प पानी नहीं उठा पाता इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पम्प 6 और 7 दोनों को एक जगह से कनेक्शन दिया जाए ताकि बिजली आए तो पानी दोनों जगह से चल सके। जब एक जगह पानी चल पड़ता है और दूसरी जगह पम्प पानी नहीं उठा पाता। सभापति महोदय, बाढडा और लोहारु जैसे रेतीले इलाकों के लिए 1970 में लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम बनाया गया था। सभापति महोदय, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि जितने पानी की जरूरत आज करनाल, सोनीपत, और रोहतक जिलों के अंदर एक एकड़ जमीन की सिंचाई करने में पड़ती है लोहारु बाढडा के अंदर एक एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए उससे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो वाटर अलाउंस लोहारु और बाढडा के लिए पहले

थे वह अब दोबारा से भुरु किया जाये। सभापति महोदय, लोहारु और बाढडा के लिए 3.05 क्यूसिक पानी प्रति एक हजार एकड के लिए अलाट किया गया था और हमारा टोटल 1380 क्यूसिक पानी बनता है जिसको पिछली सरकार ने कम करके 2.40 क्यूसिक प्रति एक हजार एकड के हिसाब से हमारी जनता के साथ बहुत नाइंसाफी की। पिछली सरकार की नाइंसाफी की वजह से लाहारु और बाढडा का पानी कम होकर 850 क्यूसिक रह गया। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि लोहारु और बाढडा के लिए 3.05 क्यूसिक पानी प्रति एक हजार एकड के हिसाब से अलाउ किया जाये ताकि वहां के लोगों को पूरा पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं जैसा कि मैं चोरी की बात कर रहा था कि अगर आप पानी को जितने ज्यादा दिन तक चलायेंगे उतना ज्यादा नुकसान लोहारु हल्के को होगा क्योंकि 16 की बजाय 20 दिन 400 400 क्यूसिक या 200-200 क्यूसिक पानी नहर में चलेगा तो लोहारु तक पानी नहीं पहुंचेगा, पहले ही पानी चोरी होता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जी 8-8 दिन ही इकटठा पानी लोहारु हल्के के लिए चलाये ताकि वहां तक पानी पहुंच सके। अगर इनके अधिकारी कहते हैं कि इकटठा पानी पम्पस नहीं उठा सकते हैं तो यह उनमें इम्प्रूवमेंट करे या एकस्ट्रा पम्प लगाये। सभापति महोदय, दादरी हल्के के अंदर 37 वाटर वर्क्स नये बनाये गये हैं और बाढडा के अंदर भी नये वाटर वर्क्स बनाये गये हैं। उन वाटर वर्क्स के लिए अलग से पानी अलाट नहीं किया गया है। जब तक वे वाटर वर्क्स नहीं भरते किसानों को पानी नहीं मिलता।

किसान तो सोचते हैं कि उसमें भी चोरी कर लें। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि फलां जगह का वाटर वर्क्स भर रहे हैं। कभी कह देते हैं फलां जगह का वाटर वर्क्स भर रहे हैं और हकीकत में कहीं का भी वाटर वर्क्स नहीं भरते और न ही किसानों को पानी देते हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो 7-8 दिन निश्चित कर रखे हैं उनमें भिवानी या दादरी के वाटर वर्क्स भरते हैं तो भरे और नहीं भरते हैं तो न भरे लेकिन लोहारु के लिए जितना पानी अलाउड है वह पानी लोहारु को अवश्य मिले। सभापति महोदय, इसी तरह से बीन्द्रावण पम्प हाउस है वहां पर 1998-99 के बीच काफी पानी मिलता था जिससे 8-9 मोटरे उठाती थी और लोहारु डिस्ट्रिब्यूटरी के उपर दमगोरा गांव तक पानी चलता था। लेकिन मंत्री जी इस बात के लिए इंतजार करें कि जैसे वहां पहले पानी मिलता था उसी तरह से पानी मिले। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कमोद, समंसपुर और लोहरवाडा आदि गांवों की तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। कई गांवों में सेम की समस्या है उनकी तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। कई गांवों में मोरी नहीं लगी हुई वहां के किसान पानी की चोरी करके धान की सिंचाई करते हैं उस तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। चरखी दादरी और मानकावास आदि गांवों की तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। सभापति महोदय, जुई नहर के अंदर 8 दिन इकट्ठा पानी मिलता है मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से लोहारु के अंदर भी इकट्ठा पानी दिया जाये और पहले जो 1380 क्यूबिक पानी हमें अलाउट था वह दोबारा से मिलना चाहिए। इसक साथ साथ मैं मंत्री

जी से प्रार्थना करुंगा कि लोहारु और बाढडा के अंदर अधिकतर खाले कच्ची है उन्हे पक्का किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया की सिंचाई हो सके। सभापति महोदय, अब मै रोडवेज के बारे में जिक करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के जिन गावों मे पहले बसें चलती थी अब वहां नही चल रही। नांगल बाजु से बुढडी और सिवाणा से बुथ पैली, विधवाण, मण्डौली खुर्दा और बहल आदि गावों मे इस समय बसे नही चल रही। मंडौली खुर्द है, बजल है ये काफी लम्बे रुट है इनके उपर कोई बस नही चलती। पहले तो वहां पर एक पुल की प्राब्लम बनाई जाती थी लेकिन वह पुल भी अब नहरी डिपार्टमेंट ने चौडा कर दिया है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर बस सेवा प्रदान की जाये। रोड्स के बारे मे भी मै आपके माध्यम से खासतौर से मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि जो तो गाम, बहन और भुद्धिवास रोड है अगर आप उस रोड से जाते है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जीन को नही चलाया जा सकता। इसलिए उस सडक पर विशेष तौर से गौर करनी चाहिए। बाकी मेरी कांस्टीच्युएं ि के साथ बडी रेल लाईन गुजर रही है वहां पर पहाडो से बजरी, पत्थर, कंकर लेकर डम्पर जाते है जिनकी वजह से ज्यादातर रोडस का बहुत बुरा हाल है तो मै चाहूंगा कि गिगनाउ से लेकर सहर, पहाडी और मानफरा से बहन तक इस रोड का खासतौर से ध्यान दिया जाये और जैसे कुछ एक गावों के अंदर जो सडके बनी हुई है वे बहुत ही नीचे में है और वहां पर पानी भर जाता है। इस बात को मैने कई बार संबंधित

अधिकारियों के नोटिस में भी लाया और आज फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जी से प्रार्थना करता हूँ कि खासतौर से बडदू जोगी जो गांव है वहां रोड्स की इतनी बुरी हालत है और वहां पर हर वक्त कीचड़ भरा रहता है जिससे उस पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ऐसे कुछ एक ओर गांवों के बारे में भी मैंने लिखकर दिया हुआ है जहां पर रोड्स पर पानी खड़ा रहता है। गुडेडी गांव है ओर भी कई गांव हैं जैसे कुलपुरा है जहां की रोड पर पानी भरता है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, खासतौर से मैं सिवानी जो कि एक सब डिवीजन है, के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि वहां पर पी एच सी है। उस सब डिवीजन के अंदर घुरेरा, लीलस, बडवा और झुप्प गांव आते हैं लेकिन वहां पर पी एच सी एक है तो मैं आपके माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूँ कि वहां पर 50 बिस्तर का एक हास्पिटल बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा हो सके। यह बड़ी सोचनीय बात है कि उस सब डिवीजन में एक ही पी एच सी है और वहां पर भी कोई डाक्टर नहीं है। 2-3 बातें और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं खासतौर से सिवानी-बडवा का जिक्र करना चाहता हूँ वहां पर एक हास्पिटल बिल्डिंग एक सेठ द्वारा बनाई गई है वहां पर हास्पिटल चल रहा है। लेकिन उस बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) इस बारे में हम अगर महकमे वालों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि रिपेयर तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि इसका कब्जा हमारे पास नहीं है। मैं आपके माध्यम

से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बारे में भी कुछ कारगर कदम उठाये जाए। उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेकर उसकी रिपेयर की जाये क्योंकि इतनी अच्छी और बड़ी बिल्डिंग आपको मुफ्त में मिल रही है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए और इसकी समचित व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री औम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा दिन है लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष के लोगों को आज तक बोलने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। यह तो आपको तय करना चाहिए कि हमें बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अभी तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 85 मिनट का समय अपोजी उन के लिए दिया गया है जिसमें निर्दलिय श्री अर्जुन सिंह 9 मिनट बोले और श्री सुखबीर सिंह फरमाणा 9 मिनट बोले। भारतीय जनता पार्टी के श्री नरे 1 मलिक 20 मिनट बोलने और आप स्वयं 43 मिनट बोले यानि 43 मिनट तक आप आन लैग रहे। ठीक है, अगर आप अब बोलना चाहते हैं तो बोलिए I allow you.

श्री औम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह टाइम की भारत भी इंडियन ने नल लोकदल के सदस्यो पर ही लागू होती है क्योंकि इससे पहले तो बोलने वाले बहुत लम्बे समय तक बोलते रहे हैं। और आप भी बड़े बुलंदबाग दावे करते हैं कि पहली

मर्तबा इतने लम्बे समय तक सै ान चला है। इतने दिन का सै ान है मुख्यमंत्री जी को 17 मार्च को जवाब देना है उससे पहले तो समय ही समय है इसमे आप कंजूसी किस बात की कर रहे है। सभी को बोलने के लिए पुरा समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिए, आपको समय दिया जाता है किसी प्रकार की कंजूसी नहीं है।

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, भुक् है कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चाए चल रही है। गवर्नर के अभिभाषण को पढने से ऐसा जाहिर हो रहा है कि यह बिंल्कुल नीरस अभिभाषण था, कोई किसी प्रकार की कही न कोई रिलीफ दिया गया है और न कोई आगे के लिए व्यवस्था है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें आप पहले भी कह चुके है फिर इनको दोहराने की क्या जरूरत है?

श्री औम प्रका ा चौटाला: मैने क्या कहा, क्या नह कहा यह मेरा काम है। वह तो आपने कह दिया था कि रिकार्ड न किया जाये।

श्री अध्यक्ष: वह आपका रिकार्ड में है।

श्री औम प्रका ा चौटाला: रिकार्ड मे है या नही वह तो रिकार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। मेरा कहने का भाव यह था

कि गवर्नर के अभिभाषण मे एक बात पर बडा जोर दिया गया है जो विशेष रूप से मै समझता हूं कि विधान सभा के दायरे क्षेत्र मे थी ही नहीं लेकिन केन्द्र की कर्जा माफी घोशणा को बहुत प्रचारित किया गया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसका लाभ किन किन लोगों को मिला? इसमें कई किस्म की भारते लगाई गई है। छोटे बडे किसानो का हवाला भी उसमे दिया गया है, जो डिफाल्टर है उनका क्या होगा, इन सब बातो की क्लैरिफिके ान नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि अर्थ शास्त्रियो की तरफ से भी ब्यान आये है कि इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा मै उस बहस मे नहीं जाना चाहूंगा लेकिन उसमे मुतजात किस्म के ब्यान आये है। गवर्नर के अभिभाषण के पेज 5 पर पैरा 9 मे जिक आया है कि सहकारी बैंको के 451 करोड रुपये के लोन के ब्याज माफ हुए है जबकि मुख्यमंत्री जी का ब्यान छपा है कि 830 करोड रुपये के ब्याज माफ हुए है। मुख्यमंत्री जी का दूसरा ब्यान छपा है कि 800 करोड रुपये के ब्याज माफ हुए है।

श्री अध्यक्ष: इस पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने क्लैरिफिके ान दे दी थी कि माफी की योजना में 830 करोड रुपये आये हे।

श्री औम प्रकाश चौटाला: आपको इसमे क्या आपत्ति है? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी देंगे। जब वे जवाब देंगे तो इस बार को क्लीयर कर देंगे लेकिन जो चर्चा आई है तो उसका जिक तो मै करुंगा। उसका जिक करना मेरा अधिकार है। यह

बात समझ नहीं आ रही है कि इनमें से कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है? मुख्यमंत्री जी के भी दो मुख्तलिक ब्यान आये हैं। एक ब्यान में उन्होंने कहा कि 830 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए हैं और दूसरे में कहा कि 800 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का ब्यान आया कि केन्द्र के फैसले से 10-11 लाख किसानों को लाभ मिलेगा जबकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3 लाख 7 हजार किसान लाभांवित होंगे। (तोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (तोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला फिर से भुरु हो गया तो कैसे काम चलेगा? यह तो तय किया जाये कि किस बात का प्वायंट आफ आर्डर है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: आप सुनेंगे तो ही पता चलेगा कि किस बात का प्वायंट आफ आर्डर है वैसे कैसे पता चलेगा आपको?

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार को उसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर कोई गलत ब्यान करता है तो उसमें लिखा जाए।

श्री रणबीर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अगर हाउस को बरगलाया जायेगा, कोई सदन को गुमराह करने की कोशिश करेगा तो हमारा यह अधिकार है कि हम सही तथ्य सदन के सामने रखें, सच को सदन के सामने लाये उसमें चाहे चौटाला जी हो या कोई और माननीय सदस्य हो। सदन में कोई सम्मानित सदस्य गैर जिम्मेदाराना बात करेगा तो सरकार को तो तथ्य रखने ही पड़ेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि यह बात उस दिन भी आई थी और चौटाला जी ने आज फिर भुल कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि 830 करोड़ रुपये की माफी दी गई है। उसमें से जो राशि गवर्नर के अभिभाषण के अंदर दी गई है यह वह राशि है जो लाभ तब तक ले चुके हैं और वित्त मंत्री जी ने खडे होकर यह बात कही थी। मुख्यमंत्री जी को कोट करके बार बार इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इन्होंने कहा कि 11 लाख लोगों को लाभ होगा और कभी कहते हैं कि 3 लाख 20 हजार लोन पात्र है। अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक फैसला भारत की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लिया। 4 करोड़ किसान हैं जिनको पूरे देश के अंदर 60 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी का लाभ होने वाला है। ऐसा न आज

तक हिन्दुस्तान के इतिहास मे हुआ और न कोई सरकार कर पाई। इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय अपने आप मे एक बहुत साहसिक कदम था। उन 4 करोड मे हरियाण के कितने लोगो को कर्जो का लीगा होगा वह सरकार की केवल अनुमानित फिगर थी कि तकरीबन 4 से 5 हजार करोड भायद हरियाणा प्रदे 1 का भी होगा। स्पीकर सर, अभी यह फिगर हम कैलकुलेट कर रहे है। सच बात तो यह है कि कई दल ऐसे है जिनसे यह बात न निगले बनती है न उगले बनती है। इसके लिए वे न तो सरकार की तारीफ कर पा रहे है और न वे उसकी आलोचना कर पा रहे है। वे इसको किसी सर्कूटियस तरीके से घुमा कर प्र न चिन्ह पैदा करने का प्रयास कर रहे है। अध्यक्ष महोदय, none less than the Prime Minister of the country has said on the floor of the Parliament that by 30th June, 2008 साठ के साठ करोड रुपये के ऋण माफी का लाभ हिन्दुस्तान के किसान को मिलने वाला है। 30 जून, 2008 तक इन्तजार कीजिए जो तथ्य और आंकडे है वे सबके सामने है। अध्यक्ष महोदय, मै इनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम खडे होकर इसकी तारीफ तो करें 1600 करोड रुपये की जो बिजली बिलो की ऋण माफी की थी उसमे से 1 हजार करोड रुपये का लाभ बिजली उपभोक्ताओ को पहुंच चुका है। अध्यक्ष महोदय, लोक दल के साथियो की यह मानसिकता बन गई है कि खुद तो कुछ करना नही और जब कोई दूसरा कुछ करेगा तो उसके अंदर मीन मेख निकालने का प्रयास करेंगे। आज चौटाला साहब भी यही कर रहे है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मै इनसे यह

कहना चाहता हूं कि जोर से बोल कर ये इस बात को झुठला नहीं सकते हैं।

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा प्वायंट आफ आर्डर की आड लेकर इनको भाषण झाडने की जरूरत नहीं है। मेरा एक अधिकार है और मैं उसी अधिकार से अपनी बात कह रहा हूं। अगर मैं कोई गलत ब्यानी करता हूं या सरकार को कोई सुझाव देता हूं तो उसका जवाब रिप्लाई में लीडर आफ दी हाउस देंगे और उसमें सारी बात क्लीयर हो जाएगी। अगर एक एक बात को लेकर बीच में इस प्रकार की डिस्टर्बेंस की जाएगी तो फिर समय बर्बाद होगा। (विध्न) फिर आपकी सोच भी ऐसी है कि फिर उसके मिनट दर्ज करते चले जाएंगे। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप कांटीन्यू करें (विध्न)
चौटाला साहब, आप भी भाषण न दें और कानटीन्यू करें

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह क्या है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है लेकिन जो आंकड़े हैं वे लोगों के सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार की चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं उन चिंताओं के दृष्टीगत ही मैं भी अपनी चिंता प्रकट करता हूँ कि अभी यह क्लीयर नहीं है कि कितना कर्ज माफ हुआ है। उसमें छोटे और बड़े किसान का भी हवाला दिया गया है। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि यह सबसे पहला अवसर

है कि इस प्रकार का लाभ किसानों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने दस हजार रुपये तक के कर्ज जो हर किसान के ऊपर चढ़े हुए थे वे माफ किये थे। उसमें किसी भी छोटे या बड़े किसान की कोई बात नहीं थी। उस दस हजार रुपये तक के कर्ज माफ होने में वित्तीय संस्थान थे। सहकारी बैंकों के भी कर्ज थे और दूसरे बैंकों के भी कर्ज थे। वे दस हजार रुपये तक माफ हुए थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने थोड़ा सा रवैया बलदा है, यह बहुत अच्छा है। यह परम्परा बहुत अच्छी है और मैं इसकी सराहना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब यह ऐटीच्यूड की बात है। अगर आप खुद बदल गये हो तो आपको सब बदला हुआ नजर आ रहा है। (विधन)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि 13 मार्च, 1992 को श्री पी वी नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री थे और केन्द्र में उनकी सरकार थी। उस वक्त इस सदन में एक सम्मानित सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है और आपकी कलम के नीचे आए हुए हैं। आप उनके बारे में क्या निर्णय लेते हैं यह तो आपका फैसला है। श्री धर्मपाल मलिक जी ने उस वक्त एक सवाल पूछा था कि कितने कर्ज माफ हुए हैं तो उसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह जी का बयान आया कि इस में केन्द्र सरकार पर कुल 7714

करोड रुपये का सीधा भार पड़ेगा और 4400 करोड रुपये का अतिरिक्त भार प्रदेश सरकारों पर है। कुल मिला कर 16514 करोड रुपये के कर्जा उस वक्त माफ हुए थे और उसमें कोई if-but या किंतु परंतु नहीं था केवल एक सोच थी कि गरीब किसान को राहत मिल सके इस बात को दुश्टीगत रखकर यह निर्णय लिया गया था।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, ये तो चौधरी सम्पत सिंह जी का ब्यान था।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रिकार्ड की बात कर रहा हूँ और पार्लियामेंट में जो जिक्र आया है मैं उसका जिक्र करता हूँ। उस वक्त के रुपये की और इस वक्त के रुपये की अगर वैल्यू आंकी जाए तो वह जो पैसा था वह 16514 करोड रुपये बनता है जिनके कर्जे माफ हुए थे वे एक लाख 32 हजार करोड रुपये बनते हैं। (विघ्न) आज की तारीख में वह एक लाख 32 हजार करोड बनता है। कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था गुप्ता जी। कांग्रेस की सरकार बाद में 1991 में बनी थी और उस वक्त के वित्त राज्य मंत्री दलबीर सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था। यह जो कर्जा था वह उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल जी ने माफ किया था। (गौर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, हमारे पास आंकड़े हैं और वे यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में कर्जा माफ करने की स्कीम आई थी तो उस समय केवल 32 करोड़ रुपये ही माफ किए गए थे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि जिम्मेवारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा में दिए ब्यान आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। मंत्री जी सरकारी आंकड़ों की अनदेखी करके भी गलत ब्यानी करना मुनासिब नहीं है, मैं यह सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। यह उस वक्त के रिकार्ड की चीज है और मैं यह वित्त मंत्री जी का जवाब बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसका क्या लाभ होगा और किसको होगा यह तो समय ही बताएगा। चौधरी देवी लाल जी ने उस वक्त कोई राजनीतिक लाभ उठाने की चेश्टा नहीं की थी। उनकी ईमानदारी से यह मंता थी कि इस प्रदेश का कृषक सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए थे। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय हैं उनके कर्जे माफ हो यह बहुत अच्छी बात है अगर टोटल कर्जे माफ होंगे तो आगे के लिए किसानों की सोच कैसे ठीक हो इसके लिए सरकार की तरफ से गठित स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए तो सभी को लाभ मिलेगा, पूरे देश को लाभ

पहुंचेगा। आज केन्द्र की सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बात है तो केवल सोच का अंतर है। उस सोच के अन्तर्गत अगर किसानों को लाभ दिया जाए और आगे के लिए किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि उनको भविष्य में कर्जा न लेना पड़े। आज अभी कुछ मैम्बर्ज ने भी जिक्र किया है कि इस साल न तो किसानों को बिजली मिली है न ही पानी मिला है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे कि जब से भाखडा नहर बनी है तब से लेकर भाखडा का क्लोजर चौथे महीने में याह 10वें महीने में होता था और फुसर्त का समय देखकर उसकी मरम्मत की जाती थी। लेकिन इस साल 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक क्लोजर हुआ है। उसकी वजह से किसानों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। वह ऐसा पीरियड है, जिसमें किसानों की फसल पूरी तरह से पकती है। अध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान हैं, आपको इन सारे हालात का ज्ञान है। पता नहीं किस सोच के चलते हुए इस समय क्लोजर कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, किसान को इस बार ठंड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जैसा कि सोमवीर सिंह जी ने बताया है कि सरसों और जौ की फसल का नुकसान हुआ है बलिक कनक की फसल का भी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह जो ठण्ड पडी थी यह सुखी ठण्ड थी और इसकी वजह से कनक में पूरी तरह से फूटारा नहीं आ पाया था। अब जो एकलखत गर्मी आ गई है इसकी वजह से वह वही पर सूख जाएगी। इसकी वजह से कनक की फसल का बुरी तरह से नुकसान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय,

इस सरकार को चाहिए कि जहां पर ये जो इतनी फिराखदिली दिखा रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में हमारा माना है कि ये उसका राजनीतिक लाभ उठाएं लेकिन उसका किसानों को लाभ तो मिलना चाहिए। यह जो ठण्ड की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है उसके लिए भी सरकार निर्धारित मुआवजा किसानों को दे ताकि प्रदेश का किसान सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल हो सके। अगर हमारा किसान सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल होगा तो वह हॉर्सले से ज्यादा पैदावार बढाएगा। इसकी वजह से हमारी सरकार की जो सोच विदेशों से गेहूं खरीदने की है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था स्थापित की जाए तो इस देश के गोदाम पहले भी किसानों ने ठसाठस भरने की कोशिश की थी, इस बार पुनः गोदाम भर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार के वक्त में ऐसी स्थिति आ गई थी कि कहीं सरकारी गोदामों से गेहूं समुन्द्र में न फेंकना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसलिए फूड फार वर्क के तहत गांव गांव में गेहूं भेजा गया था ताकि उसका सही उपयोग हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हालात यह हो गए हैं कि हम यह बात तो करते हैं कि हमने किसानों को बड़े भारी भाव दिए हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि किसानों की लागत के दाम किस रेटों से बढ़ रहे हैं। खाद के दाम, बिजली के दाम, डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम किस रेटों से बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बनने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 6 बर्तबा बढ़े हैं यानि कि किसानों की

लागत का मूल्य बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की जो लागत है उस पर 50 प्रतिशत और पैसा देकर किसानों को लाभ दिया जाए। इस किस्म की सोच सरकार की होनी चाहिए, लेकिन यह सोच नहीं है। सरकार की सोच तो केवल राजनैतिक लाभ उठाने की है। अगर ये राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उठाए लेकिन यह पिक्चर भी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। इनके साथ ही वही होगा जो दूसरी सरकारों के साथ पहले होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यहाँ पर सिंचाई की बात आई और यह जिक्र किया गया था कि नहरों में पानी की दिक्कत आ रही है और प्रस्तावक ने यहाँ तक भी जिक्र किया था कि एस वाई एल नहर पर बहुत काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एस वाई एल नहर तो हमारी जीवन रेखा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका बहुत मामूली जिक्र आया है कि सरकार यह नहर बनाएगी जबकि एस वाई एल नहर के प्रति किसी भी अदालत में कोई फैसला विचाराधीन नहीं है। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है कि वह इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाए। आज हरियाणा में और केन्द्र के स्तर पर कांग्रेस की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि इस नहर को केन्द्र की सरकार बनाए। इस प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्षता तीन मर्तबा आयी और तीनों मर्तबा न मुख्यमंत्री की ओर न और न किसी ओर की तरफ से एस वाई एल नहर का जिक्र किया गया। इसके अलावा जब मुख्यमंत्रियों की एक कान्फ्रेंस चण्डीगढ़ के हुई

थी तो वह एक बहुत अहम मौका था लेकिन उस वक्त भी इस अहम मुद्दे पर किसी ने इस नहर का जिक्र नहीं किया।

Mr Speaker: Chaudhary Sahib, presidential reference is pending before the Supreme Court. जो फ़ैक्चुअल पोर्जी उन हैं आप उस पर बोलें।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए एस वाई एल नहर से संबंधित कोई भी फ़ैसला अदालत के विचाराधीन नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, फ़ैक्चुअली दो बातें हैं, जो चौधरी औम प्रकाश चौटाला साहब गलत कह रहे हैं। एस वाई एल नहर के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार ने जो मुकदमा दायर किया था और उस मुकदमे का हमारे हम के जो फ़ैसला हुआ था। उसके बाद पंजाब की विधान सभा जिसमें इनके मित्र भी शामिल थे और जिसमें कांग्रेस की उस समय की सरकार भी शामिल थी, ने मिलकर एक ऐसा कानून पारित किया था जिसका उनको अधिकार नहीं था।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप यह बताएं कि क्या हरियाणा सरकार ने इसको चैलेंज किया था?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, उस समय की हरियाणा सरकार जिसके मुखिया औम प्रकाश चौटाला जी थे, ने यह जहमत नहीं की कि वह हरियाणा के अधिकारों की सुरक्षा करे

और उस गैर कानूनी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे। परंतु उसके बावजूद हमारी सरकार आने के बाद हमने भारत सरकार को कहा। हालांकि भारत सरकार दो प्रांतों के विवाद में तटस्थ रहती है लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके पंजाब विधान सभा द्वारा पारित कानून की वैधता को प्रैजिडेंटियल रैफरेंस के तहत भेज दिया और अब अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक खण्डपीठ का निर्णय इस बारे में जल्दी आने वाला है। कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार इस मामले की पैरवी करते रहते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वह फैसला हमारे हक में ही आएगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय औम प्रकाश चौटाला जी ने एक और तथ्यों के विपरीत गलत बात कही है। इन्होंने कहा है कि खेतीबाड़ी के दाम बहुत बढ़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इन बातों की रिप्लाय बाद में दे देना। अब तो ये कह रहे हैं कि *it is not a subjudice matter.* You are saying it is a subjudice matter. Presidential reference is still pending before the Bench of the Supreme Court. This is the factual position.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर सर, औम प्रकाश चौटाला जी ने जो यह कहा है कि एस वाई एल नहर को लेकर कोई मामला अदालत में पेंडिंग नहीं है मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में प्रैजिडेंटियल रैफरेंस हमारी यू पी ए की सरकार ने प्रैजिडेंट से आग्रह करके करवाया है

और आज इस बारे में एक कांस्टीच्यूशनल बैंच कांस्टीच्यूट हो चुकी है। इसकी आगामी हीयरिंग की डेट 12 अप्रैल, 2008 है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आर्न रिकार्ड कह सकता हूँ कि हम भी उस समय विपक्ष में बैठते थे, उस समय औम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। उस समय हमने औम प्रकाश चौटाला जी से अनुरोध किया था कि आपको भी इस मामले में पार्टी बनानी चाहिए और जो हरियाणा का अहित हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ न कुछ जरूर चेलेंज करना चाहिए लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब से चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आयी है तब से हमने इस मामले में बैस्ट लॉयर इम्प्लाय कर रखे हैं। कांस्टीच्यूशनल बैंच में इस मामले की हीयरिंग की पैरवी नहीं की जबकि मोजुदा सरकार इस मामले की पैरवी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बी एम एल हांसी बुटाना लिंक नहर को लेकर भी बाधाएं डालने की कोशिश की गयी इस नहर को लेकर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 16 लोगों के द्वारा पैटीशन डलवायी गयी जिसको कोर्ट ने डिस्मिस कर दिया था और यह कहा कि इस तरह की पैटीशन आम किसान नहीं डाल सकता। यह पैटीशन कुछ ऐसी ताकतों ने डलवायी है जो यह नहीं चाहती हैं कि हरियाणा के किसानों को पानी मिले। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने जानबूझकर यह पैटीशन डलवायी थी। हाई कोर्ट ने इस बारे में स्ट्रीक्चर भी पास किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात हरियाणा के सब लोग जानते हैं कि कौन लोग नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में पानी का इक्विल डिस्ट्रिब्यूशन हो।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले जरा और स्पष्ट कर दूँ कि एस वाई एल कैनाल की कंस्ट्रक्शन का कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन नहीं है। सिर्फ केन्द्रीय सरकार द्वारा The Punjab Termination of Agreement Act, 2004 का राष्ट्रपति जी की मारफत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के लिए reference सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने मांगा है कि आप बताइए कि इस पर क्या विचार है? कैप्टन साहब, आपने तो इस पर दो बार रुकावट डाली है और इस बात के बारे में तारीख लेने की चेश्टा की कि पंजाब में डेरा सच्चा सौदा का विवाद है इसलिए इस मामले को आगे लम्बा लटकाया जाए। आपके जो अटार्नी जनरल केन्द्र सरकार के हैं उन्होंने यह दर्खास्त दी है कि चूंकि पंजाब में और हरियाणा में डेरा सच्चरा सौदा विवाद है। इसलिए अगली तारीख दी जाए। मैं तो यह मानता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा विवाद का इस पानी के मामले से कोई संबंध ही नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी चौटाला साहब कह रहे हैं। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। डेरा सच्चा सौदा वाली इस प्रकार की कोई बात रिकार्ड पर हो तो ये कहे। इनको यहां ये भी पढ़ना चाहिए। One must not either enter an Assembly Hall or he must speak there with all the righteousness, for one who does not speak or one who speaks falsely does involve himself in the equal sin. ये यहां पर लिखा हुआ है इसको ये पढ़ ले और उसके बाद ही कोई बात कहें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप जवाब दे रहे हैं you are giving certain other facts and the Hon'ble Member is giving another facts. अगर कुछ रौंग है तो breach of privilege का मोान आने दो। हाउस को गुमराह करने का प्रस्ताव लाया जाए। किसी को अधिकार नहीं है। No member has the authority on the floor of the House. कि कोई गलत ब्यानबाजी करें कोई भी गलत ब्यानबाजी करता है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं ऑन आर्थ यह बात कह रहा हूँ। केन्द्र के अटार्नी जनरल श्री बनर्जी ने यह लिखित में दिया है। उसे मंगवाकर देख लिया जाए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोानद गयर किया जाए लेकिन अगर कोई मंत्री गलत ब्यानबाजी करता है तो उसके खिलाफ भी प्रिविलेज मोान लाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह तो मैं कह ही रहा हूँ।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो उसको डिले करने की चेश्टा की है। एस वाई एल कैनाल की कंस्ट्रक्शन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही साथ मंत्री जी ने जिक्र किया कि यहां यमुना अकाउंट का मामला आया था उस वक्त हम अपोजी मोान में थे और हमने इस मुद्दे पर इस्तीफे दिये थे। फैसला हुआ था कि किसान, रेणुका और लखवार डैम जब बनेंगे तो उसके ऐवज में हरियाणा को

उसके हिस्से का पानी मिलेगा। सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास नहीं किए हैं। यह किसका जिम्मा है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जिस मुख्यमंत्री को बदनाम करने की बात सोची गई थी उस कैबिनेट में ये खुद सिंचाई मंत्री थे, एस चौधरी भी मंत्री थे, गुप्ता जी भी मंत्री थे और बहुत से लोग थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यमुना वाटर अकॉर्ड के बारे में इस समय हाउस की कमेटी बनी हुई है। It was discussed in the previous House. जिसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों का पानी के बंटवारे के बारे में इंटरस्ट अफैक्ट हुआ है, वाटर का जो भोयर था वह अफैक्ट हुआ है keeping in view the sense of the House. उस समय एक कमेटी बनी थी उस समय इनदौरा साहब भी हाउस में बैठे थे। इस बारे में कमेटी बनी थी Now, the matter is under consideration of the Committee. लेकिन उसकी तीनों मीटिंग्स में आपकी पार्टी का मैम्बर नहीं आया।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने तो उस मुद्दे पर विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफे तक दिये हुए हैं तो उस मीटिंग के हम कैसे आ सकते हैं? हम तो उस समझौते को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।

श्री अध्यक्ष: आप चाहे और लिख कर दें तो श्रीमती रेखा राणा की जगह उसमें आपकी पार्टी के किसी और मैम्बर को उस कमेटी का मैम्बर बना दें।

श्री औम प्रकाश चौटाला: हम तो इस फैसले का भुरु से ही विरोध करते आए हैं। जब से इस कमेटी को बनाने की बात चली थी तो यह किसी पुराने मुख्यमंत्री को बदनाम करने की चेश्टा की गई थी। वैसे मैं इन मामले में जाना नहीं चाहता क्योंकि यह आपकी पार्टी का मामला है। उनकी कैबिनेट में तो कैप्टन साहब भी थे और मांगे राम गुप्ता जी और ए सी चौधरी व अन्य कई लोग थे तो उसमें अकेला भजन लाल कैसे दोषी हुआ?

श्री अध्यक्ष: किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे बदनाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों का न्याय था वह काट दिया अब आप बताये कि बदनाम होना चाहिए या नहीं

श्री औम प्रकाश चौटाला: होना चाहिए लेकिन जो प्रस्तावक थे उनको भी तो त्याग-पत्र देना चाहिए जो इस बात के लिए उकसाते थे, मांगे राम गुप्ता और ए सी चौधरी को भी इस्तीफा देना चाहिए था, उनको भी त्याग पत्र देना चाहिए था अकेले भजन लाल को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, पंजाब की विधान सभा ने यूनानीमैसली एस वाई एल नहर के बारे में रेजोल्यूशन पास किया था उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी औम प्रकाश चौटाला थे। हम विपक्ष में बैठते थे। हमने उनको यह प्रस्ताव लाने के लिए कहा कि हम भी इसी

प्रकार का प्रस्ताव यूनानीमैसली लायें। हरियाणा के 90 के 90 एम एल ए इस हाउस में बैठे हैं चाहे कोई एम एल ए किसी भी पार्टी का हो हम सभी अपना त्याग पत्र देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करें कि हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतना अन्याय हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस्तीफा देकर जा रहे हैं। उस समय चौधरी और प्रकाश चौटाला जी तैयार नहीं हुए? हमने तो 90 के 90 एम एल ए के लिए कहा था उस समय इन्होंने उस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, जब इनहोंने इस्तीफा दिया था उस समय असेम्बली का केवल एक महीना बाकी रहा था।

श्री और प्रकाश चौटाला: मांगे राम गुप्ता जी तो हमारे को उंगली लगाकर बीच में सरक गये।

श्री मांगे राम गुप्ता: आपको तो जनता ने हरा दिया आपने इस्तीफा नहीं दिया जनता ने आपको ठुकरा दिया।

श्री और प्रकाश चौटाला: मांगे राम गुप्ता जी यह तो रिकार्ड की बात है जब यमुना एकाई हुआ उस वक्त की बात है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी और प्रकाश चौटाला जी से यह पूछा जाए कि यमुना एकाई कब हुआ था और इन्होंने इस्तीफा कब दिया था और विधान सभा का कार्यकाल उस समय कितना बचा हुआ था?

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वह केवल मात्र लीपापोती है।

श्री अध्यक्ष: यह कमेटी तो हाउस की सैंस से सर्वसम्मति से बनाई गई है अगर हाउस ही इस बात के लिए लीपापोती करना चाहता है then you are also part of the House. आप उस कमेटी की मीटिंग में कभी नहीं आये।

श्री औम प्रकाश चौटाला: *****

श्री अध्यक्ष: ये भाब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिये जायें। It is wrong to suggest there things. (Interruptions) Nothing is to be recorded whatever has been said by Shri Om Parkash Chautala without giving my permission. (Interruptions) Mr Chautala, you may please address to the Chair.

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि सदन के किसी सदस्य ने यह कहा था क्योंकि निश्चित रूप से यह बात रिकार्ड में भी रही होगी कि अगर इस पानी का बंटवारा हो गया तो महायुद्ध हो जाएगा। दो महायुद्ध तो मैंने सुने हैं मगर यह तीसरा महायुद्ध किस बात को लेकर हो जायेगा?

संसदीय सचिव (कुमारी भारदा राठौर): माननीय स्पीकर सर, हाउस के माननीय सदस्य के बड़े सुपुत्र श्री अजय चौटाला का ब्यान आया था कि अगर इस पानी का समान बंटवारा हो जाएगा तो प्रदेश में गृह युद्ध हो जायेगा।

श्री औम प्रका १ चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वह कभी इस सदन का सदस्य नहीं रहा।

कुमारी भारदा राठौर: माननीय स्पीकर सर, मैंने यह कहा है कि इस हाउस के माननीय सदस्य के बड़े पुत्र ने ऐसा कहा है।

श्री औम प्रका १ चौटाला: आपने यह कहा है कि सदन के सदस्य ने कहा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, भारदा राठौर जी ने यह बात कही है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री औम प्रका १ चौटाला जी के बेटे ने यह ब्यान दिया था। आप इनसे यह पूछ लें कि माननीय चौटाला जी हांसी बुटाना नहर के बनने के हक में है या नहीं?

श्री औम प्रका १ चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं on the floor of the House. इस बात का पक्षधर हूँ कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के खेत की सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जितनी नहरे बनें, हम उसके लिए तैयार हैं इसके लिए अगर हमें उस नहर की खुदाई के लिए खुद जाकर कस्सी चलानी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: आपसे माननीय मंत्री जी ने एक स्पैसिफिक क्वै चन पूछा है। आप उसका उत्तर बतायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: मैंने यह पूछा है कि आप इस नहर के बनने के पक्षधर हैं या नहीं

श्री औम प्रकाश चौटाला: हम इस बात के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार यह स्पष्ट करें कि हांसी बुटाना लिंक नहर के लिए पानी कहां से आयेगा क्योंकि एस वाई एल नहर के सवाल पर सरकार की तरफ से कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है। किसान, रेणुका, और लखवार डैम पर सरकार तवज्जोह का दावा कर रही है। मुझे सरकार यह बताए कि उस नहर में पानी कहां से आएगा? सरकार जो नहर बना रही है उसको पंचर करने की क्या कोई व्यवस्था है? जब जब रियासतो का कही भी डिस्प्यूट होता है तो उस पर सी डब्ल्यू सी फैसला करती है या फिर यह फैसला अदालत के लिए विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बताएं कि क्या पोजीशन है?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको क्लैरीफाई करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि क्या दो स्टेट्स का मामला है या नहीं Central Water Commission has already cleared the project from inter-State remification, Design, cost-aspect, irrigation planning and hydrological aspect. The Minister of Agriculture, Ground Water Board and the Minister of Environment and Forest has also cleared the project. हाल ही में कल 11 मार्च को सी डब्ल्यू सी की मीटिंग में

हमने ये फैक्ट्स दिये थे। पंजाब का यह कहना था कि एक तो फलड्स आएंगे तो हमने कहा कि जो भी स्ट्रक्चर पंजाब के लोग कहेंगे, हम उसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। दूसरी उनको एप्रीहेंशन थी कि हमारे हिस्से का पानी इसमें चला जाएगा। जिस प्वायंट से हम पंपकर कर रहे हैं उस प्वायंट पर 85 परसेंट भोयर हरियाणा का है, 5 परसेंट भोयर पंजाब का है और 10 परसेंट भोयर राजस्थान का है। हमने एफीडैविट में यह दिया है कि जहां से पंपकर करेंगे उसका कंट्रोल भी हम बी बी एम बी को देंगे और हमारी वह बात सी डब्ल्यू सी ने मान ली है। अजीमगढ़ से पंपकर होगा, यह हमने बता दिया है। कल भी मैंने एक बात कही थी। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये नहर बने लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट के अंदर इनके कई साथी जिन्होंने पैटीशन डाली हुई है।

श्री अध्यक्ष: यह जो 85 परसेंट वाटर भोयर है हरियाणा का है वह किसका भोयर है और हरियाणा के कौन से पार्ट का भोयर है और यह पानी कहां चल रहा है

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि यह पानी साउदर्न हरियाणा का है इससे एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं बल्कि 16 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात जो इनहोंने कही कि हम इसके पक्ष में हैं, यह बात स्पष्ट है कि इनके ही साथी रामपाल माजरा जी जो पहले इरीगेेशन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा और कैथल के एरिया के लोगों की तरफ से 16 पैटीशन हाई कोर्ट में डलवाई गईं और 16

की 16 पैटी इन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। जब हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी तो यह कहा था कि ये इनोसैंट फार्मर्स का काम नहीं है and all these 16 petitions filed in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court were dismissed. There is a judgement in C.W.P no. 19676 of 2005 and it is written therein that-

“Before parting, we, however, feel that it is important to unmask the petitioners, who have donned the cloak of public interest to raise such issues, which have only laid bare the fangs which do not belong to the innocent face of a farmer, but to someone else; and the petitioner, especially C.W.P No. 19676 of 2005 are a result of an ingenious mind with a purpose other than a public purpose. When viewed from the prism of the tests laid down by the Apex Court for a public interest litigation, we find the essential colours missing the spectrum.”

अध्यक्ष महोदय, ये स्ट्रिक्चर्स हैं। ये जो काम है यह इनोसैंट फेस का नहीं है इनके पीछे कोई ऐसी ताकत लगी हुई है तो यह काम पूरा नहीं होने देना चाहती जिस वजह से कोर्ट ने यह बात अपनी जजमेंट में कही है। 5 एस एल पी सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है जो डिसमिस हो गई है। 2 पैटी इन अभी चल रही है जो पंजाब और राजस्थान ने डाल रखी है। इस प्रकार हमारी जितनी भी बातें हैं वे सारी सी डब्ल्यू सी ने मान ली है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा कि पानी कहां से लाएंगे, आपने कहा साउदर्न हरियाणा का पानी है तो आप बताएं कि यह

पानी साउदर्न हरियाणा का किस एग्रीमेंट के तहत है ओर कैसे चल रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं जिस समय एस वाई एल कैनल का एग्रीमेंट हुआ था उस समय पंजाब सरकार को पैसा दिया गया था और उस वक्त कहा गया था कि एस वाई एल कैनल और भाखडा का जो पानी आयेगा वह महेन्द्रग्रढ, झज्जर ओर गुडगांव आदि जिलो को दिया जायेगा। इसके लिए पाकिस्तान को भी करोडो रुपये दिये गये थे। पिछल सरकार ने एस वाई एल का पानी लेने की कोई कोर्ि । । नही की। हमारी सरकार पानी का बराबर बंटवारा करना चाह रही है। केवल दक्षिणी हरियाणा की बात नही है बल्कि 16 जिलो को इस नहर से फायदा होगा जिसमे कैथल, झज्जर, जींद जिले भी भाामिल है। अध्यक्ष महोदय, सी डब्ल्यू सी ने हमारी कटैं । न को माना है और अपनी रिपोर्ट मे उन्होने हमारी बात को माना है। विपक्ष के साथियो का कहना है कि हमने कही से कोई परमि । न नही ली, बिल्कुल गलत बात है। हमने हर स्तर पर परमि । न ले रखी है। 29 अप्रैल की तारीख लगी हुई है उसमे हमें जरुर न्याय मिलेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मै भी एक बात कहना चाहता हूं। अगर चौटाला जी बोलना भुरु कर देंगे तो वे कहेंगे कि मै बीच में इन्ट्रुप्ट कर रहा हूं इसलिए उनके बोलने से पहले ही मै बोलना चाहूंगा कि मंत्री जी ने सारी बातें बताईं

है। हमने दो प्र न स्पीकर सर, आपकी अनुमति से औम प्रका ा चौटाला जी और उनकी पार्टी से पूछे है। क्या इनके बेटे ने गोहाना के अंदर यह ब्यान नहीं दिया कि हांसी बुटाना लिंक नहर बनने से प्रदे ा मे गृह युद्ध हो जायेगा और दूसरा प्र न यह है कि क्या चौटाला जी हांसी बुटाना लिंक नहर के हक में है या नहीं? पानी लाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, हम अपने आप ले आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे ऐसे ऐसे केस है कि एक पिता के दो पुत्र है, उन दोनो पुत्रो की जमीन तक पानी पहुचाने के लिए उनके पिता ने अलग अलग रहवाहे निकाल दिए। एक की जमीन के लिए एक रजवाहा निकाल दिया और दूसरे की जमीन के लिए दूसरा रजवाहा निकाल दिया। यह काम औम प्रका ा चौटाला जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होने किया था। उस समय पूरा दक्षिणी हरियाणा और जींद, रोहतक तथा झज्जर जिले पानी के लिए प्यासे मरते रहे और इन्होने एक एक व्यक्ति के लिए रजवाहे निकाले। अब हम उन रजवाहो से पानी लेकर बाकी के हरियाणा को दे देंगे।

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै तो केवल यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हम इस बात के लिए कतई विरोधी नहीं है कि हरियाणा प्रदे ा के किसानो के खेतो की सिंचाई के लिए नहरे न बने। हम इसके पक्षधर है लेकिन सरकार दो बातें स्पष्ट करें एक तो इसके लिए पानी की व्यवस्था कहा से की जाएगी? (विघ्न) यह बताने से क्लीयर नहीं है क्योंकि आप

साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, यदि भाखडा का ही पानी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए नई नहर बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरियाणा प्रदेश की नहरों का सिस्टम ऐसा है कि किसी भी नहर का पानी किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। हमने तो ड्रेनो में भी पानी डालकर किसानों की सिंचाई कराने का काम किया था। यह जो नहर बन रही है इसके लिए पिछले गवर्नर अभिभाषण में 265 करोड़ रुपये खर्च होना था।

श्री भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, यह सवाल सदन में बार बार उठने लगा है कि पानी कहां से आएगा, असल में तो माननीय सदस्य चौधरी औम प्रकाश चौटाला और इनकी पार्टी ने कभी इस बारे में दिलचस्पी ही नहीं ली। मुझे इसमें आपकी रुलिंग चाहिए। एस वाई एल में हरियाणा प्रदेश का हिस्सा 3.85 एम ए एफ जिसमें से हम 1.7 एम ए एफ नरवाना ब्रांच से ले रहे हैं। इसलिए यह जो कैनल अब बनाई जा रही है उसमें जो रिमेण्डर वाटर जितना भी होगा वह इसमें से भी आ जायेगा। पिछले 30-40 साल से यह होने लग रहा था कि चौधरी औम प्रकाश चौटाला और इनके दूसरे साथी यह सारा पानी सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के लिए ले जा रहे थे और वहां पर इस पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लग रहे थे।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला जी सिंचाई मंत्री रहे हैं और उन्हें इस

बारे में मुझ से ज्यादा ज्ञान है। इनकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम भाखडा में से पूरा पानी नहीं ले पाये। कई मर्तबा हमारी सरकार के वकत ऐसे अवसर आये कि हमने पंजाब की गवर्नमेंट को मँटीनैस के लिए पूरे पैसे दिये और हमें उस वकत उसमे से पूरा पानी मिलता रहा है। लेकिन यह अच्छी बात है मैं एक बार फिर उस बात को दोहराता हूँ कि पानी मिले और लोगो को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो। लेकिन हम तो केवल यही जानना चाहते है कि सरकार यह बताये कि यह पानी आयेगां कहो से? अगर इसी पानी को डिस्ट्रिब्यूट करना है तो पानी को तकसीम करना है तो उसके लिए नई नहर बनाने की जरूरत नहीं थी और फिर जो अन्य नहर बनाई जा रही है उसके लिए 265 करोड का प्रोजैक्ट था। लेकिन राज्यपाल महोदय के पिछले अभिशाण में वह 350 करोड रुपए तक पहुंच गया है और जब तक यह बनकर मुकम्मल होगी हो सकता है कि यह 500-600 करोड तक पहुंच जाये। अगर इसमें पंचर की इजाजत नहीं होगी तो फिर यह 600 करोड रुपए वेस्ट हो जाएंगे। इसकी रिकवरी कहां से होगी ये दो बातें सरकार को कम से कम स्पष्ट करनी ही चाहिए? मैं सरकार की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि पानी आयेगा तो हमें उसका फायदा होगा लेकिन अगर नहीं आयेगा तो जो आंका मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप इस सवाल में हाईपोथैटीकली क्यों जाते हैं।

श्री औम प्रका । चौटाला: नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह हाईपोथैटीकली नहीं है, इसमें हरियाणा प्रदे । के मेहनतक । लोगों का पैसा लग रहा है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मंत्री जी ने on the floor of the House यह आ वासन दिया है कि इसके लिए भाखडा को पंक्चर किया जायेगा।

श्री औम प्रका । चौटाला: स्पीकर सर, उनके कहने से तो नहीं माना जा सकता क्योंकि फैसला इनके विचाराधीन नहीं है, फैसला तो अदालत के विचाराधीन है और कल को अदालत क्या फैसला करती है इसका तो किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है। अदालत जब फैसला करेगी उसके बाद ही आप इसको पंक्चर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप इसको पंक्चर करने में सहमति रखते हैं।

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ क्योंकि हरियाणा प्रदे । के हितों के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हमने इसके लिए लडाईयां भी लडी हैं। देखिए, किसान के खेत की सिंचाई के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सके हम

इसके पक्षधर है, चाहे वह रेणुका डैम हो, चाहे लाखमार डैम हो, चाहे कोई नई नहर बनाई जाये और चाहे नई डिस्ट्रिब्यूटरियां लगाई जाये, हमे इस बात से बहुत खुशी होगी कि किसान को लाभ मिला क्योंकि किसान के खेत की पैदावार मे पानी देने के लिए केवल मात्र दो ही तो साधन है एक पानी है और दूसरा बिजली का है। अब बिजली के मामले को लेकर तो समूचे प्रदेश मे कोहराम मचा हुआ है और इस बात से सभी माननीय सदस्य पूरी तरह से अवगत है। आज बिजली है ही नहीं और बिजली न होने की मार की वजह से किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। बिजली के मामले मे सरकार की तरफ से घोटाले तो जरूर किये गये लेकिन बिजली पैदा करने के साधन जुटाने का काम नहीं किया गया। मौजूदा सरकार ब्यान बडे बडे देती है कि अतीत की सरकारो की वजह से यह नुकसान हो रहा है। अतीत की सरकारो के वक्त मे तो बिजली पैदा हुई। मौजूदा सरकार यह तो बताये कि उन्होंने कौन सी ऐसी बिजली पैदा करके दी है। इन्होंने गैस बेस्ड जो फरीदाबाद मे पावर प्लांट है 1032 मैगावाट का गैस आधारित थर्मल प्लांट जिसकी मुख्यमंत्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 25 अगस्त, 2005 को आधारित ला रखी। अध्यक्ष महोदय, 31 महीने हो गये आधारित ला रखे लेकिन अब तक उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है।

श्री अध्यक्ष: यह तो अब गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आधारित ताला रखने से पहले सोचनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, यह गैस का एग्रीमेंट झज्जर में एक पब्लिक मीटिंग में हुआ था मैं भी उस मीटिंग में भागमिल था। गेल के साथ यह समझौता हुआ था कि उस समय गेल ने कहा था कि हम गैस उपलब्ध करवायेंगे लेकिन उसमें उसको गैस नहीं मिल पाई।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। आधारित ताला रखी 25 अगस्त, 2005 को लेकिन उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो फैंक्च्यूवल पोजीशन है वह मैं बताना चाहता हूँ। भायद चौटाला जी को यह मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तान में जा गैस है वह प्रांत की मलकीयत नहीं है, राज्य सरकारों की मलकीयत नहीं है। it is treated as a national assets. और उसकी एक्सप्लोरेशन के राईट्स हमारे पास सरकार की कम्पनियों के पास भी है और कुछ प्राइवेट कम्पनियों को ऑक्शन करके ऑयल ब्लाक्सय जो दिये गये हैं उनको भी गैस मिलती है। दूसरी बात है गैस की उपलब्धता और साथ साथ गैस के रेट का निर्धारण। हम सरकार से हरियाणा के लिए जो गैस मांग रहे हैं ताकि सस्ती बिजली दे सके, वह

सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पर गैस मांग रहे है उसके लिए भारत सरकार के बहुत सारे इ यू है सर। Emp[owered Group of Ministers, External Affairs Minister श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता मे बना हुआ है जो सभी कंपनियो से प्राइवेट सैक्टर और सरकारी कम्पलियो से बात करके एक रेट को नोटीफाई करेंगे। उसके बाद गैस उपलब्ध होनी भुरु होगी। अध्यक्ष महोदय, एक प्लांट ही नही हमने तो गैस बेस्ड प्लांट के और भी कई अनुबन्ध किये हैं जब गैस उपलब्ध हो जायेगी तो वे सारे प्लांटस भी हूम चालु करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात मै और तथ्यो के आधार पर क्लैरीफाई करना चाहता हूं कि हरियाणा के गठन के बाद जो केवल 1587.4 मैगावाट के कोयले पर आधारित थर्मल प्लांट हरियाणा मे लगे हुए है उनमे से अधिकतर कांग्रेस के कार्यकाल मे लगे है। इस सरकार ने पहली बार 5 हजार मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए 24 हजार करोड रुपये का निवे 1 करने का निर्णय किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार का प्लांड बजट केवल 5 हजार करोड से कम हो और आज वह सरकार 24 हजार करोड का निवे 1 केवल बिजली उत्पादन के अन्दर कर रही है। यह सारी बिजली 2009 के आखिरी 2010 के भुरु तक मिलनी भुरु हो जायेगी।

श्री औम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार की सकीयता का अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि हमारी सरका के समय मे यमुनानगर मे दीन बन्धु सर छोटूराम के नाम पर एक

थर्मल पावर प्लांट की आधार िला रखी गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक नई आधार िला तो जरूर रखी लेकिन उसके उपर 3 सालो के दौरान एक यूनिट बिजली की भी पैदावार नहीं हुई है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात तथ्यो से परे है। वहां पर मार्च, 2005 मे जब हम गये तो स्पाट मैदान पडा था। पत्थर तो इनके पिताजी ने भी रखा था लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। 12 साल तक वह इसी प्रकार पडा रहा। आखिर मे आकर चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी ने उसे भुरु किया। आज वह प्लाट इस समय बिजली प्रोडक् ान कर रहा है। उसकी पहली यूनिट 300 मैगावाट की चली हुई है और अब तक 850 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर चुका है और चौटाला जी कह रहे है कि एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हुई है। यह बात तथ्यो से परे है।

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसको क्वै चन आवर न बनायें। मै आपसे अनुरोध करुंगा कि मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री अध्यक्ष: जो फैक्चयुअल पोजी ान है वह तो पता चलनी ही चाहिए ताकि हरियाणा प्रदे ा के लोग भी इस बात को जान सके। (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप फ़ैक्ट्यूअल पोजीशन सुने तो सही, मैं फ़ैक्ट्यूअल पोजीशन आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी सरकार के वक्त उसकी आधारभूत रखी गई थीं (विधन)

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा साहब, आप ये देखें कि इस वक्त आपके लीउर बोल रहे हैं। इसलिए आप उनको सुनें। (विधन)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप यह बात दूसरे लोगों को भी बोलें।

श्री अध्यक्ष: दूसरे तो बंद ही हैं। No running commentary please.

श्री औम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि जिस कम्पनी को यह काम दिया गया था उस कम्पनी ने हमारी सरकार के वक्त एक दरखास्त दी थी कि उसे अपनी एक सहयोगी कम्पनी को बदलने की इजाजत दी जाये। वायदे के मुताबिक उस वक्त हमारी सरकार का एक निर्णय था कि जो फ़ैसला पहले लिया गया है उसको बदला नहीं जाएगा। हमने उनकी दरखास्त रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से सरकार को नुकसान होना था। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार के वक्त 13 जून, 2005 को नई सरकार बनने के बाद उस कम्पनी ने सरकार को एक दरखास्त भेजी की हमें अपनी नई कम्पनी जो डांग फोंग इलेक्ट्रिक कार्पोरेटशन है, उसकी बजाय हमें नई कम्पनी

को साईन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि वह हमें मीने सप्लाई करेगी। उस सरकार ने 13 जून, 2005 को उनकी उस दरखास्त को नामंजूर कर दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि 15 तारीख 2005 को ही उस कंपनी से एक नई दरखास्त लेकर उसको मान लिया गया और उसकी वजह से सरकार को कम से कम 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जो पैनल्टी सरकार को मिलनी चाहिए थी सरकार को उसका नुकसान हुआ। उसके बाद बड़ी जल्दबाजी में अप्रैल 2007 से पहले कम्प्रोमाईज किया जाना चाहिए था लेकिन उसके लिए सरकार ने उनको फिर अनुमति प्रदान की कि एक नवम्बर, 2007 तक उसको मुकम्मल कर दें। एक नवम्बर को बड़ी जल्दबाजी में मुख्यमंत्री जी ने उसको फायदा पहुंचाने के हिसाब से उसको कोयले से फायर करने की बजाए तेल से करवाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, चार महीने के बाद अब तक भी उस यूनिट से जो 300 मैगावाट बिजली का उत्पादन होना चाहिए था वह अब तक नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आपके मुताबिक कितना उत्पादन हो रहा है?

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह 300 मैगावाट से कम हो रहा है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले यह कहा था कि एक यूनिट बिजली का उत्पादन भी वहां से

नहीं हो रहा है। (विधन) सर, इस बारे में आप रिकार्ड निकाल कर देख सकते हैं कि इनकी कौन सी बात सच है?

श्री औम प्रकाश चौटाला: वह कम्पि रियल के हिसाब से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसकी वजह से उस कम्पनी पर जुर्माना लगना चाहिए था। उस जुर्माने से छूट देने का काम भी इस सरकार ने किया जिसकी वजह से स्टेट को कम से कम 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी के दृष्टीगत इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में एक निर्णय लिया। उस कैबिनेट मीटिंग में भायद चटठा साहब भी उस वक्त मंत्री थे, उस वक्त एक फैसला हुआ था कि क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बिजली की कमी है, उस बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में एक ऐसी कम्पनी जो किसी कांग्रेसी सांसद के भाई की कंपनी है उससे बिजली का एग्रीमेंट किया गया और 13450 करोड़ रुपये का यह सौदा किया गया। स्पीकर सर, होना तो यह चाहिए था कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता लेकिन उस कंपनी का उत्पादन 2009 में होना है। कैबिनेट मीटिंग की अप्रूवल के बाद चूंकि बिजली की कमी है इसलिए उसको जल्दी से जल्दी लेने के लिए एग्रीमेंट करके उनको पैसा दिया गया। वह कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार को एक रुपये 90 पैसे में प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की पेशकश करती है। (विधन) वही दूसरी तरफ हमारी सरकार ने उससे एग्रीमेंट किया था कि वह पौने तीन रुपये प्रति

यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। स्पीकर सर, इसकी वजह से कितना बडा घोटाला हुआ है, इस घोटाले के लिए कौन दोशी है यह तो समय आने पर अपने आप तय होगा लेकिन यहां पर बिजली की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। स्पीकर सर, आज िालान्यास तो रखे जा रहे है, यह बहुत अच्छी बात है। झाडली मे जिस रोज आधार िाला रखी उसके बाद तो बिजली की कही झड गई और लोगों को कही दिखाई नहीं दे रही है। लोग त्राहि त्राहि कर रहे है कि बिजली कहा चली गई है। ये लोग कहते है कि 4.5 हजार मैगावाट बिजली पैदा करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। बिजली आज हर आदमी की नसैस्टी है, उद्योग की धुरी है। किसान को बिजली चाहिए, व्यापारी को बिजली चाहिए लेकिन बिजली कहां है, सरकार बिजली का उत्पादन करके बताए तो अच्छी बात होगी। अभी ये कह रहे है कि प्रोडक् ान बढ गया है लेकिन वह बिजली है कहा। हरियाणा प्रदे ा मे तो बिजली है नहीं। यह बिजली कहां जा रही है यह अभी भी समझ मे नहीं आ रहा है। लोग हमसे पूछते है कि हमारी सरकार के वक्त में बिजली कहां से आती थी यह बात तो लोगों को इनसे पूछनी चाहिए। स्पीकर सर, हमारी सरकार के वक्त मे हम हरियाणा प्रदे ा को बिजली देते थे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार दिल्ली से चलती है इसलिए दिल्ली के लोगों को राजी करने के लिए बिजली दिल्ली भेजी जा रही है जबकि हरियाणा प्रदे ा मे बिजली न होने के कारण त्राहि त्राहि मची हुई है। (विध्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये फिर उसी प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या चौटाला साहब के पास बोलने के लिए मसाला खत्म हो गया है? (गोर एवं व्यवधान) अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है। अब ये यहां से जाएंगे। (गोर एवं व्यवधान) इन्होंने यहां से जाने का मन बना लिया है। अब ये सदन से भागने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला: *****

Mr Speaker: Nothing to be recorded. चौटाला साहब, मंत्री जी बोल रहे हैं आप उनको बोलने दें। (गोर एवं व्यवधान)
Nothing to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, 40 हजार करोड़ रुपये का निवेदन चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी के सरकार के वक्त में हरियाणा में आया है। नए उद्योग धंधे हरियाणा में आए हैं। एक लाख करोड़ रुपये के निवेदन उद्योग धंधों का मामला इस समय हरियाणा में पार्सप लाईन में है। (गोर एवं व्यवधान) इस सरकार के आने के बाद 28 प्रतिशत बिजली की खपत हरियाणा में बढ़ी है। Sir, on record I want to say on oath, let Sh. Om Parkash Chautala bring a breach of privilege against me. कि एक युनिट बिजली भी प्रांत किसी को नहीं दी गई है। उलटा चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा दूसरे प्रान्तों से बिजली हरियाणा

में लेकर आए है। If I am wrong, I challenge him to bring a breach of privilege against me. (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवे ान मे क्वै चन आवर मे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है कि हरियाणा प्रदे ा की बिजली उत्तरांचल में, हिमाचल में और महाराष्ट्र मे जा रही है। (गोर एवं व्यवधान) मै यह रिकाड की बात बता रहा हू। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह सरासर झूठ है। औम प्रका ा चौटाला जी ने यह आदत बना ली है ये हर बात को तोड मरोड कर पे ा करेंगं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रका ा चौटाला: आप यह हाउस की प्रोसिडिंग मे देख लें।

श्री अध्यक्ष: कौन सी प्रोसिडिंग में है?

श्री औम प्रका ा चौटाला: आप यह पिछले बजट सै ान की प्रोसिडिंग मू देख लें।

श्री अध्यक्ष: आप उसकी डेट बताएं।

श्री औम प्रका ा चौटाला: मै आपको डेट देखकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: चलो ठीक है, ये डेट देखकर बता देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनको कम से कम सदन में आकर सत्य बोलना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान) इनके वक्त में उद्योग धन्धे हरियाणा से पलायन करके चले गए थे। (विघ्न)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार के वक्त में उद्योग धन्धे पलायन कर गए थे। अध्यक्ष महोदय, इस समय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सदन में नहीं है लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आज आए तो वे व्हाईट पेपर जारी करें कि हमारे समय में हरियाणा में कौन कौन से उद्योग पलायन कर गए थे। (गोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): चौटाला जी, आपके समय में लिबर्टी पलायन कर गई थी। (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला: कोई इंडस्ट्री पलायन नहीं की है। (गोर एवं व्यवधान)

भाहरी विकास मंत्री (श्री ए सी चौधरी): चौटाला जी, मैं आपको बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से नाम लेकर बताता हूँ। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद हरियाणा में सबसे बड़ा औद्योगिक सैन्टर रहा है। चौटाला साहब का राज आने के बाद आम बच्चे के जुबान पर यह आ गया था कि चौटाला साहब आए और फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। उस वक्त

फरीदाबाद में न्यू इन्डस्ट्रीयल टाउन के नाम पर 200 के करीब उद्योग थे। लेकिन इनके वक्त में वहां चार या पांच उद्योग रह गए थे, बाकी सारे के सारे उद्योग वहां से इनके राज के वक्त में पलायन करके राजस्थान और नोएडा में चले गए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इन्डस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ इसलिए यह बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके राज में हमारा पूरा का पूरा भाहर उजड़ गया था। अध्यक्ष महोदय, आज ये बिजली के मामले में भी पूरे का पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली मंत्री भी रह रहा हूँ इन्होंने अपने समय में बिजली की खपत इस तरह से की जिस तरह से गाड़ियों में स्पीडो मीटर लगे होते हैं और उनमें स्पीड 0 से 180 दिखाई होती है। इन्होंने लगे लगाए प्लांट्स को जहां 100, 80-90 में आना चाहिए वहां उनको ये 140 और 160 पर ले गए। जो भी प्लांट एक बार बिगड़ा वह महीनों नहीं खड़ा हो सका। आज ये उद्योगों का नाम लेते हैं लेकिन जब उद्योग रहे ही नहीं तो नाम क्या लेंगे? अगर ऐसी बात नहीं है तो ये भी चुनौती दें और मैं भी चुनौती दे देता हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, इनकी वजह से ही करनाल में लिबर्टी वाला भाग गया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री नरे । कुमार: स्पीकर सर, इन्होंने बहादुरगढ़ में बिसकुट की पारले फैक्ट्री के सामने नींव खुदवाकर दीवार बनवा दी थी जिसके बाद वह भागकर राजस्थान चला गया था। उससे

इनके लउके और इनके एम एल ए उगाही मांगते थे। इससे दस करोड रुपये मांगे थे। इन्होने लिबर्टी फैक्ट्री भी करनाल मे बंद करवा दी थी। रेहडी वालो से इनके एम एल ए के गुण्डे थैले लेकर दस दस रुपये मांगते थे। इन्होने धारुहेडा मे भी एक फैक्ट्री बंद करवा दी थी।

श्री अध्यक्ष: ये जो भी बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री औम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, *****
(गोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा: स्पीकर सर, *****
(गोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन ने नाल लोकदल के कई सदस्य हाउस की वैल के नजदीक आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

श्री नरेन्द्र कुमार प्रधान: स्पीकर सर, ये गांव गांव मे जाकर कहते थे कि मुझे एक बार सत्ता की सीढी चढा दो तो मैं तुम्हारी चार पीढी का जुगाढ करवा दूंगा लेकिन इनकी बात कोई सुनने को तैयार नही था। ये तो अपने विधायको को जहाज के अंदर पीटते है जबकि आज ये इतराते है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो पाप इन्होंने किए हैं वह पाप तो अब खुलेंगे ही। (गोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: Please take your seat. (गोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठें, आप सबको बुलवाएंगे। चौटाला साहब, आज आपको बुलाया गया है। (Interruptions) Please take your seat. पण्डित जी, आप पर इल्जाम लगाया है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं आप बताएं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं।

श्री नरे । कुमार प्रधान: स्पीकर सर, दसवीं फेल।

श्री अध्यक्ष: अब चिडाना साहब, आप बताएं कि आप कितने पढ़े हैं और आपका लीडर कितना पढा है? आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप बताएं। (गोर एवं व्यवधान) ये सदन का सम्मानित साथी है (गोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded.

श्री बलवंत सिंह सढौरा: स्पीकर सर, *****
(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठें। दलाल साहब, औम प्रका । चौटाला जी एक घंटा चार मिनट बोले हैं। चौटाला साहब, अब आप वाईड अप करें (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० छतर पाल सिंह: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर सर, खेदड गांव जो कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में पउता है वहां पर डाक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर हमारे

मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने वहां पर 1200 मैगावाट के थर्मल पावर प्लांट की आधार ि ाला रखी थी। अभी औम प्रका ा चौटाला जी बिजली के उपर बहुत लम्बा भाषण कर रहे थे खुद वाहवाही लूटने के लिए और सरकार पर ब्लेम करने के लिए। यह तथ्यो पर आधारित है कि साढे पांच साल मे इन्होने हरियाणा के अंदर राज किया है जब कांग्रेस की सरकार 1991 से लेकर 1996 के बीच में थी जिसमे मै भी वजीर था और उस कांस्टीच्यूएंसी को रिपैजेंट करता था तो उस समय 1065 मैगावाट का थर्मल प्लाट खेदड मे लगना नि ि चत हुआ था, उसकी जमीन भी ऐक्वायर कर दी गयी थी और किसानो को उसका पैसा भी दे दिया गया था। स्पीकर सर 1996 तक ये फार्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी लेकिन उसके बाद साढे पांच साल तक ये श्रीमान जी मुख्यमंत्री रहकर चले गए लेकिन इनहोने उस पावर प्लांट के उपर एक ईंट भी रखने का कभी काम नहीं किया। स्पीकर सर, क्या उस कांस्टीच्यूएंसी का कसूर यह था कि वहां से माननीय चौधरी देवी लाल जी ने चुनाव लउकर ि ाकस्त ले ली थी। हरियाणा प्रदे ा के इंट्रस्ट को वाच करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। यही तो झीक है कि इन बातो को सोचकर हरियाणा प्रदे ा के विकास पर रोक लगा दी जाए। इस किस्म की नीयत से इन्होने भाषण देते हुए कहा कि हमने 10 हजार रुपये तक कर्ज माफ कर दिए। आपको याद होगा कि इन्होने सरकार ही इस आधार पर बनाई कि सभी लोगो का हम कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई वायदा नहीं किया। चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा ने बिजली के

बिलो की पैनेल्टी और ब्याज माफ किए। हमारी सरकार ने 1600 करोड रुपये के बिजली के बकाया बिल माफ किए और बिजली यदि पैदा की है तो कांग्रेस सरकार ने की है।

श्री औम प्रकाश चौटाला: इस सदन के हर सदस्य को बोलने का अवसर आप देंगे ही। अभी उद्योग धंधों के पलायन का जिक्र भायद सदन में चल रहा था।

श्री अध्यक्ष: आप ये 'भायद' वर्ड बहुत लगाते हैं। यह आपका तकिया कलाम लगता है।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अभी कहा जा रहा था कि हमारी सरकार के वक्त में बहुत ज्यादा उद्योग धंधों पलायन कर गये थे लेकिन हमारी सरकार के वक्त में किसी उद्योग धंधों ने पलायन नहीं किया बल्कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी तो इंडस्ट्रीयल ग्रुप लेकर विदेशों में गए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आपने 11 बजकर 14 मिनट पर बोलना शुरू किया था।

श्री औम प्रकाश चौटाला: मेरा टाइम तो आप खराब करते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको ऐडवाइज करता हूँ कि प्लीज, आप अपने दायरे में रहें। it is my duty to put the record straight. Mr Chautala, please carry on your speech and conclude it.

श्री औम प्रकाश चौटाला :आप हरेक को चाहे जिसको बीच में बोलने के लिए खड़ा कर देते हो।

श्री अध्यक्ष: आप भी प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने के लिए खड़े हो सकते हैं।

श्री औम प्रकाश चौटाला: इससे ज्यादा गलत बात क्या होगी कि मुख्यमंत्री के साथ जो उद्योग का डैलीगेशन गया था उसमें एक उद्योगपति के साथ एम और यू साइन किया गया जिसकी वजह से उनका उद्योग उत्तरांचल और हिमाचल के लिए था, न कि हरियाणा के लिए था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो ये अपने साथ प्राक्लेड औफैंसर्स को अपने साथ विदेशी दौरे पर ले जाया करते थे।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप कंक्लूड करें आपको बोलते हुए 1 घंटा 8 मिनट का समय हो गया है। आपको पांच मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री औम प्रकाश चौटाला: मेरा अधिकार है और मैं पूरा समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका अधिकार है। सरटेनली आपका अधिकार है लेकिन दूसरे सम्मानित सदस्यों के अधिकार छिनने का

आपका अधिकार नहीं है। (Interruptions) I am performing my duty.

श्री औम प्राक । चौटाला: यह अधिकार किसी को नहीं है कि वह प्वायंट आफ आर्डर के नाम पर भाषण झाडे ।

Mr Speaker: Mr Chautala, please carry on your speech. Please, no interruptions from any side.

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज यहां उद्योगो की बात हो रही है। इस सरकार के बनने के बाद मजदूरो पर लाठी चार्ज किया गया। किसी भी डैमोकटिक सिस्टम मे किसान धरने भी देते है, प्रद नि भी करते है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी औम प्रका । चौटाला के हाथ तो दर्जानो किसानो के खुन से सने हुए है। छाज तो बोले, छलनी भी बोले। हमारे जिले में कंडेला की धरती है जो कि गुप्ता जी की कांस्टीच्यूएंसी के गांव मे पडती है। आज भी कंडेला की धरती इनके द्वारा किए गए अत्याचारो की कहानी कहती है। आज भी हजारो हजारो गोलियां कण्डेला गांव की दीवारो पर लगी हुई है जो इनके अत्याचार की कहानी कह रही है। एक अहंकारी ऐसा मुख्यमंत्री जिसने घोडो की टापु के नीचे लोगो को रौंद दिया हो क्या वह आज बात करेंगे?

श्री औम प्रका । चौटाला: *****

Mr Speaker: Don't cast asperations on the chair.
इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री औम प्रका । चौटाला: *****

श्री अध्यक्ष: आप उल जलूल बात करते है इसलिए
आपकी बात रिकार्ड नही हो रही है। (विधन)

श्री औम प्रका । चौटाला: *****

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, ये तो आपकी सारी बातें
पहले ही जा चुकी है अब आप बैठ जाइयें। (विधन)

श्री औम प्रका । चौटाला: *****

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मै माननीय
सदस्य को बताना चाहता हूं कि एस ई जेड के नाम पर किसानो
की एक इंच भी नाजायज भूमि को एक्वायर नही किया गया। जब
ये हाउस को बरगलाने की कोि । । करेंगे तो स्पीकर सर, मुझे
यह बात कहनी पडेगी। यह इनका अधिकार क्षेत्र नही है। अध्यक्ष
महोदय, मै सरकार की तरफ से चुनौती देता हू कि आप इस बारे
मे हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। किसानो की एक भी इंच
भूमि का अधिग्रहण एस ई जेड के लिए नही हुआ। (गोर एवं
व्यवधान)

Mr Speaker: Chaudhary sahib, please address the
chair. Nothing to be recorded. (Interruptions)

श्री औम प्रका ा चौटाला: *****

श्री अध्यक्ष: इनकी बात रिकार्ड न की जाए। ये तो अनर्गल बाते करने के आदि हो गया है। (गोर एवं व्यवधान) सदन मे किसी पार्टी की कोई राजनीति नही चलेगी। राजनीति चलेगी तो चौक पे, बाजारो में और ग्राउंड मे यहा पर राजनीति नही चलेगी। No, No यहां केवल फ़ैक्ट्स की बात होगी। Nothing to be recorded. (Interruptions).

श्री नरे ा कुमार प्रधान: अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग कानून व्यवस्था की बात करते ळे उन लोगो ने कण्डेला मे 9 किसानो की हत्या करवा दी थी इसलिए इनके खून से हाथ रंगे हुए है। स्पीकर सर, दुलीना मे 4 हरिजन भाईयो को इन्होने जिंदा जला दिया था। महम मे इन लोगो ने अपनी एक साथी अमीर सिंह की हत्या करवा दी और उसकी ला ा को खेतो में फेंक दिया था जबकि आज ये सौहार्दपूर्ण की बात करते है, न्याय की बात करते है। (गोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: Mr Chautala, I allow you to speak. You may carry on your speech. no body will interrupt you. (Interruptions).

वाक आउट

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका नही दे रहे है, मुझे बार बार इन्ट्रूट किया जा रहा है और मुझे मेरी बात को स्पष्ट करने का मौका नही दिया

जा रहा है इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन ने नल लोकदल के सदन में सभी उपस्थित सदस्य एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, आपने औम प्रकाश चौटाला को पूरा मौका दिया और आपने तो उनको जाते जाते भी कह दिया कि आप बोले लेकिन सच्ची बात को यह है कि आप चाहे उन्हें एक धण्टे का समय दीजिए, डेढ़ धण्टे का समय दीजिए लेकिन उनके पास मसाला 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के बाद उनका मसाला खत्म हो जाता है और उसके बाद वे कोर्निल करते हैं कि किस तरह से चेयर को अस्पॉर्न कास्ट करे और किस तरह से दूसरे सम्मानित सदस्यों की तरफ अस्पॉर्न कास्ट करें यहां तक कि इन्होंने अपने ही साथी डा० सीता राम तक के लिए कह दिया कि ये क्या बोलेगा। वह जो मानसिकता है जिसमें विधायकों के हाथ तोड़े जाते थे, खुद पार्टी के विधायकों को जहाज में ले जाकर पीटा जाता था, खुद के विधायकों को तेजाखेडा फार्म पर ले जाकर बेइज्जत करके कमरों में बंद करके पीटा जाता था, इनकी ऐसी मानसिकता गई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि रस्सी जल गई, हरियाणा के लोगों ने जला दी लेकिन बल नहीं टूटा और वह बल भी हरियाणा के लोगों को एक बार फिर निकालना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ये खुद के ही मैम्बर को कहते

है कि ये क्या बोलेगा। सीताराम जी भी चुनकर आए हैं और इतने ही सम्मानित सदस्य हैं जितने की औम प्रकाश चौटाला जी। कप्तान साहब भी उतने ही सीनियर मैम्बर हैं जितना औम प्रकाश चौटाला जी हैं और उतना ही राजनीतिक तजुर्बा रखते हैं। कप्तान साहब 5 बार जीतकर आए हैं लेकिन ये तो मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गए थे। कैप्टन साहब कभी चुनाव नहीं हारे और लगातार 5 बार जीत कर आए हैं। औम प्रकाश चौटाला जी कैप्टन साहब की तरफ हाथ करके कहते हैं कि तू कोन है मुझे रोकने वाला। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकदल के साथियों के लिए कम से कम पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस समझाने के लिए अलग से क्लास लगाई जाए क्योंकि ये बाकी सदस्यों के साथ संसदीय व्यवहार करना नहीं सीख पाए।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप और मैं कई सालों तक विपक्ष में बैठे हैं। जब कभी औम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे हैं ये किसी मैम्बर को रिमेनिंग पीरियड के लिए हाउस से निकालते थे तो उसको कभी वापिस नहीं बुलाते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये आपकी फिराखदिली है कि आपने पार्टी मीटिंग करके इनको बुलाया और इनको बोलने के लिए पूरा समय दिया गया, उसके बाद भी इनको आखिर तक बोलने के लिए कहा। मैं इतने सालों तक विपक्ष में बैठता रहा हूँ लेकिन कभी बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता था लेकिन आप इनके मैम्बरज को पूरा समय

दे रहे हैं। आप इस बार बहुत लम्बा सै ान चला रहे हैं जबकि इनके समय में कभी 8-10 सीटिंग से ज्यादा सै ान नहीं चला। आप चाहे तो रिकार्ड दिखवा लें, आप इतनी फिराखदिली दिखा रहे हैं फिर भी ये सुधार नहीं सकते। जैसे कुत्ते की दुम हमें ा टेढी रहती है उसी प्रकार ये सुधारने वाले नहीं हैं और ये ऐसे ही रहेंगे।

सुखबीर सिंह जौनपुरिया: अध्यक्ष महोदय, एस इ जैड का मुख्यमंत्री औम प्रकाश चौटाला ने भारी विरोध किया। 1700 एकड़ जमीन ऐसी थी जिस पर औम प्रकाश चौटाला नु मुख्यमंत्री होते हुए 17 बी पॉलिसी लगा दी थी ताकि जमींदार अपील ही न कर सकें। उन्होंने उसका 5 या साढ़े पांच लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वही मुआवजा 24 लाख 90 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया है। ये कहते हैं कि उन्होंने झज्जर में रिलायंस को फ्री जमीन दी है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज तक एक बिसवा भी जमीन कहीं ऐसी नहीं है जो गुडगांव या झज्जर के एरिया में एक्वायर करके दी गई हो, ये जो तथ्य दे रहे हैं इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। झज्जर में जहां इनके समय में जमीन का रेट 4 या 5 लाख रुपये था वह आज 22 या 25 लाख रुपये प्रति एकड़ हो गया है इसलिए एस इ जैड का तो मुद्दा ही नहीं था।

भाहरी विकास मंत्री(श्री ए सी चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौटाला जी ने दो बार कहा कि उनके

समय मे कोई भी उद्योग पलायन करके नही गया। मै सदन के सामने रिकार्ड प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैटल बाक्स, आफ् इंडिया, फरीदाबाद मे बहुत बडी कंपनी थी जो कि बैस्ट पे मास्टर थी, इंडियन हार्ड वेयर इंडस्ट्री, हीतनानी इंडस्ट्री, भास्कर इंडस्ट्री, ईस्ट इंडिया कोटन कंपनी और आई एर कंपनी चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल मे हरियाणा से पलायन कर गई थी। इसके अतिरिक्त लखानी और बाटा की एक्सटैंशन यूनिट्स दूसरी जगहो पर चली गई। इसके अतिरिक्त जेडोर टूल्ज के चार यूनिट्स और प्रसटोलाईट कंपनीज बंद होकर इनके कार्यकाल मे अपनी जमीन बेचकर हरियाणा से चली गई। इससे बडा और कौन सा सबूत इनको चाहिए। ये सभी कंपनीज चौटाला जी जैसे भले मानस के कारण हरियाणा छोडकर चली गई।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुणे उस समय बोलने के लिए समय दे जिस समय औम प्रकाश चौटाला जी सदन में उपस्थित हो क्योंकि जिस समय श्रीमान जी बोल रहे थे उस समय मैने आपना पूरा सब्र रखा है।

श्री अध्यक्ष: इस बात की आप गारंटी देंगे कि वे आपकी बात सुनेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर चौटाला जी की गारंटी तो इनके बाप ने भी नही ली, मै कैसे ले सकता हूं।

श्री एस एस सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे जो पिलर है पहले उस पर लिखा हुआ था और अब पट्टी पर लिखा हुआ है। यदि चौटाला जी को सदन में बुलाना है तो वह पट्टी सदन से हटवा देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तो झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहा। वे झूठ में पूरे एक्सपर्ट हैं। उन्होंने झूठ बोलने की लैबोरेटरी लगा रखी है। चौटाला जी समझते हैं कि लोगों को झूठ बोलकर ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। एक बार झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना भी दिया था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत ही उपलब्धियों और जन कल्याणी योजनाओं से परिपूर्ण है। इसमें प्रदेश की नीतियों और विकास के साथ साथ सीमांत वर्गों का ध्यान रखा गया है जिसके लिए मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की नीति का मूल आधार कृषि और किसान है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य आई जी भोर सिंह चेर पर पदासीन हुए।) केन्द्र की सरकार ने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करके अपोजी उन के मुंह पर एक तरह से ताला लगा दिया है। सभापति

महोदय, कर्ज माफी की प्रतीक्षा पूरे देश के किसान कर रहे हैं। सभापति महोदय इसके साथ साथ इसमें मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सुझाव है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत बैंकवर्ड हरिजन कल्याण निगम के तहत जो नौजवान लोन लेते हैं और यूनिट न लगाने के कारण कर्जदार हो जाते हैं तथा लोन वापिस नहीं कर पाते, वे लोग भी आज बहुत परेशान हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन नौजवानों की तरफ भी ध्यान दें। भारत सरकार के फैसले से पहले ही हरियाणा सरकार ने बैंकों के लोन का ब्याज माफ करके बहुत बड़ी राहत किसानों को पहले ही प्रदान कर दी थी। लेकिन इसके लिए भी मैं सुझाव दूंगा कि इसके उपर भी मुख्यमंत्री जी ध्यान दें कि जो बेरोजगार नौजवान कर्ज में डूबे हुए हैं जिनकी युनिट उसमें नहीं आई और जो चिंतित हैं तो उनको भी हरियाणा सरकार इसमें कवर कर ले। सभापति महोदय, हमारा संगठन 'हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति' एक गैर राजनीतिक प्लेटफार्म पिछले 20 सालों से दक्षिणी हरियाणा में काम कर रहा है। सबसे पहले हमने एस ई जैड के मुद्दे पर आवाज भी उठाई थी और विधान सभा में भी हमने यह मुद्दा उठाया था। हमने यह मांग रखी थी कि किसान को उसकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाये। अगर किसान की खेती की जमीन जाती है तो उसका मालिकाना हक कम से कम किसान के पास रहे क्योंकि उसके पास यही एकमात्र दादालाई सम्पत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका गुजारा चलाती है। अगर जमीन किसानों की चली जाती है तो उसके पास और उसके बच्चों के पास कोई भी दूसरा रोजगार

का साधन नहीं रहेगा क्योंकि उसके पूरे परिवार का गुजारा उसी खेती के उपर ही चलता है। हमारी यह मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार ने यह काम किया जिससे हिंदुस्तान में यह पहली सरकार सबित हुई है जिसने किसानों द्वारा उठाई गई मांग पर जो हमने डिमाण्ड भी नहीं की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि अगर किसी किसान की एक एकड़ जमीन एस ई जैड में एच एस आई डी सी में या दूसरे उद्योगों के लिए ली जाएगी तो 33 साल तक 30 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष उसको मिलेंगे और इसमें 1000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती रहेगी। पिछले दिनों नीमराना में एक किसान सम्मेलन हुआ था उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वहां बुलाया था। इससे राजस्थान के लोग बड़े अचम्भे में थे कि हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया है जबकि वहां पर किसानों को केवल 2 लाख रुपये ही मिले कोई रोजगार भी नहीं मिला और लगभग 40-50 हजार एकड़ जमीन वहां बहरौड़, नीमराना और कोटपुतली आदि क्षेत्रों की ली गई। इसका अलावा 15 हजार एकड़ जमीन तो बिडला सीमेंट फ़ैक्ट्री में चली गई जबकि उससे पूरे एरिया में धुआं और धूल का बहुत ही बुरा माहौल हो गया है लेकिन वहां भी किसानों को कभी भी कुछ नहीं मिला। यह जो भुरुआत हुई है हरियाणा से, हरियाणा की इस विधान सभा से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो इस बारे में पूरे देश में एस ई जैड के बारे में चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी।

श्री फूल चन्द मुलाना: सीमापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सभापति महोदय, सदस्य बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं पर ये यह चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो साथी उठकर चले गये उन्होंने इस प्रदेश की पंचायतों की और सोसायटीज की कितनी जमीन हथियाई थी किसी ट्रस्ट के नाम पर उसकी चर्चा ये क्यों नहीं करते कि हरियाणा प्रदेश में श्री औम प्रकाश चौटाला के राज में हरिजनो का इतना दमन किया गया। आपको पता है हरसौला से हरिजनो के 200 परिवार बाहर निकाल दिये गए जिनहे इस सरकार ने बसाया हैं। दुलिना में 8 हरिजनो को मार दिया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, इनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि उनके दिल में हरिजनो के लिए कितना प्रेम है। उनके रराज में नौकरी के लिए जाने वाले रिटन टैस्ट में हरिजन टाप पर रहते थे लेकिन उनको इंटरव्यू में 0 से 3 तक नम्बर दिये जाते थे, उसका जिक्र भी इनको करना चाहिए। उनको तो एक मुद्दा चाहिए था बाहर जाकर मेरे प्रैस बंधुओं को बोलने तक कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता इसलिए वे उठकर चले गये हैं। उसकी भी इनको चर्चा करनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुलाना जी ने जो सुझाव दिए हैं वे बहुत ही सही सुझाव हैं और यह बात बिल्कुल सही है। आज हम देखते हैं कि भाराब के ठेके के माध्यम से कई हजार नौजवानों को लॉटरी के जरिए रोजगार मिल गया है

वर्ना चौटाला जी की सरकार जब 2005 में आई थी तो टेको की बोली के समय कह दिया जाता था कि 300 करोड़ की इकट्ठी बोली छोड़ी जाएगी। सीधे एक ही ग्रुप को 4-5 जिले इकट्ठे करके दे दिये गये और बोलीदाता वहां पर बैठे देखते ही रह गये और उपर से अजय भाई साहब का इतारा हो गया कि भाई साहब का मैसेज आ गया है। ऐसे ही गुडगांव में हुआ, बाहर के टैण्डर हुए, रेवाडी के अंदर भी बाहर का टैण्डर हुआ। यह जो हमारे यहां स्लेट पत्थर होता है उसका रेवाडी में टैण्डर था और बहुत से नौजवान जिनके खेत वहां पर लगते हैं वहां पहुंच गये। हम भी वहां पहुंच गये। बोली हो गई लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कुछ ताकतवर लोग वहां पर पहुंच गये। अजय चौटाला जी खुद प्रेजेंट थे नहीं बोली हो गई, बोलीदाताओं ने फैसला किया कि जो लोकल लोग हैं उनको भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए। बाद में वह बोली कैंसिल हो गई और फिर दोबारा चुपचाप बोली लगवाई गई। सभापति महोदय, ये सारी चीजे मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्योंकि कुछ नेटवर्क भी है। सेज के मामले में पश्चिम बंगाल में न जाने कितने किसान मारे गये लेकिन वहां की सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई। सेज पर कम्पनी इस बात पर अड़ी हुई है कि फैक्ट्री वही पर लगेगी। उत्तर प्रदेश में भी खुब आन्दोलन चले। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से नेताओं ने भी इसका विरोध किया, धरने पर भी बैठें। वी पी सिंह भी उत्तर प्रदेश में सेज के विरोध में धरने पर बैठे थे, राज बब्बर भी गये थे। खूब लड़ाईयां लड़ी लेकिन सरकार ने कोई फैसला

नहीं किया कि किसान की अगर जमीन ली जाएगी तो उस किसान के परिवार को बसाने के लिए क्या मिलेगा लेकिन हमारी सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला किया जिसका हमने स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया क्योंकि पूर्व की सरकार केवल लूट खसोट का कार्य करती थी, केवल अपने परिवार के लोगों के लिए जमीन अधिग्रहण करती थी। गुडगांव में जो भी जमीन खाली मिली उसको नोटिस भिजवाकर वे अपने कब्जे में ले लेते थे। आज जो भी उद्योग यहां लगे, जिन कंपनियों को यहां बुलाया गया, अल्टीमेटली यह फैसला हुआ कि सभी कंपनियां चाहे वह रिलायंस हो या दूसरी कंपनी हो, उनको किसान से मार्केट रेट पर सीधी जमीन खरीदनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री जी इस मामले में ईमानदार नहीं होते, उनकी सोच ठीक नहीं होती तो वे कंपनियों की ओर ही खड़े होते। लेकिन अंत में यही फैसला हुआ कि जो भी कंपनी हो किसान के पास जाये और उनसे भाव तय करें अगर सरकार जमीन दिलवायेगी तो 33 साल तक 30 हजार रुपये प्रति एकड़ किसान को देने पड़ेंगे और अगर एच एस आई डी सी यूनिट लगायेगी तो उसको भी देने पड़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने किया है, मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। 15 हजार रुपये सरकारी कार्य के लिए और जो सेज के लिए जमीन उपयोग होगी उसके लिए 30 हजार रुपये देने होंगे। इसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। 500 रुपये प्रति वर्ष सरकारी कार्य के लिए और एक हजार रुपये प्रति वर्ष सेज के लिए बढ़ोतरी होगी। जहां तक कृषि का सवाल है 24 जून, 2002 का वह दिन मुझे

आज भी याद है। चौधरी औम प्रकाश चौटाला उस समय पंजाब में फंका जा रहे थे। बादल जी, चौधरी देवी लाल जी की मूर्ति को अनावरण कर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी वहां पहुंचना था। हमने इस मौके पर तय किया कि नारनौल के अंदर एस वाई एल कैनाल के मुद्दे पर प्रदत्त निर्णय करना है। पंजाब में भी उस समय बादल की सरकार थी, हरियाणा में औम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका था कि तुरंत प्रभाव से एस वाई एल कैनाल का निर्माण करवाया जाये और यह कार्य सालों व महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में भूरा किया जाये। यह फैसला आने के बाद भी चौटाला जी को कोई चिंता नहीं हुई। इसके बाद हमने नारनौल में प्रदत्त निर्णय किया और पंजाब की गाड़ियों को रोकना भूरा कर दिया क्योंकि बादल साहब ने कह दिया था कि हम एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। हम जब प्रदत्त निर्णय करते हुए ज्ञापन देने के लिए जाने लगे तो चौटाला साहब ने पंजाब से ही उस समय के एस एस पी और डी सी को आर्डर किया कि इनको रास्ते में ही रोक दो। एक तरफ तो कंडेला कोंड हो रहा है और दूसरी ओर ये खड़े हो गये हैं तो पानी के उपर हमें कुछ बोलना पड़ेगा। बोलने के बजाय बादल का साथ देते हुए हमारे उपर लाठी चार्ज किये गये, 307 के मुकद्दमे बनाये गये। हमारे किसानों को जेलों में डाल दिया गया। जेलों के अंदर भी हम अनिश्चय पर बैठे रहे। किसी को मिलने तक नहीं दिया

गया। इस तरह के अत्याचार इनके भासन काल में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हुए।

श्री सभापति: क्या आपके साथी भी हुआ?

श्री नरे । यादव: हां सर, मैं खुद जेल में था। खुद मेरे उपर 307 का मुकदमा था। सभापति महोदय, पिछली बार जब विधान सभा का सेशन चल रहा था और उस समय ओलावृष्टि हो गई थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी खुद महेन्द्रगढ़ जिले में गए थे। पलवल और मेवाज 2-3 जगहों पर सेशन से जाकर उन्होंने अपना हेलीकाप्टर उतारा। उस समय हमारे माननीय चौटाला साहब मण्डलाना गांव में बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी महेन्द्रगढ़ जिले में उतर रहे थे। मुख्यमंत्री जी यहां से तय करके गए थे और वहां जाते ही उन्होंने पांच हजार प्रति एकड़ की दर से किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की थी। जबकि औसत प्रकार का चौटाला जी ने अपने भासनकाल में 2 रुपये, 5 रुपये और 11 रुपये का मुआवजा किसानों को दिया। सभापति महोदय, यहां तक कि सिरसा में जहां इनका अपना हलका है, 25 पैसे का मुआवजा देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया था। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से किसानों का ओलावृष्टि का मुआवजा दिया गया है उसी तर्ज पर पाले के कारण हुए नुकसान का मुआवजा भी किसानों को दिया जाना चाहिए। पाले के कारण वहां पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अटेली मण्डी आए थे तो उस समय भी हमने उनसे यह निवेदन किया था कि

पाले के कारण वास्तव मे किसानो का बहुत नुकसान हुआ है इसलिए किसानो को हुए नुकसान का कुछ न कुछ समाधान निकाल कर किसानो को कुछ राहत जरूर दें। जो किसान कर्जे मे डूबा हुआ था उसका कर्जा माफ करके उसको कुछ राहत दी गई है लेकिन पाले के कारण जो नुकसान हुआ है उससे किसान भाई दबा हुआ है। फसल बीमा योजना से भी किसानो को ज्यादा फायदा नही हुआ है। कैप्टन साहब ने कहा था कि पिछली बार फसल बीमा योजना के तहत किसानो को कुछ ज्यादा राहत नही मिली थी। इसको किसी भी तरीके से कवर कर के किसानो को उसका फायदा पहुंचाया जाए जिससे किसान दोबारा खडा हो सके। चेयरमैन सर, यहां पर पशुधन के बारे में भी मेरी मांग है कि काफी गांव ऐसे है जिनमे वेटरनरी डिस्पेंसरी की बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन वहां वेटरनिटी चिकित्सक नही है। गावों मे पशु अस्पताल बनाए जाने जरुरी है। पिछले तीन साल से हम मांग कर रहे है और हमने 4-5 गावों की लिस्ट भी दी हुई है। इन गावों मे पशु चिकित्सालय खुलवाना और डाक्टरज पहुंचाना जरुरी है इसलिए इस पर सरकार ध्यान दे। चेयरमैन सर, सिंचाई के बारे मे कैप्टन साहब हमको आश्वासन दे रहे है कि हमें पानी मिलेगा। एच वी एल कैनाल के लिए बी एम एल मे पंचर होगा और पानी आएगी। कैप्टन साहब अभी हमारे यहां पर जाकर आए है। नहरो की सफाई पर भी उन्होने खूब पैसा लगाया है इसमे कोई भाक नही है। पिछले सैकड़ों से इस सैकड़ों के दौरान लगभग सभी डिस्ट्रिब्यूट्रीज की सफाई का कार्य हुआ है। लेकिन

पानी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। इस बारे में मुझे विभाग के बारे में भी जानकारी है। जब हम चण्डीगढ़ में अधिकारियों से पूछते हैं कि हमारे एरिया के लिए कितना पानी चल रहा है तो यहां के आफिस वाले कहते हैं कि हम आपके एरिया के लिए 650 क्यूबिक फिट पानी चला रहे हैं लेकिन जब यह पानी महेन्द्रगढ़ कैनल में पहुंचता है तो यह बहुत ही थोड़ा रह जाता है। लास्ट बार्डर पर नांगल चौधरी है और वहां तक पहुंचते पहुंचते वह पानी 400 क्यूबिक फुट भी नहीं रहता। वहां पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सिंचाई की बात तो दूर पीने के पानी के भी हमें लाले पड़ जाते हैं। जो लोग इंजर वगैरा चलाते हैं तो उन पर तावान लगाते हैं। वहां के लोगों के लिए एक ही मुद्दा रह जाता है कि पानी मिले या नहीं मिल कम से कम जुर्माना माफ कर दिया जाए।

श्री सभापति: इस विषय पर प्रश्न काल में बात हो चुकी है इसलिए अब आप further carry on करें

श्री नरेन्द्र यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हांसी बुटाना लिंक नहर, एस वाई एल नहर के मुद्दे तो कोर्ट में चल रहे हैं। एस वाई एल पर जैसे पंजाब के हाउस में एक सहमति बनी है वैसी ही सहमति यहां पर भी हाउस में बननी चाहिए। अभी यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है लेकिन अगर यह मामला कोर्ट से निकल आता है तो हाउस में इस बारे में एक परिचर्चा करवा

लीजिए ताकि सब लोगो के विचार सामने आए और इसके लिए एक सहमति बन सके। हांसी बुटाना लिंक नहर के उपर भी हमने आज हाउस मे कार्यवाही देखी है। सभापति महोदय, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने औम प्रकाश चौटाला जी से पूछा था कि आप हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्ष मे है कि नहीं सभापति महोदय, उन्होने सदन का सवा घंटा खराब कर दिया लेकिन चौधरी जी ने इस बात का जवाब नही दिया कि वे इसके पक्ष में है कि नही है। इसका मतलब है कि वे हांसी बुटाना लिंक नहर को नही चाहते है। सभापति महोदय, हमने काफी लोगों को बताया कि हमारे हरियाणा के अंदर काफी लोग ऐसे बैठे है जो हरियाणा की तरक्की करना नही देखना चाहते है। सभापति महोदय, 1994-95 मे इसी हाउस की चार सदस्यो की कमेटी बनी थी उसमे औम प्रकाश चौटाला बेरी तथा तीन सदस्य और मैम्बर थे। उन्होने ही इस चोरी को पकडा था कि 1977 मे 18 लाख हैक्टेयर पानी केवल दो जिलो को जा रहा था। सभापति महोदय, मै हिसार कृशि वि विद्यालय मे पढा हुआ हूँ और वहां का वैज्ञानिक भी रहा हूँ। वहां पर अभी कृशी मंत्री जी एक मेले मे आए थे। वहां पर आज भी केवल एक ही मुद्दा है कि सेम की प्रोब्लम से निजात दिलाई जाए। हमारे सदन के साथी सीता राम जी भी यही बात कह रहे थे कि उनके यहां सेम की समस्या का समाधान किया जाए।

श्री सभापति: यादव जी, उस समस्या का समाधान होने जा रहा है।

श्री नरे । यादव: सभापति महोदय, वहां पर हजारों एकड़ जमीन पानी की बहुतायत की वजह से खराब हो गई है। वाटर लैवल बहुत ही उपर जा चुका है। लेकिन वे लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी सरकार के वक्त में उनकी सोच इतनी बेकार रही कि वहां पर वाटर लैवल बहुत उपर आने की वजह से वहां पर दलदल बन गया है। जबकि दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी जिले के गोदबलावा, मलथल, गढानिया के 4-5 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर 1400 फूट पर पानी नहीं मिलता है। इसी तरह से राधे भयाम भार्मा जी के हल्के के दोस्तपुर गांव में भी 1400 फूट तक पानी नहीं मिलता है। सभापति जी, जो इस प्रकार की सोच के लाग यहां बैठे हुए हैं जब वे सत्ता में होते हैं तो केवल एक जिले की ही बात करते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं हम हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। जब सत्ता में होते हैं तो चाहे विविद्यालय हो, चाहे युनिवर्सिटी हो, नहर का पानी हो या रोजगार की बात हो सब कुछ एक ही सजिले में दे दिया जाता है। आज इस सरकार ने एक अच्छी कोर्नर की है, एक अच्छी भुर्रात की है। इस सरकार की नियत है कि हरियाणा में पानी का समान बंटवारा हो। यह एक बहुत ही अहम फैसला है और यह फैसला लेना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था। सभापति महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी की

पार्टी से लोकसभा का चुनाव लडा था। मै आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1994 मे भजन लाल जी की सरकार के वक्त मे एक मर्तबा नारनौल मे किसानो पर लाठियां चलवाई गई थी और वहां पर हमारे नौजवान साथी को पुलिस की गोली लगने से मौत भी हो गई थी तथा सैंकडो किसान घायल हो गए थे। उस वक्त भजन लाल जी ने किसानो पर मुकदमे बनवाए थे। उस वक्त सरकार ने पानी मांगने वालो पर ताना ाही की थी। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई, हमने उनसे कहा था कि दक्षिणी हरियाणा मे पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यू ान का रौला चल रहा है इसलिए आप इसकी घोशणा हरियाणा मे कर दें। हमने उनसे कहा था कि अभी मुद्दा गर्म है, आप इस बारे मे घोशणा कर दें। चौधरी बंसी लाल जी कहने लगे कि भई नही, यह बहुत मु किल काम है, मेरे से दो बडे जिले नाराज हो जाएंगे। सभापति महोदय, इस सरकार मे मुख्यमंत्री जी ने जो समान पानी के बंटवारे के बारे में निर्णय लिया है उसके लिए मै मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हू। सभापति महोदय, हमारी हाउस मे कामो को लेकर काफी नोंक झोक होती रहती है लेकिन हमने समान पानी के बंटवारे और एस इ जैड के मामले को लेकर अटेली मे मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया था और कहा था कि आपने यह बहुत ही स्ट्रांग कदम उठाया है। सभापति महोदय, चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी हरियाणा मे पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होने बहुत ही स्ट्रांग स्टैप लेकर यह निर्णय लिया है। कैप्टन साहब, मै आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि कई स्टेटस मे बहुत ही दूर

दूर से पाईप लाईन बिछाकर पानी दिया जा रहा है। कैप्टन साहब ये जो हमारा महेन्द्रगढ जिला है, रिवाडी जिला है इनके पलथल और गढानिया मे भी पानी नही है इसलिए वहां पर आप पाईप लाईन बिछा कर पानी पहुंचाने का कश्ट करें नहर बेस्ड स्कीम के तहत जो आपने वाटर टैंक बनाए है और उन पर 200-200 लाख रुपये खर्च कर दिए है, लेकिन फिर भी पानी नही पहुंच रहा है। कैप्टन साहब मेरा सुझाव है कि जो मेन महेन्द्रगढ कैनाल लहरोदा के पास है जहां पर हमे पाानी रहता है वहां से पाईप लाईन बिछाकर उन जगहो पर पानी दिया जाए। सर अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है और वहां पर पानी की बहुत भारी किल्लत होने वाली है इसलिए इससे पहले कि वहां पर पानी की किल्लत आए आप उसका ईलाज कर दें। यह बात ठीक है कि वहां पर पीने का पानी टैंकरो से दिया जा रहा है इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं पिछली बार विधान सभा के सैशन मे ही तय हो गया था कि जिस गांव मे वाटर लैवल नीचे चल रहा है वहां पर जन स्वास्थ्य विभाग टैंकर से पानी **13:00 बजे** पिलाएगा। पूरे हरियाणा और खासतौर से अटेली और नारनौल के एरिया मे यह काम आज भी यथावत जारी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि गावों मे मेन नहर से एक पाईप लाइन के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाए या ऐसा कोई चैनल बनाया जाए, ऐसी कोई स्कीम बनायी जाए जिससे लोगों को पीने के पानी की दिक्कत न हो।

श्री सभापति: नरे । जी, अब आप वाईड अप करें आपने बोलने के लिए 25 मिनट मांगे थे और अब आपके 25 मिनट हो चुके हैं।

श्री नरे । यादव: चेयरमैन सर, जहां तक पावर की बात है यह बात ठीक है कि बिजली की किल्लत रही है हम भी जब गांव गांव में जाते थे तो हमें पता चलता था कि बिजली की प्रोब्लम थी क्योंकि बिजली की खपत बढ़ गयी थी। लेकिन पिछले बीस पच्चीस दिनों से यह महसूस किया जा रहा है कि बिजली में काफी सुधार हुआ है खासतौर से स्टूडेंट्स की पढाई के समय जो पहले बिजली की दिक्कत थी, वह पिछले महीने से सुधार गयी है। कैप्टन साहब के सामने ही मैंने विधार्थियों की एक मीटिंग में उनसे पूछा था तो उन्होंने स्वीकार किया कि अब पढने के टाइम में बिजली मिल रही है। चेयरमैन सर, सरकार अब पावर प्लांट्स लगा रही है लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ हालांकि यह क्वै चन आवॉर नहीं है कि आप जो पावर प्लांट झाडली में या दूसरी जगहों में बनाएंगे तो उनके लिए आपको पानी की जरूरत भी होगी। क्या आपने इसके लिए कोई पानी का अरेंजमेंट किया है? अभी तक तो दौ सौ या तीन सौ क्यूसिक ही पानी हमें मिल रहा है और असल में वहां तक 50 क्यूसिक पानी ही पहुंच रहा है तो रास्ते में झाडली में हमारा वह पानी रुक तो नहीं जाएगा? आपने कोई ऐसी व्यवस्था की होगी कि जब इन प्लांट्स में पानी की जरूरत पड़ेगी तो जो सुचारु रूप से पहले से

व्यवस्था चल रही है वह रुक न पाए। चेयरमैन सर, जहां तक मेरे हलके की छोटी छोटी मांगों की बात है।

श्री सभापति: नरे जी, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। आपकी जो मांगें हैं उनको लिखकर दे देना।

श्री नरे जी यादव: चेयरमैन सर, आपने औम प्रकाश चौटाला जी को तो एक घंटे का समय बोलने के लिए दे दिया जबकि वे तो हाउस का समय खराब कर रहे थे। मैं तो काम की बात बता रहा हूँ, स्टेट के हित की बात बता रहा हूँ फिर भी आप मुझे बोलने का टाईम नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की जो सड़कें हैं उनमें से मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें आपके आर्थिक विवाद से अभी बननी भुरु नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत चार सड़कों का काम तीस करोड़ रुपये की लागत से आलरेडी भुरु करवा दिया गया है। मैंने क्वेश्चन आउर में भी कहा था कि जो हमारी सड़कों के टुकड़े राजस्थान बोर्ड तक जुड़े हुए हैं वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हमारी इस तरह की पांच सात सड़कें हैं जिनके बारे में मैंने मंत्री महोदय को पहले भी लिखकर दिया है और अब जब चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं तो मैं फिर से इनके बारे में लिखकर मंत्री जी को दे दूंगा। राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं हो सकता है कि ये भी राजस्थान में चुनावों में अपना भाषण देने के लिए जाएं। अगर मंत्री महोदय हमारी ये सड़कें बनवा देंगे तो हो सकता है कि दूसरा फायदा इनको भी मिल जाए क्योंकि हमारी दस पन्द्रह सड़कें

राजस्थान बोर्डर से जुड हुई है। मुख्यमंत्री जी अभी नीमराणा गए थे।

श्री सभापति: यादव जी, आप इनके बारे में मंत्री जी को लिखकर दे देना उनकी तरफ से कार्यवाही हो जाएगी।

श्री नरे । यादव: जी हां, मैं लिखकर दे दूंगा। चेरमैन साहब, नीमराणा से खातीखेडी रोड है, नीमराणा से अटेली रोड है इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैं यह भी मांग करता हूँ कि वहाँ के उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर करवा दें क्योंकि एिया लैवल पर नीमराणा आज काफी डिवैल्प हो गया है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से पर्यटन विभाग की बात है। पर्यटन मंत्री जी इस समय बैठी नहीं है। हमारे यहाँ नारनौल अटेली रोड पर राजस्थान बोर्डर तक कोई भी पर्यटक स्थल नहीं है और न ही वहाँ पर कोई झील है। अब झील की बात करेंगे तो फिर पानी की बात आ जाएगी। मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जो एक प्राचीन जल महल है इसको सरकार पर्यटक स्थल बना सकती है।

श्री सभापति: यादव जी, हारवैस्टिंग बगैरा बन जाएगा। आपने इस बारे में पढा भी होगा।

श्री नरे । यादव: चेरमैन सर, पीने का पानी मिलेगा तभी तो उसको भी भरवाएंगे। इसके अलावा सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज भी बहाल की है। चौटाला साहब ने तो कनीना

म्यूनिसिपल कमेटी की मांग करने वालों को जेल में डाल दिया था क्योंकि वे लोग इसका चुनाव न चाहकर अनअपोज जिताना चाहते थे। म्यूनिसिपल कमेटी तो बहाना हो गई है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक एक पैसा भी उनको नहीं मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके लिए भी कुछ राशि दे ताकि विकास के काम हो सके।

श्री सभापति: नेर । जी , आप वार्ड आप करें पैसा आपको मिल जाएगा। कंसीडर हो रहा है।

श्री नरे । यादव: सर, मैं अपने एरिया में वाटर लैवल जो नीचे जा रहा है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। वाटर रिचार्जिंग हमारे एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पानी का लैवल किस तरह से उपरन लाया जाए, इसके लिए जरूर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम एल ए डी टी के तहत भी पैसा नहीं मिला है।

श्री सभापति: नेर । जी, आपको एक मिनट का और समय दिया जाता है। उसके बाद आप बैठ जाएं क्योंकि फिर बहन प्रसन्नी देवी बोलेंगी।

श्री नरे । यादव: ठीक है सर, सभापति महोदय, नरेगा स्कीम में जोहड खोदने का कार्य चलता है। इसके बारे में मेरा सुझाव था कि इसमें पैसा वेस्ट जा रहा है। हम एम एल एम एज

जो लिस्ट बनाकर देते है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। उसकी व्यवस्था बनाई जाए। इस मामले मे संबंधित एम एल ए को साथ रखा जाए ताकि विकास के काम कराए जा सके। जिला महेन्द्रगढ मे हमारे यहां कोई युनिवर्सिटी नही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके यहां युनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब कह दिया गया है कि रिवाडी गुडगांव मे बनाएंगे। हम चाहते है कि सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बाछौद मे 200 एकड जमीन भी है इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कनीना मे सरकारी कालेज डिक्लेयर किया जाए।

श्री सभापति: अब आप बैठ जाए।

श्री नरे । यादव: सभापति महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री सभापति: एक एक मिनट कहकर आप दस मिनट ले चुके है। अब आप बैठिए।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौथला): सभापति महोदय, आपने जो मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हू। प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता मे केन्द्र सरकार ने जो 60 हजार करोड रुपये किसान के कर्ज के माफ किर दिये वह एक बहुत ही ऐतिहासिक सराहनीय और अनूठा कदम है। इसके साथी ही साथ एक प्रार्थना मैं यह भी करना चाहती हूं

कि जो आदमी खेती से जुड़े हुए है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है और उनके छोटे मोटे कर्ज भी है। ऐसे आदमियों के लिए जैसे भी सरकार ठीक समझे और उनको जितना भी रिलीफ दे सके, उनको कुछ न कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे किसी ने कर्ज लेकर भैंस ली हुई है या छोटी मोटी आटा पीसने की चक्की लगाई हुई है।

श्री सभापति: हरियाणा सरकार ने राहतें भी दी हैं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि जितना भी रिलीफ सरकार दे सके, देना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के भासन काल में हरियाणा की सरकार ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बहुत से विकास के कार्य किए हैं। उनको यदि गिनती में गिनाया जाए तो सुबह से भाम हो जाएगी लेकिन गिनाया नहीं जा सकता। लोग बाद में समझते हैं कि उनसे पहले ही ऐनाउंसमेंट भी हो जाती है और काम भी हो जाते हैं। अपोजी एन की सरकार 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिल छोड़ गई थी। पीने के पानी की व्यवस्था तो बनाई गई थी लेकिन पीने का पानी लाया नहीं गया था। सरकार ने हरिजनो को जो टंकीया और टूटीयां लगा कर दी हैं यह भी एक सराहनीय कदम है। गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट भी दिये हैं। जिस आदमी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाट बिछाने की जगह नहीं है। उस गरीब आदमी को सरकार ने 100 गज के प्लॉट फ्री दिए, यह बहुत अच्छी बात है। हाउस टैक्स के लिए लोगों ने

बडा भारी बोझ इकटठा कर लिया था, सरकार ने पहले तो उसका सरचार्ज माफ किया उसके बाद हाउस टैक्स को भी माफ कर दिया। उसके बाद चुल्हा टैक्स माफ होने से भी लोगों को काफी राहत मिली है। गेहूं का भाव बढ़ने के कारण हमारी सरकार ने जो गरीब आदमियों को राशन का 35 किलो अनाज देना शुरू किया हुआ है इसको 50 किलो किया जाये ताकि गरीब आदमी को इससे ज्यादा लाभ हो। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल जो पहले 5 लीटर राशन का मिलता था उसको अब 3 लीटर कर दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उसको फिर से 5 लीटर कर दिया जाये। वैसे तो हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। खानपुर कलां में एक महिला विधवा विद्यालय खोला है, सर्विसिज में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण दिया हुआ है। बिजली कनेक्शन अगर महिला के नाम पर है तो उसमें भी बिल में कुछ रिलीफ दिया गया है। इसके साथ ही सभापति महोदय मैं एक प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार को करना चाहती हूँ कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक महिला कालेज जरूर खोलना चाहिए जिससे हमारी बच्चीया आराम से पढाई कर सकें क्योंकि सभी जिलों में महिलाओं के लिए अलग से कालेज नहीं है। सरकार के लिए यह कोई मुश्किल चीज नहीं है। वैसे तो सरकार ने प्रत्येक जिले में काफी काम किए हैं लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है। अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में कहना

चाहूंगी। दो साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव मे गये थे मेरा गांव सींक जो पानीपत जिले के आखिरी मे जींद जिले के साथ लगता हुआ पडता है। वहां पर बिजली की बडी भारी समस्या रही है। उस समय वहां पर लोगों ने एक 33 के वी का सब-स्टे इन लगाने की मांग की थी और पंचायत ने इसके लिए जमीन देने का रैजोल्यू इन भी पास करके भेज दिया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करा दे। इसी तरह से उलाना गांव का सब-स्टे इन जो 33 के वी का था उसको बड़ाकर 66 के वी का कर दिया जाए। सर, अब मैं अपने हल्के की सडको के बारे मे बात करना चाहूंगी। पुठर से बांध तक की सडका का दो कीलोमीटर का टुकडा है अगर इस सडक को बना दिया जाए तो मण्डी जाने का रास्ता छोटा हो जायेगा। पालडी से इसराना की दो तीन किलोमीटर की सडक ईंटो की बनी हुई है इसको आगे मिलाने की जरूरत है। इसी प्रकार से उलाना कलां से कैनाल पुलिस पोस्ट की सडक जो कुराना गांव के पास मिलती है और जो कई डेरो के अंदर की सडक है इसको भी बनाया जाये क्योंकि बरसात के दिना `मे यहां पर जाने का कोई रास्ता नही मिलता यह चार पांच किलोमीटर का सडक का टुकडा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सडक को टाप प्रायोरिटी से बनाया जाए क्यांकि उन लोगों के लिए आने जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नही है। इसके अलावा िवाह गांव के साथ साथ मार्केट कमेटी ने सडक बनाई हुई है। इसके बारे मे एक साल से कह भी रहे है और इस बारे मे लिख कर भी

दिया है लेकिन इसको बनाया नहीं गया है, सरकार की अगर मेहरबानी हो जाये तो इस सड़क के बनने से यह थर्मल प्लांट के पास जो बाई पास बन रहा है, वहां पर यह मिलेगी इससे वहां के लोगों को काफी लाभ होगा। मेरी प्रार्थना है कि इन सड़को को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाया जाए। इसी तरह से जीतगढ से नौहरा गांव की सड़क है, इस सड़क को बनाने की बहुत पुरानी मांग है। उसक बन जाने से मतलौडडा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और रास्ता छोटा हो जाएगा। छोटै रास्ते के कारण लोगों को आने जाने की सहूलियत हो जाएगी। सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिन सड़को का मैंने जिक्र किया है इन सारी सड़को की तरफ ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, मैं अब शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, सरकार ने वैसे तो पिछले 3 सालो मे काफी स्कूल बनाए है और हमारे यहां भी काफी स्कूल बनाए है। पिछले काफी अर्से से कोई स्कूल नहीं बना था। गांव कुटानी, सिमला, पुठाल, बड गाम, काबडी और चंदौली गांव ऐसे गांव है जिनकी आबादी 10, 15 या 20 हजार के आसपास है। और वहां प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल है तो 10+2 का स्कूल करने की जरूरत है ताकि इन गावों के बच्चो को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी तरह लडकियो के स्कूलो की बहुत कमी है। गांव मांडी मे लडकियो के लिए प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल बनना है जिसके लिए लोगों ने बिल्डिंग खडी कर रखी है इसके अलावा मैंने जिन गावो के नाम लिए है इन सबमे बिल्डिंग बनी हुई है। गांव सीख मे लडकियो के लिए मिडल स्कूल से हाई स्कूल,

उरलाना मे हाई स्कूल से 10+2 का स्कूल, इसराना हाई स्कूल को 10+2 का स्कूल और नौलथा के हाई स्कूल को 10+2 का स्कूल बनवाया जाए क्योंकि यह बहुत जरूरी है जिनके बगैर काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि स्कूलों का दर्जा बढ़ाने से हमारी लड़कियां जो बाहर या दूर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती उनको गांव के अंदर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नौलथा गांव में P.H.C है उसको C.H.C बनाने के लिए 2 साल से ज्यादा समय से लोगों की कोशिश है और लोगों ने इसके लिए रैजोल्यूशन भी दे रखा है। जमीन और सरकार की जो दूसरी कंडीशन है उनको पूरा करने के लिए लोग तैयार हैं क्योंकि सारे एरिया में आसपास कोई और C.H.C नहीं है इस बारे में मुझे पता नहीं लग पाया कि यह केस किस स्टेज पर है और C.H.C क्यों नहीं बन पा रही है? इसी तरह एक और C.H.C है वहां डाक्टरों की कमी है। हमें पता नहीं चल रहा कि क्या कारण है कि इस C.H.C में डाक्टरों की कमी पूरी क्यों नहीं हो रही? सभापति महोदय मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोग सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकें। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री को किसी काम के लिए बहुत कहने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि लोग किसी बात को मुख्यमंत्री से कहने के लिए सोचते हैं उससे पहले मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस काम के लिए अनाउंसमेंट हो जाती है। जिस तेजी के साथ हमारी स्टेट तरक्की कर रही है, ऐसी बहुत कम स्टेट्स मिलेंगी। मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करके देखा है

जितनी लगन से हमारे मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों की तरफ ध्यान दे रहे हैं उतना कभी किसी अन्य मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। गांव की, देहात की सारी समस्याओं का उन्हें पता है। जिस तरीके से हरियाणा में काम चल रहे हैं यह एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि विधान सभा भवन का बहुत अच्छा रैनोवे इन किया गया है इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय, का धन्यवाद करना चाहते हैं लेकिन एम एल एज होस्टल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा के एम एल ए होस्टल को पंजाब के एम एल ए होस्टल की तरह बल्कि उससे भी अच्छा बनाया जाना चाहिए।

श्री सभापति: सै इन के बाद एम एल ए होस्टल का काम भी हो रहा है। अब आप वाइंड अप करें

श्रीमती प्रसन्नी देवी: सभापति महोदय, इन भाबदों के साथ मैं अपने आप को भारदा राठौर द्वारा सदन में रखे गए प्रस्ताव के साथ भामिल करती हूँ।

श्री कुलबीर सिंह बेनीवाल: सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज प्रदेश के अंदर बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदरणीय मुख्यमंत्री भुपेन्द्र सिंह हुडडा ने बिजली के बारे में जैसे कदम उठाए हैं वैसे आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं उठाये। हरियाणा के

अंदर 10-10 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वालो ने कभी बिजली की समस्या का हल नहीं किया। औम प्रकाश चौटाला जी लोगो को कहते थे कि एक बार मुझे सत्ता दे दो मैं 24-24 घंटे मुफ्त बिजली दूंगा लेकिन उनहेने बिजली उत्पादन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा ने बिजली उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चयमुनानगर मे स्थापित की जा रही 300 मैगावाट की दो ईकाईयो मे से पहली इकाई को नवम्बर, 2007 मे चालू कर दिया था तथा दूसरी इकाई इस वर्ष मार्च मे सिंक्रोनाईज होनी वाली है। इसके अतिरिक्त हिसार के खेदड गांव मे 1200 मैगावाट का कोयला आधारित राजीव गांधी थर्मल प्लांट का कार्य भुरु हो चुका है जो वर्ष 2009-10 तक चालू हो जायेगा। इसी तरह से झज्जर में 1500 मैगावाट क्षमता का पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो 2010 तक चालू हो जायेगा। इसी तरह से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के तहत 242 करोड रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश मे हर जाति को मान सम्मान दिया है सरपचो को मान सम्मान दिया है और चौकीदारो को भी मान सम्मान दिया है, लोगो के हाउस टैक्स और चूल्हा टैकस हमारी सरकार ने माफ किए है। इसके अतिरिक्त गरीब परिवारो को 100-100 गज के

प्लाट दिए है जो कि बहुत ही सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस हल्के से आता हूँ वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ढाणियो मे रहते है। एक ढाणी में बिजली पहुंचाने के लिए एक एक लाख रुपये लग जाता है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे वहाँ हर ढाणी मे लाईट पहुंचाई है इसके लिए अपने हलके के लोगों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। आज वे भू गये कि उनकी सरकार के समय मे कानून व्यवस्था की धज्जियां उडा दी गई थी। उस समय उनके रि तेदारो और चहेतो को भाराक के ठेके दिए जाते थें। चौटाला जी के राज मे खानो पर गुण्डा टैक्स लगा दिया गया था। सोनीपत की खाने उन्होने अपने रि तेदारो और चहेतो को दी दी थी। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी अपने विधायको के हाथ तोड दिया करते थे। लेकिन आज वे कानून व्यवस्था की बात करते है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने विपक्ष के साथियो को बोलने के लिए समय दिया लेकिन उनके पास बोलने के लिए कोई मुददा नही है। वे केवल टाईम पास के लिए ही बोलते है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृशि का सवाल है, कृशि की तरफ भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है जिसके कारण वर्ष 2006—2007 के दौरान प्रदेश मे खाद्यान्न उत्पादन 147 लाख टन से भी अधिक हुआ है। यह उत्पादन आज तक का सबसे बडा उत्पादन है। गत फरवरी और मार्च, 2007 के दौरान ओले गिरने से हुए नुक्सान की भरपाई करने के लिए प्रभावित किसानो को

हमारी सरकार ने 208 करोड रुपये का मुआवजा दिया है जबकि चौटाला जी की सरकार के समय में किसानों को 25 पैसे, 75 पैसे और एक एक रुपये मुआवजा के तौर पर किसान के साथ भद्दा मजाक किया गया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला सोनीपत के गन्नौर भाहर में लगभग 500 एकड़ क्षेत्र पर एक वि व स्तर की टर्मिनल मार्केट बनाने जा रही है। यह मण्डी भारत में फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मण्डी होगी। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने गेहूं के भाव 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है जबकि पिछली सरकार के समय में 20-20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाता था। ये उस समय अपने आपको किसानों का नेता कहते थे। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी की सरकार के समय में एक नारा था 'चौटाला तेरे राज में, जरी गई ब्याज में' और आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में यह नारा दिया जाता है कि 'हुड्डा तेरे राज में, जरी गई जहाज में'। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में हमारी सरकार एस वार्ड एल नहर के माध्यम से नदियों के जल में हरियाणा का हिस्सा लेने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती है। उपलब्ध नहरी पानी के सदुपयोग और समान वितरण करने के लिए सिंचाई के क्षेत्र में नई पहल की गई है। हरियाणा के अतिरिक्त पानी का सदुपयोग करने के लिए 30 करोड रुपये की लागत से पिचमी यमुना नहर की कैपेसिटी 13500 क्यूसिक से बढ़ाकर 20 हजार क्यूसिक की जा रही है। दादुपुर-नलवी नहर का निर्माण किया जा रहा है और पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाने

का कार्य भी युद्धस्तर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी पश्चिमी क्षेत्र की पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा के सभी गावों और भाहरो के लिए पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पेयजल की कमी वाले 500 गावों में जलापूर्ति बढ़ा दी गई है तथा वर्ष 2008-09 में ऐसे ही 368 और गावों की जलापूर्ति में बढ़ोतरी की जायेगी। नवम्बर, 2006 में भुरु की गई 'इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम' के तहत ग्रामीण एवं भाहरी क्षेत्रों में 8 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त में 200 लीटर की पानी की टंकी और कनेक्शन दिया गया। इस योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 4 से 4.50 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की 2-3 समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। भट्टू मण्डी में वाटर वर्क्स की हालत बहुत चिंताजनक है इसलिए उसकी रिपेयर किया जाना बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो पानी के टैंक हैं वे बहुत ही जर्जर हालत में हैं। इसके अलावा मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में तमाम वाटर वर्क्स की रिपेयर अपेक्षित है। इसके अलावा भट्टू मण्डी में सीवरेज की व्यवस्था भी दोबारा से करवाये जाने का मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समूचित विकास को सतत प्राथमिकता देती है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी कार्यान्वित की जा

रही है जो कि पहले हरियाणा प्रदेश के दो जिलों सिरसा और महेंद्रगढ़ में ही थी लेकिन आगामी वित्त वर्ष के दौरान इसको प्रदेश के दो सभी जिलों में लागू किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को आवास स्थान आबंटित करना भी हमारी सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। 1 नवम्बर, 2007 को हरियाणा दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गृह कर को समाप्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो मेरी अन्तरात्मा बार बार कहने को कह रही है कि हमारी सरकार की कोशिशों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कोशिशों से हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के ऋण माफ किए हैं। इससे जनजन को फायदा होगा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है अगर हमारा किसान कर्ज मुक्त होकगा तो वह खुशहाल होगा और अगर किसान खुशहाल हो जाएगा तो जो मजदूर व व्यापारी वर्ग है उसको भी उसकी खुशहाली का फायदा होगा। इस कार्य के लिए विधान सभा के सभी सदस्यों को भारत सरकार और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए कि ऐसा जनहितकारी फैसला लिया गया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया था। इस बार लोक सभा के बजट सत्र में पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम दो बार लिया गया। इसके साथ ही स्पीकर साहब आपने मुझे राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

प्र० छतर पाल सिंह: स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने हरियाणा सरकार द्वारा जो पॉपुलर कार्य इन पिछले तीन साल के अंदर किये गये हैं उनका ऐतिहासिकत वर्णन अपने अभिभाषण के अंदर किया है। मैं उनके इस अभिभाषण के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूँ। स्पीकर सर, यहां पर विपक्ष के साथियों का जो आचरण है।

Mr Speaker: Now, the House stands adjourned till 9:30 tomorrow, the 13th March, 2008.

1330 Hrs

(The Sabha then adjourned till 9:30 A.M on Thursday, the 13th March, 2008.)